R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth
पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 13
01 से 15 अप्रैल 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

₹

मध्य प्रदेश विधानसभा
बजट-सत्र 2025

मप्र का बजट सत्र छोटा... काम पूरा

अपनों के निशाने पर रही सरकार

मध्यप्रदेश में 17 साल बाद बना पूरे समय सदन चलने का रिकॉर्ड

9 दिन के सत्र में विधायकों ने सरकार से पूछे 2849 सवाल

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA$_{1c}$, HbA$_2$ and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA$_{1c}$ or HbA$_2$/F/A$_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

लालफीताशाही

8 | बगैर जुगाड़ के पर्यावरण...

मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं और कार्यक्रम बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अफसर हैं कि सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। अफसर सरकार के विकासवादी कदम को किस तरह रोक रहे हैं...

डायरी

10-11 | प्रभार से मुक्त होंगे...

मप्र में आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में...

विवाद

15 | पदोन्नति का 36:64...

मप्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक अब हटने की संभावना है। यदि इस पर अमल किया जाता है, तो हजारों कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। पदोन्नति के लिए सरकार ने तीन विकल्प बनाए हैं। पहला कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता...

समस्या

19 | गांवों में गहराया जलसंकट

भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बिसनखेड़ी गांव में जलसंकट गहराने लगा है। ग्रामीणों को पानी के लिए दो किलोमीटर दूर एक गड्ढा खोदना पड़ा है। वे उस गड्ढे के मटमैले पानी को कपड़े से छानकर प्लास्टिक के ड्रमों में भरते हैं और बैलगाड़ी के जरिए घरों तक ले जाते हैं।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र यानि बजट सत्र में भले ही 9 बैठकें हुईं, लेकिन इस दौरान जिस तरह सदन की कार्यवाही बिना हंगामे और बिना गतिरोध के चली, उससे एक बार फिर से मप्र की गरिमा लौटी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के संचालन के लिए जो नवाचार गढ़े हैं, उसका ही असर है कि 17 साल बाद मप्र विधानसभा का सदन चलने का रिकॉर्ड बना है।

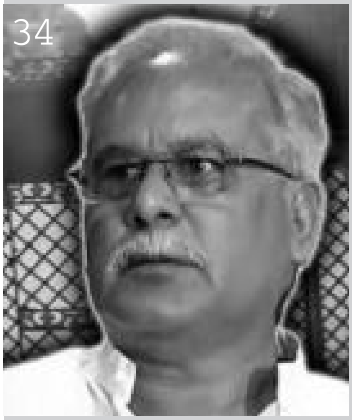

राजनीति

30-31 | परिसीमन पर आर-पार

लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गत दिनों तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 58 दल के नेता शामिल हुए। बैठक की...

महाराष्ट्र

35 | औरंगजेब पर सियासी...

महाराष्ट्र सहित पूरे देश में इस समय औरंगजेब पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई जारी है। 24 मार्च को नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी...

उत्तरप्रदेश

37 | मिशन 2027 पर फोकस...

उप्र में विधानसभा चुनाव भले ही दो साल बाद हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-13, पृष्ठ-48
1 से 15 अप्रैल, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

डॉ. मोहन को लुभाया भोपाल ने...

शायर कैफ़ भोपाली का एक शेर है...

दाग़ दुनिया ने दिए ज़ख़्म ज़माने से मिले
हमको तोहफ़े ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले

उपरोक्त पंक्तियों भोपाल और भोपालियों के मिजाज को दर्शाती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि मप्र की राजधानी होने के बावजूद भोपाल के विकास और विस्तार पर किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर भोपाल को पेरिस बनाने का दावा करते रहे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी तरह भोपाल के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंच हो या कोई शासकीय बैठक, मुख्यमंत्री यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं कि मेरा पसंदीदा शहर भोपाल है। शायद यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित की गई, जिससे भोपाल को नई ग्लोबल पहचान भी मिली है। अगर डॉ. मोहन के अब तक के कार्यकाल का आंकलन करें तो हम यह पाते हैं कि उनका पूरा फोकस भोपाल के विकास पर रहा है। भोपाल का व्यवस्थित विकास हो इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भोपाल में महापुरुषों का इतिहास बताने के लिए द्वार बनाने की घोषणा की है। यानि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि एक बार जो भोपाल आए वह इसकी सुंदरता, सरलता, शालीनता और व्यवस्थित विकास का कायल हो जाए। मुख्यमंत्री की मंशानुसार भोपाल में शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। राज्य सरकार ने झीलों के शहर को पांच शहरों के साथ जोड़कर विकास की नई कल्पना की है। आगामी 25 साल में भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से स्वच्छता पेयजल, सीवर और रोड जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखकर योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि हम भोपाल को एक सुंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे। भोपाल शहर में सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों में नगर द्वार बनाए जाएंगे। भोजपुर मंदिर रोड पर भोज द्वार और इंदौर-उज्जैन मार्ग पर विक्रमादित्य के सुशासन के प्रतीक स्वरूप विक्रम द्वार बनाए जाएंगे। दरअसल, भोपाल आकर सभी को आनंद आता है, क्योंकि यहां की झीलें, तालाब और यहां की संस्कृति जीवंत हैं, यही हमारी पूंजी है। भोपाल देश का एकमात्र राजधानी क्षेत्र है जहां मानव और बाघों के सह-अस्तित्व का अनोखा और अद्वितीय उदाहरण विद्यमान है। भोपाल शहर के समीप ही रातापानी अभयारण्य है। यहां दुर्लभ बाज मिलने की भी पुष्टि हुई है। यह हमारी राजधानी को और भी आकर्षक बनाते हैं। भोपाल की इन विशेषताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लुभाया है। यही वजह है कि भोपाल शहर का सतत सौंदर्यीकरण हो रहा है। भोपाल की विरासतों को चिरस्थायी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि भोपाल भारत की सबसे स्वच्छ और हरितिमा से भरी राजधानी है। यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की निरंतर कोशिश बनी हुई है कि भोपाल का इस तरह विस्तार और विकास किया जाए कि यहां औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले, जिससे क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ें और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सके। मुख्यमंत्री ने भोपाल के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए अभी तक जो भी प्रयास किए हैं, उसके लिए राजधानीवासी तो उन्हें साधुवाद देते ही हैं, साथ ही पड़ोसी जिले भी मुख्यमंत्री की पहल की भरपूर सराहना कर रहे हैं। भोपाल में अभी विकास की भरपूर जरूरत है और भविष्य की आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की विकसित सुविधाओं का किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य करेगी।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

सख्ती दिखाए सरकार

मप्र में पुलिसकर्मियों पर हमले की बढ़ती घटनाएं एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अपराधियों का दुस्साहस बढ़ रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था लचीली सी पड़ गई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

● **जगदीश नामदेव,** रायसेन (म.प्र.)

रोजगार के नए आयाम

मप्र में रोजगार की दिशा में सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। जहां सरकार प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर स्वरोजगार को भी संबल दे रही है। इससे बेरोजगारी कम हो रही है।

● **अखिल सूर्यवंशी,** बैतूल (म.प्र.)

नियमों की उड़ रहीं धज्जियां

वाहनों पर हूटर लगाकर रौब झाड़ने की खबरें आए दिन सुनाई देती हैं। मप्र में तमाम नेता और अधिकारी अपने निजी वाहनों पर भी हूटर लगाकर घूम रहे हैं। जबकि हूटर लगाने के भी कुछ नियम हैं। सरकार को इस विषय में कड़ी कार्रवाई करते हुए नए नियम बनाने चाहिए।

● **कविता सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

विकसित भारत में मप्र की भूमिका अहम

मप्र देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है। प्रदेश कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन क्षेत्रों में और अधिक विकास के लिए केंद्र सरकार से मजबूत वित्तीय सहयोग–अनुदान की आवश्यकता है। विकसित भारत का निर्माण विकसित मप्र के बिना नहीं हो सकता, इसलिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जो अपील की है, वह सराहनीय है। इससे राज्य मजबूत होंगे और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने में सहायक होंगे। राज्य अपनी क्षमता और सीमित संसाधनों से ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं। केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय अनुदान मिलने से राज्य अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को अल्पकाल में ही प्राप्त कर सकेंगे।

● **नीलम पांडे,** इंदौर (म.प्र.)

वैश्विक ताकत के रूप में उभरेगा भारत

बीते एक दशक में भारत ने केवल आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि कूटनीति और वैश्विक राजनीति में भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां, तकनीक के क्षेत्र में प्रगति, कूटनीतिक कौशल और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत को एक नई दिशा दी है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल एक उभरती हुई शक्ति रहेगा, बल्कि एक स्थापित वैश्विक ताकत के रूप में अपनी स्थिति और सुदृढ़ करेगा। आगामी वर्षों में मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि नई नीतियों से देश को विकसित किया जाएगा।

● **अभिषेक मिश्रा,** ग्वालियर (म.प्र.)

खनिज संसाधनों में मप्र आगे

मप्र खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। प्रदेश खनिजों की प्रचुरता और सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मप्र का खनिज संसाधन विभाग खनिज ब्लॉक नीलामी में देश में अग्रणी रहा है। खनन क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

● **मोहित कटारिया,** कटनी (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बंगाल भाजपा में बगावत की बू

पश्चिम बंगाल में भाजपा अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहती है लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहां पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा के 77 विधायक जीते थे लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 65 रह गई है वहीं चर्चा है कि आठ और विधायक पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। यही नहीं भाजपा विधायक तापसी मंडल के तृणमूल में जाने से उसे बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के दो विधायक जो पहले से सांसद थे, इस्तीफा देकर वापस संसद चले गए हैं। इसके बाद धीरे-धीरे आठ और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। एक विधायक का निधन हो गया जबकि एक और विधायक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। इन सभी सीटों पर हुए उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा जिससे पार्टी की सीटें 65 तक सिमट गईं। इस बीच हल्दिया की भाजपा विधायक तापसी मंडल ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह भाजपा के लिए दोहरे झटके जैसा है क्योंकि तापसी के पार्टी छोड़ने से विधानसभा में भाजपा की ताकत घटी और दूसरी ओर वे शुभेंदु अधिकारी के गढ़ की विधायक थीं। तृणमूल इसे शुभेंदु के प्रभाव क्षेत्र में बड़ी सेंध बता रही है।

योगी कैबिनेट में विस्तार के आसार

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सूबे की सियासत में कानाफूसी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कई मंत्रियों की मंत्री परिषद से छुट्टी हो सकती है। वहीं जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को उप्र विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। उप्र चुनाव 2027 को लेकर पार्टी इसके जरिए अपनी रणनीति को अमलीजामा पहना सकती है। इसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान होगा। ऐसे में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में वापस लाया जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि योगी मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। योगी सरकार के महत्वपूर्ण पद संभाल रहे मंत्री जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव में जीते थे। इसके बाद उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ऐसे में उनको मिले विभाग अभी भी प्रभार के सहारे चल रहे हैं। इनके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों में कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की।

एनडीए का सहारा बनेंगे सहनी ?

बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी करीब सात-आठ महीनों का समय शेष है लेकिन सूबे की सियासत में अभी से दल बदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। बीते दिनों विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की दो दिवसीय राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा संगठन धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। आने वाला चुनाव हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं और आपसे भी, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमें नए सिरे से संघर्ष करने के लिए विचार करना होगा और हमें लक्ष्य भी प्राप्त करना होगा। सही अर्थों में हमारी पार्टी की नीति और प्राथमिकता गरीबों के कल्याण की रही है। आज राजनीति में काफी बदलाव आया है हमें भी अन्य दलों से मुकाबला करने के लिए वैसे ही बदलाव लाना होगा। सहनी के इस वक्तव्य के बाद से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहनी एक बार फिर एनडीए का सहारा बनेंगे या महागठबंधन में बंधे रहेंगे।

नसीहत पर ध्यान दें राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल को बोलने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एक हफ्ते से उनको बोलने से रोका जा रहा है। लेकिन यह विवाद बढ़ा जब स्पीकर ने एक नसीहत देते हुए राहुल को सदन की उच्च परंपराओं का पालन करने को कहा। हालांकि तब कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ प्रेस दीर्घा में बैठे पत्रकार भी अनुमान ही लगा रहे थे कि क्यों स्पीकर ने नसीहत दी है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल के सदन में बैठने या टीशर्ट पहनने को लेकर स्पीकर ने नसीहत दी है। लेकिन असल में वह नसीहत राहुल को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपने लगाव का सार्वजनिक इजहार करने को लेकर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस सदन की उच्च परंपरा रही है, जिसका सबको पालन करना चाहिए। उन्होंने खासतौर से राहुल गांधी को इंगित करके कहा कि नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वे सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे।

येदियुरप्पा ने दिखाई ताकत

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इन दिनों सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनको लेकर निगेटिव खबरें ही ज्यादा आईं। उनसे जुड़े कई मामलों की जांच को लेकर खबरें आती रहती हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया है कि कर्नाटक भाजपा की जहां तक बात है तो बॉस वे ही हैं। उनका और उनके बेटे कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का विरोध करने वाले वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है। भाजपा ने अनुशासन की कार्यवाही करते हुए अपने वरिष्ठ नेता बासनगौड़ा पाटिल यतनाल को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। अभी सिर्फ एक ही नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई है लेकिन इसके जरिए उनका साथ देने वाले सभी नेताओं को संदेश दे दिया गया है। असल में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से ही कर्नाटक भाजपा के कई नेताओं ने येदियुरप्पा और उनके बेटे के खिलाफ मोर्चा खोला है। बसनगौड़ पाटिल यतनाल इस विरोध का चेहरा हैं।

मंत्री का साथ... फिर क्या बात?

जनता से डायरेक्ट जुड़े जितने विभाग हैं, उनमें सबसे अधिक घपले-घोटाले होते रहते हैं। घपले-घोटाले करने वालों का संरक्षक विभागीय मंत्री और अधिकारी होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल प्रदेश के निकायों की जिम्मेदारी वाले विभाग का है। दरअसल, इस विभाग में इंजीनियरों के जो मुखिया हैं, उनकी कमीशनखोरी से अन्य अधिकारी-कर्मचारी परेशान हैं। सूत्रों का कहना है कि बड़े इंजीनियर साहब हर काम में कम से कम 10 प्रतिशत कमीशन तो ले ही रहे हैं। इसके लिए वे बकायदा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का सहारा ले रहे हैं। बड़े इंजीनियर साहब की ऐसी शिकायतें ऊपर तक पहुंच रही हैं। कई इंजीनियरों ने शिकायत की है कि साहब हर महीने उनसे मोटी रकम की मांग करते हैं। जिस विभाग की बात हो रही है, प्रदेश में वह विभाग सबसे अधिक फर्जीवाड़े के लिए जाना जाता है। सूत्रों का कहना है कि जिन बड़े इंजीनियर साहब पर आरोप लगा है, उन्हें मंत्रीजी ने ही बड़ी कुर्सी दिलवाई है। अब ये साहब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर प्रदेशभर से वसूली कर रहे हैं। कभी विभाग के अपर मुख्य सचिव तो कभी कमिश्नर का नाम लेकर प्रदेशभर से वसूली कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसकी खबर सरकार तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी, या मंत्रीजी का वरदहस्त काम आएगा।

ऊपरी कमाई के लिए ओएसडी में होड़

सरकार सुशासन के लिए बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन उसकी नाक के नीचे ही मंत्रियों के संरक्षण में पल रहे अफसर ऊपरी कमाई के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्री के दो ओएसडी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों में ऊपरी कमाई की ऐसी होड़ मची हुई है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। मंत्रीजी के एक ओएसडी रिटायर अधिकारी हैं तो दूसरी अभी सेवा में हैं। जो ओएसडी सेवा में हैं, उन्हें कृषि का अच्छा खासा अनुभव है। कृषि के इतर इनका एक अनुभव भी इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वह है उन्हें पता चल जाता है कि किस अधिकारी का ट्रांसफर हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि उक्त ओएसडी आव देखते हैं न ताव, ट्रांसफर होने वाले अधिकारी के पास पहुंचकर पैसे की मांग करने लगते हैं। इस तरह वे जमकर कमाई कर रहे हैं। वहीं दूसरे ओएसडी, जो रिटायर होने के बाद भी मंत्रीजी को सेवा दे रहे हैं, वे खाद-बीज में खेला कर रहे हैं। इस तरह दोनों ओएसडी में कमाई की होड़ लगी हुई है। बता दें कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से आने वाले एक मंत्रीजी के यहां ये दोनों ओएसडी पदस्थ हैं।

साहब की मांग से परेशान

प्रशासनिक वीथिका में एक अपर मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली और उनकी मांग से विभाग परेशान है। दरअसल, जिस अधिकारी की यहां बात हो रही है, वे कानून व्यवस्था वाले विभाग में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी संभाल रहे हैं। विडंबना यह है कि इस विभाग में कोई सचिव नहीं है, इसलिए अपर मुख्य सचिव से काम चलाया जा रहा है। उधर, विभाग में पदस्थ होने के बाद से ही अपर मुख्य सचिव ने अपनी मांग से वरिष्ठ अफसरों को परेशानी में डाल रखा है। सूत्र बताते हैं कि गत दिनों साहब ने अपने कक्ष में फोटोकॉपी मशीन के लिए नोटशीट तैयार करवाई और उसे खुद लेकर पुलिस विभाग के मुखिया के पास पहुंच गए। जबकि वे भेज भी देते तो काम हो जाता। साहब के इस कदम से अन्य अधिकारी अचंभित रह गए। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार भी साहब इस विभाग में पदस्थ थे, उस समय अपने लिए कम्प्यूटर की मांग कर बैठे थे। वहां भी उन्होंने कम्प्यूटर के लिए नोटशीट तैयार करवाकर भेजी थी। बताया जाता है कि साहब हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। यहां बता दें कि राजधानी में जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उस समय ये एसडीएम थे और एक महिला एसडीओपी से भिड़ गए थे। दरअसल, एसडीओपी किसानों के साथ इनके पास गई थीं, ताकि किसान इन्हें ज्ञापन सौंप सके। बताया जाता है कि साहब के इस रुख को देखकर किसानों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वे जैसे-तैसे वहां से बच निकले।

पोस्टिंग को लेकर ठनी

प्रदेश के एक बड़े विभाग में एक पोस्टिंग को लेकर मंत्री और आयुक्त में ठन गई है। दरअसल, प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री के विभाग में विगत दिनों आयुक्त के माध्यम से एक विधि सलाहकार को नियुक्त किया गया था। अपनी मनमानी के लिए ख्यात मंत्रीजी को जब इसकी खबर लगी तो उन्हें यह नागवार गुजरा और उन्होंने एक नोटशीट के आधार पर राजभवन सचिवालय की जनजातीय सेल में हुई आदिवासी विधि सलाहकार की नियुक्ति मात्र सात दिनों में रद्द कर दी गई। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि नियुक्त विधि सलाहकार मंत्री के विरोधी परिवार से संबंध रखती हैं। दरअसल, मौजूदा विधि सलाहकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इसी कारण राजभवन के प्रस्ताव पर 21 मार्च को आयुक्त ने नई सलाहकार की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। यह नियुक्ति 8 अप्रैल से प्रभावी होने वाली थी। लेकिन, जैसे ही मंत्री को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने उच्च स्तर पर एक नोटशीट भेजी, जिसमें उन्होंने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई। अब इस नियुक्ति मामले में मंत्री और आयुक्त के बीच ठन गई है।

आईजी-एसपी में रार

विंध्य क्षेत्र के एक जिले में इन दिनों अजीबो-गरीब स्थिति देखने को मिल रही है। स्थिति यह है कि यहां आईजी और एसपी के बीच अघोषित रार चल रही है। इस रार की वजह काली कमाई बताई जा रही है। सबसे हास्यास्पद और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों उच्च अधिकारियों में छिड़ी रार में एक एएसआई दोनों को अपने इशारे पर घुमा रहा है। विंध्य के अन्य जिलों की तरह यह जिला भी कोयले जैसे खनिज के लिए ख्यात है। यानि यहां कोयले का अवैध कारोबार जोरों पर है। सूत्रों का कहना है कि इस काले कारोबार से होने वाली कमाई के लिए आईजी और एसपी में होड़ मची हुई है। दोनों की कोशिश है कि उन्हें अधिक राशि मिले। इससे दोनों के बीच शीतयुद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है। ऐसे में एक एएसआई दोनों अफसरों के बीच की कड़ी बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि उक्त एएसआई दोनों अफसरों के लिए पैसा वसूल रहा है। मामला कबाड़ का हो या कोयले की कालाबाजारी का, यह एएसआई पूरी वसूली करता है और फिर दोनों अफसरों को अपने हिसाब से हिस्सेदारी देता है।

बगैर जुगाड़ के पर्यावरण अनुमति नहीं

मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं और कार्यक्रम बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अफसर हैं कि सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। अफसर सरकार के विकासवादी कदम को किस तरह रोक रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण माइनिंग की अनुमति के मामले में सामने आया है। सालों से जमे अफसर इस तरह का खेल कर रहे हैं कि माइनिंग की अनुमति मिलने के बाद भी लिपिकीय त्रुटि में खदानों को उलझा रहे हैं। प्रदेश में करीब 17 खदानों की पर्यावरण अनुमति लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं मिल पाई है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। साथ ही अफसरों ने अपनी करतूतों से यह सिद्ध कर दिया है कि बगैर जुगाड़ के पर्यावरण अनुमति मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस बात का खुलासा सिया अध्यक्ष की समीक्षा में हुआ है।

अंगद का पांव बने अफसरों के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो वे सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे माइनिंग कारोबारी परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाले कारोबारियों की कोई सुन नहीं रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योगपतियों के लिए लाल कारपेट बिछा रही है। उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें सभी अनुमतियां सिंगल विंडो पर मिलेगी। एक क्लिक पर सभी अनुमतियां उनके पास होगी। सरकार इसके लिए ईमानदारी से काम भी कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश का माइनिंग विभाग ऐसा है, जहां उद्योगपतियों को अनुमतियों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इस विभाग में सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी उद्योगपतियों को न सिर्फ परेशान किया जाता है, बल्कि उनकी अनुमतियां भी जारी नहीं की जा रही हैं। ऐसे एक-दो नहीं कई प्रकरण हैं, जिन्हें सिर्फ विभाग में लिपिकीय त्रुटि के नाम पर दो-दो साल तक रोका गया। इसका खुलासा भी सिया के अध्यक्ष के द्वारा की गई लंबित प्रकरणों की समीक्षा में हुआ। खास बात यह है कि बेवजह प्रकरणों को रोकने वाले अफसरों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि माइनिंग विभाग में सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है।

दरअसल, सरकार ने माइनिंग के लिए काफी सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे में कागजी खानापूर्ति करने के लिए पहले मशक्कत करनी पड़ती है। किसी ने अगर इसे पूरा भी कर लिया तो गारंटी नहीं होती है कि उसे अनुमति तत्काल मिल जाएगी। विभाग में सालों से जमे अफसर इसे मुश्किल बना देते हैं। वे इन अनुमतियों को लिपिकीय त्रुटि का नाम देकर लंबित प्रकरणों में डाल देते हैं। विभाग के वरिष्ठ अफसर भी इस तरफ देखना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में यह अनुमतियां लंबे समय तक अटकी रहती हैं। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि रोजगार के रास्ते भी नहीं खुल पाते हैं।

जानकारी के अनुसार, माइनिंग विभाग में यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इसका खुलासा सिया के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान के द्वारा की गई समीक्षा में हुआ। चौहान ने ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा की जिन्हें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है। इसमें एक प्रकरण 10752 वर्ष 2023 संदीप राय बिछिया डिंडोरी का था। जिसकी समीक्षा में सामने आया कि इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। कार्यालय द्वारा भ्रमित करने वाली टीप प्रस्तुत की गई है कि इसमें लिपिकीय त्रुटि है। अध्यक्ष ने भविष्य में प्रकरण का पूर्ण अवलोक एवं परीक्षण करने के बाद ही टीप अंकित करने के निर्देश दिए। साथ ही सिया की 5 जून 2024 को हुई बैठक में इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लाने के लिए संबंधित प्रोजेक्ट फैलों एवं प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस मामले में सर्वसम्मत निर्णय नहीं होने के कारण मिनट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजने का निर्णय लिया गया।

वहीं एक प्रकरण में तो अनुमति मिलने के बाद भी काम नहीं कर सके। जानकारी के अनुसार, मेसर्स स्टोन वर्क्स माइनिंग विवेक दुबे ने डोलोमाईट खदान के लिए बड़वारा कटनी में 2.80 हेक्टेयर के लिए आवेदन किया था। इस प्रकरण में सिया ने अनुमति जारी कर दी थी, लेकिन बाद में इसे लिपिकीय त्रुटि बताते हुए रोक दिया गया। इससे खदान में कार्य ही चालू नहीं हो सका। समीक्षा के दौरान सामने आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर बी-1 श्रेणी के लिए ही आवेदन किया गया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के साथ कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र भी बी-1 श्रेणी में आता है। सेक ने भी इसे इसी श्रेणी में रखा है। प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सिया द्वारा प्रकरण में 10 जून 2024 में अधिरोपित मानक शर्तों के स्थान पर परिशिष्ट-2 सुधारा जाए। साथ ही बी-1 श्रेणी की कलस्टर मैनेजमेंट की 3 अन्य शर्तों को भी जोड़ते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाए।

● कुमार राजेंद्र

सालों से जमे हैं अफसर

खदानों को अनुमति देने के लिए दो कमेटी बनी हैं। इसमें एक सेक है और दूसरी सिया। सेक में अलोक नायक सालों से बैठे हुए हैं। इनसे मिलने के बाद ही अनुमति जारी होती है। वहीं सिया में अच्युतानंद मिश्रा बैठे हैं। ये नायक के बहनोई हैं। यह वही काम करते हैं, जो नायक भेजते हैं। दोनों ही अफसर लंबे समय से जमे हुए हैं, लेकिन न तो इन पर कभी कार्रवाई होती है और न ही इन्हें हटाने के प्रयास ही कभी हुए। जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है।

जनता के और करीब आई राज्य सरकार

मप्र सरकार अब जनता के और करीब आ गई है। जनता सरकार से जुड़ी खबरों, कैबिनेट के फैसलों, आर्टिकल और फोटो सहित कई जानकारियों को एक क्लिक में हासिल कर सकेगी। दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 मार्च को जनसंपर्क विभाग का मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप से प्रदेशवासियों को सरकार की नीतियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों की त्वरित व सटीक जानकारी सीधे मोबाइल पर ही प्राप्त हो सकेगी। मोबाइल ऐप पर समाचार, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, मंत्री परिषद के निर्णय, आलेख, विभिन्न विभागों की वेबसाइट के लिंक, जिलों के समाचार तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों, कमिश्नर और कलेक्टर की सूची आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक जनसंपर्क अंशुल गुप्ता तथा सोशल मीडिया विशेषज्ञ उपस्थित थे। आयुक्त जनसंपर्क डॉ. खाड़े ने बताया कि ऐप पर स्क्रीन रीडर की भी सुविधा दी गई है, जिससे यूजर आसानी से समाचार सुन सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐप में वॉइस सर्च की सुविधा दी गई है, जिससे यूजर आसानी से आवश्यकता अनुसार कंटेंट सर्च कर सकते हैं। ऐप पर वॉट्सऐप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करने की लिंक भी दी गई है, इससे सुगमता से कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया जा सकेगा। मोबाइल ऐप पर पुश नोटिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है, इसके माध्यम से समाचार को सभी यूजर्स तक पुश किया जा सकता है।

इस ऐप के जरिये सरकार जनता के बीच और आसानी से संवाद कर सकेगी। सरकार लोगों को एक पल में यह बता सकेगी कि राज्य के विकास के लिए उसकी प्लानिंग क्या है। यह ऐप एंड्रॉयड बेस्ड है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जनसंपर्क एमपी लिखना होगा। गौरतलब है कि यह ऐप अपने आप में बेहद खास है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री-मंत्रीगणों से जुड़े समाचार सिंगल क्लिक पर हासिल किए जा सकेंगे। इस ऐप पर समाचार, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, मंत्री परिषद के निर्णय, आलेख, मंत्रिमंडल की सूची, कमिश्नर-कलेक्टर की सूची, मप्र के शासकीय विभाग, उनकी वेबसाइट की लिंक और जिलों के समाचार आसानी से मिलेंगे। बता दें, जनसंपर्क के इस ऐप पर स्क्रीन रीडर की भी सुविधा दी गई है। इससे यूजर आसानी से समाचार सुन सकेंगे। ऐप में वॉइस सर्च की सुविधा दी गई है। इससे यूजर आसानी से आवश्यकता अनुसार कंटेंट सर्च कर सकते हैं।

वहीं 27 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन-विज्ञान उत्सव और चालीसवें मप्र युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में समत्व भवन से वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनेक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक और एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक प्रत्येक क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत एक दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विजनरी नीति का ही परिणाम है कि भारत डिफेंस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन रहा है। मप्र शासन द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरूआत के लिए भी मंथन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जीआईएस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

● नवीन रघुवंशी

उज्जैन है काल गणना का केंद्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति भी विज्ञान आधारित है। हम अनेक शुभ कार्य नवग्रह पूजन से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 2082 आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के काल से लेकर अब तक उज्जैन के इतिहास, कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ ही विज्ञान के केंद्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी उज्जैन को काल गणना के केंद्र के रूप में जानते हैं। इस संबंध में भी निरंतर अनुसंधान हो रहा है। हम नूतन का स्वागत करते हुए पुरातन परंपराओं को भी साथ रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक साथ प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा पर आधारित विभिन्न सत्रों का आयोजन सराहनीय है, जिसमें लगभग 300 शोधार्थी और युवा वैज्ञानिक 17 विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार आज की आवश्यकता है। हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आईटी विभाग के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण नीतियां मप्र ड्रोन संवर्धन और उद्योग नीति-2025, मप्र एनीमेशन, विजुअल एफैक्टस, गैमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) नीति-2025, मप्र सेमी कंडक्टर नीति-2025 और मप्र वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2025 घोषित की गई हैं। वैज्ञानिक सम्मेलन में स्पेस पॉलिसी बनाने का सुझाव आया है। इस नाते मप्र की स्पेस पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए बधाई दी।

प्रभार से मुक्त होंगे एसीएस और पीएस

मप्र में आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में सबसे पहले अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से प्रभार वाले विभाग लिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। गौरतलब है कि 12 बड़े विभागों का प्रभार एसीएस और पीएस के पास है।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार प्रदेश में होने वाली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में करीब 32 आईएएस को सरकार नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, तो प्रभार में टिके मंत्रालय के कई विभागों को स्वतंत्र अफसर भी मिलेंगे। सरकार ने इस फेरबदल में बीते एक साल के दौरान एसीएस, पीएस, सचिव, संभागायुक्त व कलेक्टरों के कामों को आधार बनाने की योजना रखी है। इसमें ऐसे अफसर जिनके काम के नतीजे अच्छे रहे हैं और सरकार को केंद्र स्तर पर, 16वें वित्त आयोग की प्रजेंटेशन बैठक में व अन्य स्तरों पर सराहना मिली, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं किरकिरी कराने वालों की कुर्सी खिसकना तय है।

शिकायत वाले अधिकारी भी हटेंगे

जानकारों का कहना है कि इस बार के तबादले में अफसरों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिन अधिकारियों की सरकार को शिकायत मिली उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों के कलेक्टर, एसपी व संभागों के संभागायुक्त भी बदले जाने हैं। इस बदलाव के कई आधार होंगे। जिनमें जिलों में घटित होने वाली बड़ी घटनाओं को नहीं संभाल पाना, प्रशासनिक चूक के कारण घटना होना, नेताओं की वास्तविक नाराजगी का बार-बार सामने आना, खनिज माफिया व अपराधियों की करतूतें उजागर होना, अलग-अलग स्तर पर कमियों के कारण विपक्ष को मुद्दा मिलना, जैसे बिंदु अहम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ऐसे कुछ बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। प्रदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के लिए अब तक के उनके काम को देखा जाएगा। इसमें मंत्रालय में विभाग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर, उप सचिव, विभाग प्रमुख और संभाग और जिलों में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे।

कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर

मप्र में कई महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही राज्य को स्वतंत्र कृषि उत्पादन आयुक्त और कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष देने की तैयारी में है। वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल के पास है और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे के पास है, जबकि पीडब्ल्यूडी जैसे 12 बड़े विभागों का काम भी प्रभार पर चल रहा है। जो बड़े विभाग प्रभार पर हैं उनमें लोक सेवा प्रबंधन डॉ. राजेश राजौरा, एसीएस, सीएमओ, कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, एसीएस वन, कर्मचारी चयन मंडल संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, विमानन संजय शुक्ला, एसीएस, नगरीय विकास एवं आवास, पीडब्ल्यूडी नीरज मंडलोई, एसीएस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा संदीप यादव, पीएस, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आनंद विभाग राघवेंद्र सिंह, पीएस, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन, विज्ञान एवं तकनीकी संजय दुबे, एसीएस, जीएडी, संसदीय कार्य अनुपम राजन, एसीएस, उच्च शिक्षा, मप्र राज्य लोक संपत्ति अनिरुद्ध मुकर्जी, एसीएस लोक संपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल, विशेष आयुक्त समन्वय रश्मि अरुण शमी, एसीएस, खाद्य नागरिक मप्र भवन दिल्ली आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मप्र धार्मिक शिवशेखर शुक्ला, पीएस, संस्कृति एवं पर्यटन ट्रस्ट एवं बंदोबस्ती, पिछड़ा वर्ग एवं डॉ. ई. रमेश कुमार, पीएस अनुसूचित जाति अल्पसंयक कल्याण कल्याण, आयुष विभाग डीपी आहूजा, पीएस, मछुआ कल्याण, मत्स्य विकास, कुटीर-ग्रामीण उद्योग अमित राठौर, पीएस वाणिज्यक कर, पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, पीएस, खनिज संसाधन, एप्को नवनीत मोहन ठाकुर, पीएस, पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन एम सेलवेंद्रन, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि कार्मिक विकास विभाग है।

इनको मिलेगी पदस्थापना

मप्र के नए साल में जिन 4 डीआईजी को आईजी बनाया गया है, उन्हें अब आईजी के रूप में नई पदस्थापना मिलेगी। गौरतलब है कि 4 डीआईजी को प्रमोट कर आईजी बनाया गया था। 2007 बैच के आईपीएस अफसर डीआईजी छिंदवाड़ा सचिन कुमार अतुलकर को पदोन्नत कर आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी चंबल रेंज कुमार सौरभ, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल मध्यक्षेत्र कृष्णावेनी देसावतु और डीआईजी प्लानिंग जगत सिंह राजपूत को पदोन्नत कर आईजी बनाया गया है। इन सबकी पदस्थापना यथावत रखी गई है। हालांकि वहीं 2007 बैच की आईपीएस कृष्णावेणी देसावतु ओएसडी मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बनाई गई हैं। इन अफसरों की नई पदस्थापना के अलावा पुलिस विभाग में पीएचक्यू से लेकर मैदानी स्तर पर भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

पिछले साल अक्टूबर 2024 में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकार ने उन्हें 1 नवंबर 2024 से मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति दे रखी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में संविदा पर पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकार को पुलिस से संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आखिर क्यों बदले जा रहे एडीजी इंटेलीजेंस

प्रशासन में किसी भी अधिकारी की पदस्थापना सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन पिछले 14 महीने के दौरान जिस तरह सरकार बार-बार इंटेलीजेंस के एडीजी को बदल रही है, वह चर्चा का विषय बन गया है। सरकार ने अब तक 3 एडीजी बदल दिए हैं। विगत दिनों पुलिस विभाग में जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, उसमें एडीजी साइबर ए साईं मनोहर को इंटेलीजेंस की कमान सौंपी है। वहीं एडीजी इंटेलीजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे योगेश देशमुख को लोकायुक्त में प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है। इंटेलीजेंस सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। लेकिन जिस तरह पिछले 14 महीने में 3 एडीजी इंटेलीजेंस बनाए गए हैं, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि जिस तरह दिल्ली दरबार से प्रदेश में मुख्य सचिव और डीजीपी को पदस्थ किया गया है, उसी तरह प्रशासनिक जमावट भी वहीं के दिशा निर्देश पर हो रही है।

6 महीने में हटाए गए जयदीप

गौरतलब है कि मप्र सरकार ने गत दिनों 15 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया है। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारने वाले प्रभारी महानिदेशक, लोकायुक्त जयदीप प्रसाद को 6 महीने में ही हटा दिया गया है। उन्हें अब एडीजी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जिम्मेदारी दी गई हैं। जयदीप प्रसाद को 24 सितंबर 2024 को जारी आदेश में लोकायुक्त संगठन का प्रभारी महानिदेशक बनाया गया था। जयदीप प्रसाद की जगह योगेश देशमुख को लोकायुक्त में प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है। वहीं सीएम के ओएसडी राकेश गुप्ता को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण बनाया गया है। गुप्ता 5 महीने पहले 24 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ हुए थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लोटने के बाद एडीजी राजबाबू सिंह की पोस्टंग कर दी गई है। उन्हें पीएचक्यू में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाया गया है।

आखिर रीवा को मिला आईजी

गौरव राजपूत को रीवा रेंज का आईजी बनाया गया है। गौरव राजपूत के पास अभी ओएसडी, गृह विभाग की जिम्मेदारी थी। रीवा रेंज में आईजी का पद बहुत समय से खाली था। वहीं मऊगंज जिले में एक घटना में एएसआई की हत्या के बाद डीआईजी, रीवा रेंज साकेत प्रकाश पांडे को हटा दिया गया है। उन्हें डीआईजी, पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। उनकी जगह राजेश सिंह को रीवा रेंज का डीआईजी बनाया गया है। राजेश सिंह के पास अभी डीआईजी, सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल भोपाल की जिम्मेदारी है। वहीं 2007 बैच की आईपीएस कृष्णावेणी देसावतु ओएसडी मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बनाई गई हैं। कृष्णावेणी देसावतु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और तेज-तर्रार अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं। वो अपनी ड्रेस सेंस के लिए भी काफी चर्चा बंटोरती हैं। देसावतु हर जगह पर पोस्टिंग के दौरान अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए जानी जाती हैं।

ओएसडी के कमरे में हिंगणकर

मुख्यमंत्री कार्यालय में इन दिनों अजब-गजब नजारा देखने को मिल रहा है। नजारा यह है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश हिंगणकर इन दिनों ओएसडी के कमरे में बैठ रहे हैं। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी राकेश गुप्ता को संचालक खेल पदस्थ किया है। ऐसे में उनके स्थान पर राजेश हिंगणकर को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस संबंधी कार्यों (जो कार्य राकेश गुप्ता देखते थे) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश हिंगणकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहते भी यह जिम्मेदारी संभाल चुके थे।

● **राजेंद्र आगाल**

डायल-100 के पेमेंट के लिए ठनी

खटारा गाड़ियों के सहारे चल रही मप्र की डायल-100 सेवा के दिन फिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, पहले मुख्य सचिव और अब मुख्यमंत्री की फटकार के बाद डायल-100 की कायापलट करने के लिए 1570 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए डायल-100 वाहन खरीदने जाने हैं। पूर्व में करीब 1200 नए हाईटेक फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) खरीदने के लिए कैबिनेट ने 1565 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। अभी सेवा में 1000 वाहन हैं, लेकिन मेंटेनेंस न होने से 100 से ज्यादा वाहन कंडम होकर ऑफ रोड हो चुके हैं। अब मप्र में डायल-100 की नई और अपग्रेडेड 1200 एफआरवी (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) जल्द दौड़ती नजर आएंगी। उधर, डायल-100 की गाड़ियों के रखरखाव के साथ ही अन्य कार्यों के लिए पेमेंट को लेकर सरकार और पुलिस में ठन गई है। दरअसल, टेंडर प्रक्रिया जारी होने के बाद से पीएचक्यू के अधिकारी भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल लेकर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री से भुगतान की मांग कर रहे हैं। उधर, सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग इस बात से खफा है कि पीएचक्यू ने डायल-100 सेवा के टेंडर में इतनी देरी क्यों की। अगर पहले ही टेंडर जारी हो गया रहता तो आज भुगतान के लिए ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती।

गुरिल्ला वार की तैयारी में नक्सली

मप्र और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों ने संगठन स्तर पर कई बड़े फेरबदल किए हैं। मप्र के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सक्रिय देश की इकलौती नक्सल बटालियन को भी नक्सलियों ने कई टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब नक्सली छोटे-छोटे समूहों में गुरिल्ला वार की रणनीति बना रहे हैं, जबकि पहले गर्मियों में नक्सली बड़े हमले करते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्च, अप्रैल, मई और जून के समय को नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन (टीसीओसी) कहते हैं।

यह वही समय है, जब जंगल के भीतर दृश्यता बढ़ जाने का लाभ उठाकर नक्सली बड़े हमले करते रहे हैं। नक्सलियों के पुनर्वास की सरकार की नई नीति के चलते भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ऐसे लोगों को फिर से मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है। राज्य में शांति स्थापित होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। नक्सल मामलों के जानकारों का कहना है कि इस समय सुरक्षा बल की स्थिति जंगल के भीतर मजबूत हुई है। सटीक सूचना के आधार पर अभियानों में नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि नक्सली गुरिल्ला लड़ाई तकनीक के अनुसार छोटे-छोटे समूह में बंटकर बड़े नुकसान पहुंचाने की ताक में होंगे। गुरिल्ला युद्ध में छोटा बल भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रदेश में बीते 5 सालों में 1.52 करोड़ रुपए के 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं 3.31 करोड़ रुपए के ईनामी 20 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। मप्र पुलिस को इनपुट मिला है कि प्रदेश में करीब 75 नक्सली सक्रिय हैं। इनमें 20 महिला नक्सली हैं। ये सभी बालाघाट के आसपास के जंगलों में सक्रिय हैं। बीते 5 सालों में मारे गए नक्सलियों में 50 प्रतिशत महिला नक्सली भी शामिल हैं। मप्र में अब तक एक दर्जन से अधिक नक्सली घटनाएं सामने आई हैं। इनमें साल 1991 में बालाघाट के लांजी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वहीं साल 1999 में नक्सलियों ने प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे की हत्या कर दी थी। जबकि इसी साल बालाघाट के रुपझर थाना के ग्राम नारंगी क्षेत्र में माइन्स विस्फोट में 16 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इसी तरह नक्सलियों ने पुलिस से मुखबिरी के शक में 2 नवंबर 2023 को लांजी क्षेत्र के कासपुर ग्राम के भककुटोला में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। घटना के समय पूर्व सरपंच घर पर थे, नक्सलियों ने उन्हें घर से बाहर निकाला और गोली मार दी।

● जितेंद्र तिवारी

मप्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

- 6 नवंबर 2020 : बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली 25 वर्षीय शारदा उर्फ पुज्जे को मार गिराया। यह छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी।
- 11 दिसंबर 2020 : किरनापुर थाना अंर्तगत बोरवन-सिरका के जंगलों में 14 लाख की ईनामी नक्सली महाराष्ट्र के गढ़चिचौली निवासी 30 वर्षीय शोभा पति उमेश गावडे को मार गिराया।
- 12 दिसंबर 2020 : किरनापुर थाना अंतर्गत बोरवन-सिरका के जंगलों में 14 लाख की ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बस्तर निवासी सावित्री उर्फ आयते को मार गिराया।
- 8 मार्च 2021 : लांजी क्षेत्र के देवरबेली चौकी के मलकुंआ के जंगलों में 14 लाख के ईनामी महाराष्ट्र गढ़चिचौली निवासी 55 वर्षीय श्यामलाल उर्फ मोती राम सनकु जांगधुर्वे को गिरफ्तार किया।
- 10 अगस्त 2021 : गिरसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैरासी जंगल क्षेत्र में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा निवासी संदीप कुंजाम उर्फ लक्खु कुंजाम को गिरफ्तार किया।
- 20 जून 2022 : बहेला थाना के खराड़ी जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ बीजापुर के गंगालूर निवासी 23 वर्षीय मनोज डोडदी को मार गिराया।
- 20 जून 2022 : बहेला क्षेत्र के अंतर्गत खराड़ी के जंगल में 29 लाख के ईनामी नक्सली महाराष्ट्र गढ़चिचौली के नागेश उर्फ नागेश्वर उर्फ राजु तुलावी को मार गिराया।
- 20 जून 2022 : बहेला थाना क्षेत्र के खराड़ी के जंगलों में 14 लाख की ईनामी महिला नक्सली छत्तीसगढ़ बीजापुर निवासी 24 वर्षीय रामे पिता आयतु पुनेम को मार गिराया।
- 17 सितंबर 2022 : मलाजखंड थाना बांधाटोला समनापुर में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़, सुकमा निवासी बादल उर्फ कोसा उर्फ कोशन मड़ावी को गिरफ्तार किया था।
- 30 नवंबर 2022 : गढ़ी थानाक्षेत्र के सूपखार वन क्षेत्र में जामसेहरा वन चौकी में 29 लाख के ईनामी नक्सली महाराष्ट्र गढ़चिचौली के नयनगुड़ा निवासी 27 वर्षीय गणेश को मार गिराया। इसके साथ ही 20 लाख का ईनामी नक्सली राजेश उर्फ वंदा वंजाम मारा गया।
- 18 दिसंबर 2022 : मालखंड थाना के पाथरी चौकी के हर्राटोला जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा के रुपेश उर्फ हुंगा डोडी को मार गिराया। वहीं 14 दिसंबर 2023 को कमकोदादर जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़, बीजापुर निवासी चैतू उर्फ हिड़मा मरकाम को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया।
- 22 अप्रैल 2023 : गढ़ी थाना के कदला जंगल में 14 लाख की ईनामी महिला नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा निवासी सुनीता उर्फ सोमडी मांडवी को मार गिराया।
- 29 दिसंबर 2023 : सोनगुड़ा चौकी के कुंदुल-कोदपार जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ बीजापुर निवासी एसीएम कमलु को मार गिराया।
- 1 अप्रैल 2024 : थाना लांजी के पितकोना-केरझरी जंगल में 14 लाख रुपए के ईनामी नक्सली बालाघाट के दडेकसा निवासी एससीएम रघु उर्फ शेरसिंह उर्फ सोमजी पंद्रे को मार गिराया।
- 1 अप्रैल 2024 : लांजी थाना के पितकोना केरझरी जंगल में 29 लाख की ईनामी महिला नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा के रेगाड़म निवासी साजंती उर्फ क्रांति पति सुरेंदर को मार गिराया।
- 8 जुलाई 2024 : हट्टा थाना के कोठियाटोला जंगल में 14 लाख के ईनामी नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा के सोहन उर्फ उकास एर्फ आयतु को मार गिराया।

पेट माफिया का पूरे स्टेट में खूंखार सिंडिकेट

मंत्री एदल सिंह कंषाना के विवादास्पद बयान ने एक गंभीर बहस छेड़ दी है। मंत्री ने रेत माफिया को पेट माफिया बताया था। इस बयान से सरकार की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। हाल के वर्षों में रेत माफिया की हिंसक गतिविधियां बढ़ी हैं। माफिया सरकारी कर्मचारियों पर हमले कर रहे हैं। माफिया को जब लगता है कि उसके धंधे में कोई बाधक बन रहा है तो वे उसे मौत के घाट उतारने में भी देर नहीं करते हैं। ऐसे में मंत्री के बयान को माफिया की हिंसक गतिविधियों को कम आंकने वाला माना जा रहा है।

पिछले कुछ सालों में मप्र में रेत माफिया की गुंडागर्दी बढ़ गई है। 2024 और 2025 में कई ऐसी घटनाएं हुईं हैं, जिनमें माफिया ने खुलेआम कानून को तोड़ा है। हाल ही में मुरैना में एक और ऐसी घटना हुई। वन विभाग की टीम ने रेत से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। माफिया के लोगों ने ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को धमकी भी दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सरकार की कमजोरी उजागर हुई। रेत का अवैध कारोबार करोड़ों रुपए का है। एक ट्रक रेत से 10,000 से 30,000 रुपए तक की कमाई होती है। यह सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है। यह एक बड़ा व्यवसाय है। इसमें होने वाला मुनाफा माफिया और उनके साथियों के बीच बंटता है। विपक्षी दलों के आरोपों से पता चलता है कि माफिया को स्थानीय नेताओं और अधिकारियों का समर्थन मिलता है। इससे पेट माफिया वाली बात कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि इसमें पावर और प्रभाव का खेल शामिल है।

संसद में भी उठ चुका है नर्मदा खनन का मुद्दा

मप्र में रेत के अवैध खनन का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। मप्र की जीवन रेखा नर्मदा जो अब तक प्रदेश में राजनीति का बड़ा मुद्दा बनी रही। नर्मदा में अवैध खनन का मुद्दा हर चुनाव में कांग्रेस सबसे मजबूत हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा के सांसद ने ही सदन में नर्मदा में बढ़ते अवैध खनन का मुद्दा उठा दिया। नर्मदापुरम से पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा के शून्यकाल में नर्मदा की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अब औद्योगिक इकाइयों का कचरा भी नर्मदा में मिल रहा है। लिहाजा अब जरूरी है कि नर्मदा के संरक्षण की योजना बनाई जाए। नर्मदापुरम से सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद में शून्यकाल में नर्मदा नदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी मां नर्मदा के संरक्षण की अति आवश्यकता है। मां नर्मदा गुजरात सहित मप्र की जीवनरेखा है। केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही मां नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक नहीं है। बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संरक्षण नहीं होने से लोगों के उपयोग के लिए अनफिट होती जा रही हैं। बांधों और हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण से मूल स्वरूप बदल रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। नदी में अधिक रेत खनन के कारण नर्मदा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

मंत्री अवैध रेत कारोबार और रेत माफिया को किसी भी नजर से देखें, लेकिन रूह कंपा देने वाली हकीकत यह है कि अवैध रेत के इस कारोबार के आगे रेत माफिया लोगों की जान की कीमत नहीं समझ रहे। अवैध रेत लेकर अंधी रफ्तार में दौड़ रहे रेत माफिया के वाहन हर साल औसतन पांच लोगों की जान ले रहे हैं। रेत माफिया का आतंक 21 जून 2018 को दिखा, जब जिला मुख्यालय से चार किलोमीटर दूर रामपुर गंज गांव के पास अवैध रेत के तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने महिंद्रा मैक्स गाड़ी को टक्कर मारी। इसमें 15 लोग थे, जिनमें 12 की मौत हुई। लगभग आठ साल पहले एसपी विनीत खन्ना और कलेक्टर विनोद शर्मा बरवासिन घाट पर निरीक्षण को पहुंचे थे, तब रेत माफिया ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जवाब में पुलिस ने भी खूब फायर किए। इसमें अफसरों ने भागकर जान बचाई। खनन माफिया अब तक अनगिनत जानें ले चके हैं। 31 मार्च 2014 को देवरी घड़ियाल केंद्र पर हवलदार विश्वनाथ को माफिया ने गोलीमारी थी। 5 अप्रैल 2015 को धनेला रोड पर डंपर से कुचलकर पुलिस आरक्षक धर्मेंद्र सिंह चौहान की हत्या की। 16 सितंबर 2015 को रेत के ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर हाईवे पर युवक की मौत। 7 मार्च 2016 रेत माफिया ने वन आरक्षक नरेंद्र शर्मा को ट्रैक्टर से कुचलकर मारा। 20 फरवरी 2017 को रेत के ट्रैक्टर ट्राली ने मां-बेटे को कुचला, जिसमें बच्चे की मौत हुई थी। 2 मार्च 2016 को टेंटरा में रेत के ट्रैक्टर से कुचलकर चार माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2016 को रामपुरकलां में रेत के ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलकर महिला की मौत हुई थी। 18 जून 2017 को रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली ने दो भाइयों को कुचला था। 25 जून 2017 को रेत के ट्रैक्टर-ट्राली से महिला की मौत हो गई। 25 दिसंबर 2017 को अंबाह में रेत के ट्रैक्टर-ट्राली ने एक खिलाड़ी को कुचला, विरोध में जाम लगा था। 6 सितंबर 2018 को रेत माफिया ने वन नाके पर ट्रैक्टर से कुचलकर डिप्टी रेंजर की हत्या की। सितंबर 2020 में मुड़ियाखेड़ा में बुजुर्ग को अवैध रेत के ट्रैक्टर-ट्राली ने कुचला। जनवरी 2020 में 9वीं की छात्रा को रेत के ट्रैक्टर-ट्राली ने कुचला। 9 नवंबर 2022 को बड़ोखर चौराहे पर रेत से भरे टैक्टर-ट्राली से नरेश पुत्र रतीराम की मौत हो गई। 19 मार्च 2024 को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने नेशनल हाईवे 44, सिकरौदा नहर के पास खांडौली के रहने वाले 40 वर्षीय घनश्याम सिंह सिकरवार को कुचलकर मार डाला। घनश्याम सिंह उप्र के एटा में शिक्षक थे।

शहडोल में मई 2024 में एक दुखद घटना हुई। सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) महेंद्र बागरी को रेत से भरे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि माफिया कितने बेखौफ हैं। शहडोल में ही नवंबर 2023 में एक और घटना हुई थी। पटवारी प्रशन्न सिंह को भी रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। यह छह महीने में दूसरी घटना थी। शाजापुर में 2023 में एक महिला खनन निरीक्षक और होमगार्ड्स पर हमला हुआ था। माफिया ने उनके साथ मारपीट की थी। इन घटनाओं से पता चलता है कि रेत माफिया सिर्फ अवैध खनन नहीं कर रहा है। वे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं।

● **लोकेश शर्मा**

किसान बनेंगे बिजली उत्पादक

मप्र में सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार किसानों को बिजली उत्पादक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। इससे न केवल आम जनता को महंगी बिजली से राहत मिलेगी वहीं किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि किसानों को खेतों के लिए लगातार बिजली चाहिए होती है। दरअसल, प्रदेश में बंजर, अनुपयोगी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए किसानों को बिजली उत्पादक बनाया जाएगा। यह सोलर प्लांट किसान और निवेशक मिलकर भी लगा सकते हैं। इन सोलर प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली को सरकार खरीदेगी। इसके लिए सरकार सोलर प्लांट लगाने वालों से 25 साल का अनुबंध करेगी। केंद्र सरकार ने कुसुम 'ए' योजना के तहत प्रदेश को 1790 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का टॉरगेट दिया। इसके तहत 500 मेगावाट तक के पावर परचेज एग्रीमेंट की तैयारी हो चुकी है।

कुसुम 'ए' योजना के तहत यह प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया ऊर्जा विकास निगम ने शुरू कर दी। इसके लिए निगम के पास 1 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं। पीपीए में देरी की वजह से काम अटका हुआ था। अब सरकार के निर्देश के बाद सभी पावर परचेज एग्रीमेंट 31 मार्च तक करने के निर्देश हैं। अभी मप्र इस योजना के तहत बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कुसुम 'ए' योजना में मप्र को चार चरणों में अभी तक 1790 मेगावाट की सौर विद्युत गृह स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। मप्र ऊर्जा विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है। मप्र ऊर्जा विकास निगम द्वारा लगभग 1001 मेगावाट के एलओए जारी हो चुके हैं। इसमें से मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 240.02 मेगावाट के (पीपीए) पावर परचेज एग्रीमेंट कर दिए हैं। इस माह के अंत तक 500 मेगावाट के पीपीए कर दिए जाएंगे। राजस्थान प्रथम और महाराष्ट्र अभी कुसुम 'ए' योजना में तीसरे स्थान पर है।

प्रदेश के सभी जिलों में 2033 सोलर प्लांट इस स्कीम के तहत लगाए जाएंगे। सबसे ज्यादा 1079 सोलर प्लांट सेंट्रल जोन में लगेंगे। वेस्ट जोन में 372 और ईस्ट जोन में 582 प्लांट लगाए जाएंगे। ये सोलर प्लांट 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होंगे। परियोजना से उत्पादित विद्युत, शासन द्वारा क्रय की जाएगी, जिससे कृषकों को नियमित आय होगी। प्रदेश की वितरण कंपनियों द्वारा चिन्हित सब स्टेशनों से 5 किमी की परिधि में सोलर प्लांट लगेंगे। बिजली कंपनियों ने प्रदेश के सभी सब स्टेशन की लिस्ट ऊर्जा विकास निगम को सौंप दी है। इसके मुताबिक निवेशक और किसान सोलर प्लांट के लिए आवेदन कर सकते है। कृषि भूमि पर लगने वाले सोलर प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली को 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा जाएगा। इसका अनुबंचन उत्पादक के साथ सरकार और बिजली कंपनी 25 साल के लिए करेगी। यानी सरकार उत्पादकों से 25 साल तक बिजली खरीदेगी। ऊर्जा विकास निगम द्वारा निर्धारित सभी सोलर प्लांट अगर प्रदेश में लग जाते हैं, तो आधे से ज्यादा प्रदेश सोलर ऊर्जा से रोशन हो सकता है। परियोजना के संचालन और रखरखाव का अनुबंध भी मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी करेंगी। मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मप्र में 20 गीगावाट या उससे अधिक की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वपूर्ण सहयोग से मप्र में लगभग 80,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। इससे सोलर एनर्जी उत्पादन और अधिक बढ़ जाएगा। सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।

मप्र ऐसा राज्य है, जहां पर बिजली की स्थिति सरप्लस वाली है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों को भी बड़ी मात्रा में बिजली की सप्लाई मप्र द्वारा की जाती है। ताप विद्युत के बाद मप्र में तेजी से सौर ऊर्जा से बिजली बन रही है। अब प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में नए प्रयोग करने जा रही है। यह प्रयोग विदेशों की तर्ज पर करने की तैयारी है, जिससे एक ही स्थान पर तीन तरह से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। यानि की एक ही जगह पर पानी, कोयला के अलावा सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में अब हाइब्रिड कॉम्बो पावर प्लांट लगाने की योजना है। अभी तक सिर्फ एक ही कैटेगरी की बिजली का पावर प्लांट होता आया है, लेकिन प्रदेश में अब हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लाने की तैयारी हो गई है। यानी सीधे तौर पर कहें तो हवा, पानी और सूरज से एक साथ बिजली बनाने का रास्ता खुलेगा।

● **प्रवीण सक्सेना**

कार्बन उत्सर्जन कम और बिजली ज्यादा मिलती है

हाइब्रिड प्रोजेक्ट मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा के रहते हैं। इसलिए इनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और बिजली ज्यादा मिलती है। एक ही जगह दो पावर प्लांट होने से लागत कम होती है। इस पर खर्च भी कम होता है। ईंधन कम लगता है। यह प्लांट निजी निवेशकों द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे एनर्जी के क्षेत्र में स्पर्धा बढ़ती है। इससे सस्ती बिजली मिलती है। प्रदेश में अभी तक थर्मल, हाईडल, सोलर और विंड पावर प्लांट अलग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन, अब इनमें से एक या दो कैटेगरी के पावर प्लांट एक जगह पर लगाकर उत्पादन हो सकेगा। इसमें केवल सोलर, हाईडल व विंड प्रोजेक्ट हाइब्रिड होकर एक साथ भी लगाए जा सकेंगे। मसलन, पानी से बनने वाली बिजली की जगह पर ही सोलर पैनल के जरिए हाईडल व सोलर दोनों बिजली का प्रयोग हो सकेगा। हाइब्रिड कॉम्बो पावर प्लांट विदेशों में सफल रहे हैं। इसमें चीन में सबसे अधिक काम हुआ है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित कुछ देशों में हाइब्रिड सिस्टम है। वहीं भारत में साउथ में इस पर कुछ काम हुआ है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स में इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। अब मप्र में इस पर काम हो रहा है।

पदोन्नति का 36:64 फॉर्मूला फेल

मप्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक अब हटने की संभावना है। यदि इस पर अमल किया जाता है, तो हजारों कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। पदोन्नति के लिए सरकार ने तीन विकल्प बनाए हैं। पहला कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वरिष्ठता की गणना किस तारीख से होगी। दूसरा 2002 से अब तक जिन 60,000 से अधिक एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है, उनका डिमोशन नहीं किया जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2024 को दिए फैसले में कहा था कि 2002 के आधार पर हुए प्रमोशन रद्द किए जाएं, लेकिन सरकार इसका नया समाधान निकालेगी। तीसरा इस प्रमोशन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों के अंतिम निर्णय के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। यानी पूर्व में पदोन्नति का जो 36:64 फॉर्मूला बनाया गया था, वह फेल हो गया है।

बता दें कि साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए पदोन्नति में आरक्षण लागू किया, ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ने लगा तो कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया, जिसके बाद 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया। लेकिन, बात यहीं खत्म नहीं हुई और तत्कालीन शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मई, 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन इस पर अमल से पूर्व सरकार गिर गई। कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम देने को लेकर 9 दिसंबर, 2020 को उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। पदोन्नति का फॉर्मूला तय करने के लिए 13 सितंबर, 2021 को मंत्री समूह गठित किया गया। मंत्री समूह की सिफारिशें लागू नहीं की गई। बता दें कि इस अवधि में 80 हजार से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

गौरतलब है कि मप्र में अधिकारी, कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले करीब 9 साल से रोक लगी है। पदोन्नति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कर्मचारियों की मांगों पर सरकारों ने पदोन्नति का रास्ता निकालने के प्रयास तो किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मोहन सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर 36:64 प्रतिशत का फॉर्मूला प्रस्तावित किया था, जिसमें 36 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों के लिए और शेष 64 प्रतिशत पद सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान था। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) और मप्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण इस फॉर्मूला पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। फिलहाल सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस फॉर्मूले में पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36 प्रतिशत पर ही एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने की बात कही गई थी, शेष बचे 64 प्रतिशत पदों पर उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती थी। फॉर्मूले में यह भी प्रावधान किया गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले सरकार यह भी देखेगी की यदि पदोन्नत होने वाले कुल पदों में से 36 प्रतिशत पदों पर एससी-एसटी के कर्मचारी पदस्थ हैं, तो उन्हें पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया था कि यदि दोनों संगठनों के बीच इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा मामला सुप्रीम कोर्ट में पूर्ववत चलता रहेगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे की इस संबंध में सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों के साथ दो-तीन दौर की चर्चा हुई, लेकिन इस फॉर्मूले पर उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाया।

बता दें कि मप्र एकमात्र राज्य है, जहां इतने वर्षों से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकालकर पदोन्नति प्रक्रिया को गति दी जाएगी। प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयान के बाद कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब विपक्ष के समर्थन से प्रमोशन से जुड़े मुद्दों को स्थायी समाधान मिले। सपाक्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पहले हाईकोर्ट के आदेशानुसार पूर्व में पदोन्नत हुए एससी-एसटी के कर्मचारियों को रिवर्ट किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओबीसी के क्रीमीलेयर के कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता, यदि सरकार ऐसा करती है, तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। साथ ही संख्या के अनुपात में पदोन्नति कैसे दी जा सकती है। अजाक्स के प्रदेश महासचिव एसएल सूर्यवंशी का कहना है कि संविधान के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पदोन्नति के मामले में मप्र शासन जो भी निर्णय लेगा, हमारे संघ को वह मान्य होगा। सरकार के 36:64 का फॉर्मूले में अजाक्स को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को नियम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर सरकार को सेवारत कर्मचारियों से बात करना चाहिए।

● अरविंद नारद

पदोन्नति की आस में 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी

मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल, 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 2002 के बाद पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 12 मई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति के इंतजार में नौ साल में 80 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो नौकरी में हैं, वे हताश और निराश हैं। प्रदेश में पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। तत्कालीन शिवराज सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम देने को लेकर दिसंबर, 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट पर कई विभागों में कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया।

मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में एक बार फिर इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरह अधिकारियों ने योजनाओं में अनियमितता की है। कैग ने कई अनियमितताओं पर आपत्ति उठाते हुए सरकार से जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। लेकिन विडंबना यह है कि हर साल अनियमितता आने के बाद भी न जांच होती है और न ही कार्रवाई।

अनियमितता की भेंट चढ़ी योजनाएं

मप्र विधानसभा के बजट सत्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2022 की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की कई प्रमुख योजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के खुलासे के बाद, विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और मप्र को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि में भारी झोलझाल हुआ है। यह झोलझाल किसी और ने नहीं बल्कि संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने ही किया है। वर्ष 2018 से 2022 तक पांच साल में 13 जिलों में कर्मचारियों, उनके रिश्तेदारों समेत अपात्र लोगों को 23.81 करोड़ रुपए की राहत राशि दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 से 2022 के बीच मप्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को 10,060 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की गई। हालांकि, इसमें से 13 जिलों में 23.81 करोड़ रुपए की राशि फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी स्वीकृति आदेश तैयार कराए और अपने तथा रिश्तेदारों के खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। कैग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से उन सभी जिलों में आपदा राहत राशि वितरण की जांच कराई जाए, जो कैग की जांच में शामिल नहीं हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल बजट प्रणाली और आईएफएमआईएस की कमियों ने ई-भुगतान प्रणाली को कर्मचारियों के लिए सरकारी धन के गबन का माध्यम बना दिया है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी सिवनी जिले में हुई, जहां 11.79 करोड़ रुपए गबन किए गए। इसके अलावा, श्योपुर में 3.36 करोड़ रुपए, शिवपुरी में 3 करोड़ रुपए, देवास में 1.26 करोड़ रुपए और सीहोर में 1.17 करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। अन्य जिलों में भी करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पाई गई। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और नागरिकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा 6-4 के तहत मुआवजा देती है। इसमें ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, पाला, शीतलहर, कीट प्रकोप, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा और अग्नि दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रदान की जाती है। कैग की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बड़वानी जिले की राजपुर और सेंधवा जनपद पंचायतों में सीईओ और लेखपाल ने मिलकर 2.47 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली। यह पैसा मजदूरों की मदद के लिए आया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे अपने और अपने करीबी लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक मृत मजदूर के नाम पर संबल योजना और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना से कुल 89.21 लाख रुपए निकाले गए। इसके अलावा, जो मजदूर पहले ही संबल योजना का लाभ ले चुके थे, उन्हें नियमों का उल्लंघन करके 72.60 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दे दी गई। कैग ने पाया कि श्रम विभाग ने 2.18 करोड़ मजदूरों का पंजीयन किया था, लेकिन बाद में इनमें से 67.48 लाख मजदूरों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इन लोगों को अपात्र ठहराने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। अकेले बड़वानी जिले में ही 1320 लोगों ने जब अपात्र घोषित किए जाने पर शिकायत की तो बिना किसी जांच के 1085 लोगों को दोबारा पात्र मान लिया गया। कैग की रिपोर्ट में सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है।

अवैध निर्माण से सरकार को 322.71 करोड़ का नुकसान

भोपाल के वल्लभ भवन और कलेक्ट्रेट के पास 37.69 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर झुग्गी और अवैध निर्माण से सरकार को 322.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण इन अतिक्रमणों को समय रहते हटाया नहीं गया, जिससे राजस्व हानि हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर इस अतिक्रमण को रोकने के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। न तो इसे अतिक्रमण पंजी में दर्ज किया गया और न ही संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजी गई। कैग ने अपनी जांच में पाया कि यदि समय रहते यह अतिक्रमण चिह्नित कर लिया जाता, तो इसे हटाने की कार्रवाई हो सकती थी। इधर, भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 20.23 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी गई। कैग रिपोर्ट के अनुसार, जमीन की कीमत 218 करोड़ रुपए थी, पर इसे मात्र 38.85 करोड़ रुपए में सौंप दिया गया। कलेक्टर ने इस जमीन का बाजार मूल्य 109 करोड़ रुपए तय किया था, लेकिन पट्टा विलेख 38.85 करोड़ रुपए में किया गया और सिर्फ 9.71 करोड़ (कीमत का 25 प्रतिशत) ही प्रीमियम लिया गया।

भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की गई जिससे 65.5 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। संबल योजना में भी गड़बड़ी सामने आई है। 67 लाख 48 हजार श्रमिकों को अपात्र किया गया है। संबल योजना के कुल 31 फीसदी लोगों को अपात्र किया गया। इसी तरह अंत्येष्टि सहायता राशि में भी गड़बड़ी की गई है। श्रमसेवा पोर्टल के डाटा का विश्लेषण किया गया जिसमें 142 मामलों में 52 खातों में 1.68 करोड़ की राशि जमा की गई, ये खाते पंजीकृत श्रमिकों के नहीं थे। विवाह सहायता के 86 मामलों में बिना पंजीकृत श्रमिकों के 41 बैंक खातों में 38.92 लाख की राशि जमा की गई।

दरअसल, मप्र सरकार रजिस्टर्ड श्रमिकों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि और अनुग्रह राशि उसके परिवार को देती है। इसमें रजिस्टर्ड श्रमिकों को उनके विवाह और दो बेटियों के विवाह के तहत भी राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। रिपोर्ट में इसमें गड़बड़ी मिली है। जांच में पाया गया कि 142 प्रकरणों में 52 बैंक खातों में अपात्र के खाते में राशि जारी कर दी गई। इसके लिए फर्जी नाम का उपयोग किया गया। इस तरह के मामले भोपाल समेत अन्य नगर निगमों में सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दो करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि संदिग्ध खातों में ट्रांसफर की गई। यही नहीं दस्तावेजों की जांच में यह भी सामने आया है कि विदिशा, आगर मालवा, सतना, दमोह, रायसेन, मंदसौर, खंडवा, छतरपुर, देवास, शिवपुरी, सीहोर, श्योपुर और सिवनी समेत 13 जिलों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान की राशि में गड़बड़ी की गई है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर अपने रिश्तेदारों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी। वर्ष 2022 में करीब 23 करोड़ 81 लाख की राशि का भुगतान हुआ है। इस गड़बड़ी के लिए अलग-अलग बैंकों में एक ही व्यक्ति के नाम से कई खातों का उपयोग किया गया।

सिवनी में डूबने, सांप काटने और बिजली गिरने के मामलों में 11.14 करोड़ रुपए की राशि की धोखाधड़ी पाई गई है। यही नहीं अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से स्वीकृति आदेश जारी करने की बात भी रिपोर्ट में लिखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में 40 से ज्यादा सहकारी समितियों के खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि जमा करने में अंतर पाया गया है। दरअसल, तहसीलदारों ने समितियों के बैंक खातों में 56.91 करोड़ की राशि जमा की, लेकिन समितियों की तरफ से सिर्फ 48 करोड़ की राशि ही प्रमाणित की गई। अब बाकी राशि का कैग को कोई हसाब नहीं मिला। संबल योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि की स्वीकृति और भुगतान में भी बड़े पैमाने पर देरी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, हजारों मामलों में सहायता राशि 1,272 दिनों तक विलंब से स्वीकृत की गई, जबकि योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसे 15 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए। एनआईसी डेटा और संबल योजना के बैंक खाते की जांच में पाया गया कि 1,68,342 आवेदनों में से 1,07,076 (64 प्रतिशत) मामलों में स्वीकृति में 1 से 1,272 दिनों तक की देरी हुई। रिपोर्ट के अनुसार 1,349.92 करोड़ की राशि वाले 60,674 मामलों में भुगतान 2 से 1,013 दिनों तक विलंब से किया गया। कैग रिपोर्ट 2022 में सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की गई। इससे राजस्व को 65.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

● सुनील सिंह

कहां, क्या मिली गड़बड़ियां?

- खंडवा जिले के सभी तहसीलदारों ने अतिवृष्टि के कारण 105 सहकारी समितियों को 164.31 करोड़ का भुगतान किया। इन समितियों ने किसानों की पहचान किए बिना ही 8.28 करोड़ का विसंगतिपूर्ण और 4.93 करोड़ की अनियमितता की।
- भोपाल की हुजूर तहसील में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलुरु को बाजार मूल्य के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 20.234 हेक्टेयर जमीन गलत ढंग से आवंटित करने की वजह से सरकार को 65.05 करोड़ का नुकसान हुआ।
- कलेक्टर धार ने आईएचबीएल इंदौर को भूमि आवंटन के एक प्रकरण में बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत इंद्रावल में आवंटित 3.750 हेक्टेयर भूमि पर निर्धारित प्रीमियम एवं पट्टा किराया पर पंचायत उपकर नहीं लगाने की वजह से 70.13 लाख रुपए की चपत लगी।
- इंदौर के ग्राम बड़ा बांगड़दा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट को शून्य प्रीमियम एवं एक रुपए वार्षिक पट्टा किराए पर शासकीय भूमि के आंवटन के कारण 4.19 करोड़ के प्रीमियम और 4.13 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वार्षिक पट्टा किराए की हानि सरकार को हुई।
- भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण (एएआई) को शून्य प्रीमियम एवं एक रुपए वार्षिक पट्टा किराए पर भूमि आंवटन की वजह से सरकार को 26.64 करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- स्वामी विवेकानंद तकनीकी संस्थान को शून्य प्रीमियम एवं एक रुपए वार्षिक पट्टा किराए पर शासकीय भूमि के आवंटन की वजह से 12.94 लाख प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया में 25 हजार 889 रुपए हर साल की वसूली नहीं हुई।
- चयनित 8 जिलों की 23 तहसीलों में 2,371 प्रकरणों अवैध कब्जे वाले मामले की जांच से पता चला कि संबंधित तहसीलदारों ने 2,364 प्रकरणों में अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बेदखली के आदेश जारी किए थे, लेकिन 1,037 प्रकरणों में 38.74 लाख रुपए की वसूली नहीं की गई थी। अनाधिकृत कब्जा जारी रहने के कारण सरकार को 71.68 करोड़ की हानि हुई।
- मुख्यमंत्री संबल योजना में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए गलत प्रक्रिया अपनाई और भौतिक सत्यापन के दौरान 2.18 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों में से 67.48 लाख को विभिन्न कारणों जैसे ढाई एकड़ से अधिक जमीन, सरकारी सेवा में कार्यरत और करदाता होने के बाद भी 67.48 लाख असंगठित श्रमिकों में से 14.34 लाख के अपात्र होने पर उन्हें लाभ दिया गया। इससे सरकार को करोड़ों की चपत लगी।

चारा घोटाले की तर्ज पर धान घोटाला

मप्र के जबलपुर में बिहार के चारा घोटाले की तरह धान घोटाला हुआ है, जहां धान मिलिंग और परिवहन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया। घोटालेबाजों ने परिवहन दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी की।

धान को ट्रकों के बजाय कार, बस, ट्रैक्टर और पिकअप जैसी गाड़ियों में परिवहन होना दिखाया गया। इतना ही नहीं, कुछ वाहन तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रहे थे, लेकिन कागजों में उन्हें धान ढोते हुए जबलपुर से बाहर जाते हुए दर्शाया गया। धान मिलर्स ने 14 हजार टन धान के उठाव के लिए कुल 614 ट्रिप दिखाए, लेकिन टोल नाकों पर जांच करने पर इनमें से 571 ट्रिप का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यहां तक कि एक ही ट्रक को एक दिन में तीन-तीन बार जबलपुर से उज्जैन जाते हुए दिखाया गया, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है।

47 करोड़ के धान घोटाले में अधिकारी-कर्मचारी सहित 17 राइस मिलर्स सहित कुल 74 लोगों के खिलाफ 12 थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। धान की खरीदी से लेकर मिलिंग में काम कर रहे संगठित गिरोह का दुस्साहस ऐसा था कि कार और बस में भी धान की ढुलाई दिखा दी। दरअसल, जिन चालान में जिन वाहनों के नंबर डाले गए थे वह प्राइवेट और यात्री वाहन निकले। प्रशासन की जांच में 55 वाहनों के फर्जी नंबर डाले जाने का खुलासा हुआ है। इसी प्रकार जीएसटी से ई-वे बिल के जरिए जांच कराई तो यह खुलासा भी हुआ कि मिलर्स के 15 वाहनों में धान का चालान कटा लेकिन वे उसी तारीख में प्रदेश के दूसरे शहरों में स्क्रेप, सोयाबीन, ऑर्टिकल ऑफ स्टोन, मिनरल, कैमिकल, मार्बल और लकड़ी की ढुलाई कर रहे थे। एक मिलर ने तो ट्रिप के नाम पर हद कर दी, उसने एक वाहन से एक दिन में उज्जैन के चार ट्रिप बता दिए। इस फर्जीवाड़े के खुलासे में दो महीने का समय लगा लेकिन इस दौरान जांच दल कई जगहों पर गया। आरटीओ से लेकर जीएसटी के अधिकारियों से संपर्क कर वाहनों का पूरा ब्यौरा एकत्रित किया।

17 राइस मिलर्स ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। उन्होंने गोदामों से धान की खरीदारी किए बिना ही फर्जी एंट्री कराई। स्थानीय दलालों के माध्यम से सरकार को चूना लगाया गया। इस फर्जीवाड़े में मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक सहित 13 अधिकारी और 44 सोसाइटी व उपार्जन केंद्र के कर्मचारी शामिल थे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 2510 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 307 ऐसे वाहन नंबर इस्तेमाल किए गए जो असल में कार और बस के थे। यानी, कागजों में दिखाई गई गाड़ियां पूरी तरह से फर्जी हैं। उन्होंने सरकारी खजाने को जमकर चपत लगाई। ठेकेदारों ने कार से लेकर बस, ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ियों में करोड़ों की धान का परिवहन दिखाकर सरकार को चूना लगाया। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रही गाड़ियों को भी धान के परिवहन में इस्तेमाल करना दिखाने के साथ-साथ जिन गाड़ियों की क्षमता 100 क्विंटल तक की है उनमें 400 क्विंटल तक धान का परिवहन बताकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया। हैरानी की बात तो यह है कि घोटालेबाज ठेकेदारों ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से सांठगांठ कर एक ही गाड़ी को एक ही दिन में जबलपुर से उज्जैन तक की तीन-चार ट्रिप दिखाई हैं। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना की अगुवाई में बनी टीम ने करीब ढाई हजार पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की है। जबलपुर से उज्जैन, मनेरी मंडला, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर के मिलर्स के 307 ट्रिप को फर्जी पाया है। इनमें 15 ऐसे हैं जो कि निर्धारित रूट से अलग थे। इनमें दूसरी चीजों की ढुलाई चल रही थी। इन ट्रिप को मिलर्स ने धान की मिलिंग के नाम पर बिल से घटाने का प्रयास किया लेकिन सही समय पर इसका पर्दाफाश हो गया।

47 करोड़ के 2 लाख क्विंटल धान मिलिंग व घोटाले में प्रशासन ने जिले के 12 थानों में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक दिलीप किरार व उसके 13 स्टाफ सहित राइस मिलरों व समिति के 74 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 67 की तलाश है। उधर, धान घोटाले के पुराने मामले में फरार छह आरोपियों पर एसपी संपत उपाध्याय ने 5-5 हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की। बताया गया है पनागर थाने में सेवा सहकारी समिति पनागर के केंद्र प्रभारी चंदन कॉलोनी पनागर निवासी रविशंकर पटेल, भिड़ारीकला निवासी कम्प्यूटर ऑपरेटर विनय पटेल, सर्वेयर कोहना निवासी महेंद्र पटेल और और गढ़ा कोटा सागर निवासी महेंद्र पटेल व सेवा सहकारी समिति महाराजपुर की खरीदी केंद्र प्रभारी मोहिनी पाठक, कम्प्यूटर ऑपरेटर विश्वास खरे और सर्वेयर विकास खरे समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

● धर्मेंद्र कथूरिया

96 फीसदी धान का गोलमाल

जांच में पता चला कि जबलपुर से मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा और मंडला भेजी गई धान का अधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। सैकड़ों ट्रकों में धान भेजने की बात कही गई थी। लेकिन ये ट्रक नेशनल हाईवे के टोल नाकों से गुजरे नहीं। 1 लाख 31 हजार क्विंटल से अधिक धान का परिवहन फर्जी नंबर वाले वाहनों से किया गया। टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरओ में दर्ज वाहन नंबर वाले 614 ट्रक टोल नाकों से गुजरने थे, लेकिन महज 15 ट्रक ही इन टोल नाकों से गुजरे। जांच से बचने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के जरिए धान का परिवहन किया गया। जो नंबर आरओ में दर्ज थे, जांच में वे नंबर बसों और कारों के निकले, जिनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई संबंध ही नहीं था। इधर, पुलिस ने देर से एफआईआर होने के बाद एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादातर फरार हो गए हैं, जिनके लिए टीमें गठित की गई हैं। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि एक ही रात में करीब एक दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के घर में दबिश दी गई, लेकिन वे पहले ही फरार हो चुके थे। जानकारों के अनुसार, आरोपियों से ये जानकारी मिल सकेगी कि जब धान दूसरे जिलों में नहीं भेजी गई कि जबलपुर में किसे बेंची गई। इन नामों के खुलासा होने के बाद कार्रवाई की दूसरी कड़ी शुरु होगी। बताया गया है कि इतने बड़े पैमाने में बंदरबांट करने वाले रसूखदार ही होंगे।

गांवों में गहराया जलसंकट

बैठक तक ही सिमट गया प्रयास

प्रदेश के विभिन्न जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं की समीक्षा हुई। लेकिन पानी उपलब्ध कराने का प्रयास बैठक तक ही सिमट गया। दमोह में 3 जुलाई और 3 अगस्त 2024 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। गुना में पिछले साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के मौके पर बैठक हुई और 29 नवंबर को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक और इस साल 24 जनवरी को जिला पंचायत में जल जीवन मिशन की प्रगति और योजना स्थानांतरण की समीक्षा बैठक हुई । 24 जनवरी को जिला पंचायत की बैठक और 21 फरवरी को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक हुई। नीमच में पिछले साल 10 और 24 दिसंबर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और जल जीवन मिशन की क्रियान्वित गांधीसागर 2 समूह जलप्रदाय योजना की समीक्षा बैठक हुई। बुरहानपुर में 31 जुलाई, 8 अगस्त, 10 अक्टूबर, 18 नवंबर 2024 को हुई जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन, संधारण, सभी आंगनवाड़ियों, स्कूलों और सरकारी भवनों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। ऐसा ही हाल अन्य जिलों में भी रहा।

भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बिसनखेड़ी गांव में जलसंकट गहराने लगा है। ग्रामीणों को पानी के लिए दो किलोमीटर दूर एक गड्ढा खोदना पड़ा है। वे उस गड्ढे के मटमैले पानी को कपड़े से छानकर प्लास्टिक के ड्रमों में भरते हैं और बैलगाड़ी के जरिए घरों तक ले जाते हैं। यह गांव मप्र सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है। सीहोर जिले के शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इसके बावजूद यह गांव जलसंकट से जूझ रहा है। हर विधानसभा सत्र में बिसनखेड़ी जैसे सैकड़ों गांवों के जलसंकट की चर्चा होती है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जलसंकट और जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। इस बार भी विपक्ष ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि, कुछ हद तक जल आपूर्ति योजनाओं से समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन कई जगहों पर जमीनी हकीकत सरकारी दावों से अलग है।

पिछले साल 5 जुलाई 2024 को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कलेक्टर अब जल जीवन मिशन की बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करेंगे। यह बैठक हर महीने होगी। यदि इसके बाद भी कोई शिकायत रहती है, तो अधिकारी को भेजकर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। विजयवर्गीय की विधानसभा में की गई इस घोषणा के बावजूद अधिकारियों ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाए बिना ही जल जीवन मिशन की बैठकें कर लीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। साल 2024 में अनूपपुर जिले में 11 जुलाई, 22 अगस्त, 10 सितंबर, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 31 दिसंबर को जल जीवन मिशन की बैठकों में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। इस साल 15 जनवरी को डीडब्ल्यूएसएम (डिस्ट्रिक्ट वॉटर एंड सैनिटेशन मिशन) के तहत हुई बैठक में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को को बुलाया गया, लेकिन 10 फरवरी की बैठक में किसी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया। उमरिया में 2024 में 30 जुलाई और 1 अक्टूबर को बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें हुईं। छिंदवाड़ा के परासिया खंड में 21 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक हुई, जिसमें सांसद बंटी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, परासिया विधायक सोहन लाल बाल्मीक, चौरई विधायक सुजीत सिंह, सौंसर विधायक विजय चौरे, पांढुर्णा विधायक नीलेश उईके, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह और जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके मौजूद रहे। लेकिन 19 सितंबर, 10 अक्टूबर 2024 और 23 जनवरी 2025 को बिना जनप्रतिनिधियों को बुलाए ही बैठकें कर ली गईं।

वहीं कटनी में 5 दिसंबर 2024 और 5 फरवरी 2025 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें हुईं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। नरसिंहपुर में 30 जुलाई 2024 को हुई बैठक में तेंदूखेड़ा विधायक विष्णुनाथ सिंह और गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश मौजूद थे। 21 अक्टूबर 2024 को दिशा समिति की बैठक में सांसद दर्शन चौधरी, तेंदूखेड़ा और गोटेगांव विधायक शामिल हुए। मंडला में 22 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक में पीएचई मंत्री संपतिया उईके, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधायक चैन सिंह बरकड़े मौजूद थे। लेकिन 31 जनवरी 2025 की बैठक में केवल मंत्री संपतिया उईके ही उपस्थित रहीं। डिंडोरी में 15 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक में विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कुल 448 योजनाओं की समीक्षा की गई। रीवा में 4 जुलाई 2024 को जिला योजना समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। 22 अगस्त को मनगवां और सेमरिया के विधायक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। लेकिन 5 सितंबर, 6 नवंबर 2024 और 27 फरवरी 2025 को हुई बैठकों में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। निवाड़ी में निवाड़ी जिले को 100 प्रतिशत नल जल युक्त जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन लड़वारी खास ग्राम पंचायत के शिवरामपुर गांव में अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है। मऊगंज में 4 जुलाई को रीवा की जिला योजना समिति के साथ ही मऊगंज जिले की जिला योजना समिति की बैठक रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई। 22 अगस्त को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक में मनगवां, सेमरिया के विधायक प्रतिनिधि और उपमुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मौजूद रहे। छतरपुर में साल 2024 में 3 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जल जीवन मिशन की विभागीय समीक्षा बैठक हुई। साल 2025 में 9 जनवरी को और 25 जनवरी को जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक हुई। टीकमगढ़ में 24 अक्टूबर 2024-जिला योजना समिति, जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक हुई। 21 जनवरी 2025 को जिला योजना समिति की बैठक हुई। सागर में साल 2024 में 5 अगस्त, 8 नवंबर और इस साल 25 जनवरी को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें हुई।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

> आतंकवाद को पोसने और पालने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद से त्रस्त है। भारत सहित विश्वभर में आतंकी गतिविधियों का संचालन करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह दी गई है, लेकिन अब एक-एक करके आतंकी आकाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है।

आतंकी आकाओं में अज्ञात किलर का खौफ

पाकिस्तान में लोग इस खौफ को अब कई नाम से जानने लगे हैं। अज्ञात किलर, अननोन गनमैन या साइलेंट किलर कहें या फिर इसे मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारी या फिर फिदायीन दस्ता का नाम दिया जाए। पाकिस्तान में चोटी के मौलानाओं को निशाना बनाने वाले इस रहस्यमयी फिगर ने पाकिस्तान में सिहरन पैदा कर दी है। ये कौन है, किसके लिए काम करता है, कोई नहीं जानता। लेकिन इसका वार इतना घातक है कि इसकी चर्चा ही पाकिस्तान में झुरझुरी पैदा कर देती है। इन अज्ञात बंदूकधारियों ने कई ऐसे लोगों को ठिकाने लगाया है जो घोषित रूप से भारत विरोधी थे। मसलन जहूर मिस्त्री नाम का आतंकवादी, जो दिसंबर 1999 में आईसी-814 प्लेन हाइजैकिंग में शामिल पांच अपहरणकर्ताओं में से एक था। 7 मार्च 2022 को इसकी हत्या दो हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने कराची में कर दी थी।

पाकिस्तान में पिछले एक-डेढ़ साल में भारत के कई विरोधियों को इन अज्ञात बंदूकधारियों ने ठिकाने लगाया है। इनमें कुछ बड़े नाम ख्वाजा शाहिद, मौलाना रहीमुल्ला तारीक, लखबीर सिंह रोडे, जियाउर रहमान, बशीर अहमद पीर, हंजला अदनान शामिल हैं। यूं तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन कुछ दिनों की चुप्पी के बाद पाकिस्तान में अज्ञात किलर का खौफ फिर से शुरू हो गया है। 25 दिनों में ही इन अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के 5 चोटी के मौलानाओं को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें वैसे लोग शामिल थे जिन्होंने भारत के रिटायर्ड नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी में अहम रोल निभाया था।

पाकिस्तान में हाल ही में हुई हत्याओं में मौलाना हमीदुल हक हक्कानी सबसे हाई प्रोफाइल फिगर है। 57 साल का मौलाना हमीदुल हक हक्कानी 28 फरवरी 2025 को खैबर पख्तुनखवा में तब मारा गया था जब एक मदरसे में जुमे की नमाज के बाद लोग मौजूद थे। इसी दौरान एक फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया था। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी दार उल उलूम हक्कानिया सेमिनारी का चीफ था। यह मदरसा लंबे समय से तालिबान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके कई सदस्यों ने, जिनमें समूह का संस्थापक मुल्ला उमर भी शामिल है, यहीं प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बीबीसी ने इसे अपने एक लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा है। मौलाना हमीदुल हक हक्कानी प्रभावशाली पाकिस्तानी मौलवी मौलाना समी उल-हक के बेटे थे, जिन्हें व्यापक रूप से तालिबान के पिता के रूप में जाना जाता है। 2018 में हमीदुल हक हक्कानी के पिता की भी हत्या हो गई थी। इसके बाद वे मदरसा के कुलपति बने और धार्मिक जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम राजनीतिक दल के एक गुट के प्रमुख बने। हक के पिता के मुल्ला उमर सहित अफगान तालिबान के नेतृत्व के साथ लंबे समय से संबंध थे।

हत्याओं का पैटर्न

दरअसल 2021-22 से ही पाकिस्तान में कई आतंकवादी कमांडरों और धार्मिक नेताओं की हत्याएं हुई हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के सदस्य शामिल हैं। इन हत्याओं का पैटर्न आमतौर पर एक समान है। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारी आतंकवादियों या नेताओं को नजदीक से गोली मारकर फरार हो जाते हैं और जांच एजेंसियों को कुछ पता नहीं चल पाता है। इन हत्याओं का पैटर्न एक संगठित अभियान की ओर इशारा करता है, लेकिन इसके पीछे कौन है, यह स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियां 2 साल से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान इन हत्याओं का आरोप भारत पर लगाता रहता है। लेकिन आज तक उसने कभी भी जुबानी जमा के अलावा कोई सबूत नहीं दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को मनगढंत, बेबुनियाद और बकवास बताया है।

28 फरवरी के बाद एक और शुक्रवार आया। तारीख 7 मार्च 2025। एक हाई प्रोफाइल किलिंग से पाकिस्तान हिल गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने 7 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के तुरबत में मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने मुफ्ती शाह मीर पर गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मानव तस्करी में संलिप्त माने जाने वाले मीर, तरावीह (रात) की नमाज के बाद स्थानीय मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और नजदीक से उन्हें कई बार गोली मार दी। मुफ्ती शाह मीर के बारे में जो सबसे अहम बात है वो यह है कि उसने भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को किडनैप करने में आईएसआई की मदद की थी। मानव और हथियार तस्कर मीर मुफ्ती की आड़ में काम करता था और वह इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम का सदस्य था।

अगले शुक्रवार को पाकिस्तान में एक और मौलाना अज्ञात हमलावरों के निशाने पर था। तारीख थी 14 मार्च 2025। पाकिस्तान की पुलिस ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में शुक्रवार को एक मस्जिद में विस्फोट हुआ, जिसमें जमीयत उलेमा इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के जिला अमीर सहित कम से कम चार लोग घायल हो गए। दक्षिण वजीरिस्तान के जिला पुलिस प्रमुख डीपीओ आसिफ बहादुर ने बताया कि माना जा रहा है कि जेयूआई-एफ के नेता अब्दुल्ला नदीम विस्फोट

का निशाना था। उसे गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को इस हमले की कोई जानकारी नहीं है।

जुमे के महज एक दिन बाद एक और हाई प्रोफाइल किलिंग पाकिस्तान में हुई। अज्ञात बंदूकधारियों का अगला टारगेट एक खूंखार आतंकवादी और भारत में कई केस का वांटेड अबू कताल। लश्कर-ए-तैयबा टॉप आतंकवादी अबू कताल, जिसे कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, को शनिवार रात पाकिस्तान के झेलम सिंध में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता 2002-03 से शुरू होती है, जब उसने भारत में घुसपैठ की और पुंछ-राजौरी रेंज में काम किया। एनआईए ने उसे वांटेड घोषित किया था। आर्मी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये आतंकी बड़ा सिरदर्द बन गया था। आतंकी अबु कताल, हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। कई रिपोर्ट में ये भी खबर आई थी कि हाफिज सईद पर भी उस रोज हमला हुआ था। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि आईएसआई ने इस हमले के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान के क्वेटा में एक और हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) के एक वरिष्ठ नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की रविवार (16 मार्च) रात को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। मुफ्ती अब्दुल बाकी मस्जिद जा रहा था, तभी उस पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। क्वेटा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह से 28 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच पाकिस्तान में 5 बड़े मौलानाओं की हत्या हो चुकी है।

पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि उसके पास भारत के खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत भी मिल जाए तो भी अपनी जनता के सामने यह बताने से हिचकेगा कि भारत जैसा देश उसके यहां हत्याएं करा रहा है। पाकिस्तान की सरकार हो या फौज, अपनी जनता के बीच यही कहते हैं कि हमने भारत से कभी कोई युद्ध नहीं हारा। पाकिस्तान अपनी जनता के बीच यही कहता रहा है कि हमने मुंबई हमले और संसद पर हमले करके भारत को थर्रा दिया था। कारगिल युद्ध करके भारत को छकाया। हम भारत के हिस्से का आधा कश्मीर अपने पास रखे हुए हैं। इस तरह की बात करने वाली सरकार और आर्मी किस मुंह से अपने देश में हुए हमले का आरोप भारत पर मढ़ सकेगी? पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए भारत को समर्थन देती रही है। इन संगठनों के कई शीर्ष कमांडर पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) में मारे गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के सामने यह भी संकट है कि दुनिया के सामने वह कैसे स्वीकार करेगा कि ये आतंकी उसके संरक्षण में रह रहे थे।

पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसे कई इस्लामी देशों से लोन मिलना बंद हो चुका है। पाकिस्तान लगातार आईएमएफ से और कर्ज लेने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान भारत पर इस तरह का आरोप लगाता है तो भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोपों को साबित कर देगा। पाक पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। अगर वह इन हत्याओं को लेकर ज्यादा हंगामा करता है, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह साबित हो सकता है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को पनाह दे रहा है। अगर पाकिस्तान एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होता है तो जाहिर है कि कर्ज मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

2024 में भारतीय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और मजबूत सरकार बनी है, जिसने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक (2016) और बालाकोट एयर स्ट्राइक (2019) जैसे कदम उठाए थे। पाकिस्तान जानता है कि अगर वह इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएगा, तो भारत से कड़ा जवाब मिल सकता है, जिससे उसकी सुरक्षा और कूटनीति पर असर पड़ेगा। दूसरे भारत के साथ आज रूस और अमेरिका दोनों ही हैं। चीन भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मामले में सामने नहीं आएगा। चीन के बहुत से हित भारत से जुड़े हुए हैं। एक समय था कि ऐसे मौकों पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका खुलकर भारत के विरोध में आ जाता था, पर आज स्थितियां बदल चुकी हैं।

कनाडा और पाकिस्तान की स्थिति में फर्क है। कनाडा 5 आई का मेंबर है। कनाडा की बात पर विश्व के सबसे ताकतवर पश्चिमी देश उसी की भाषा में बोलने को मजबूर हो जाते हैं। कनाडा की आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान जैसी नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी तत्व खुलेआम काम कर रहे हैं और वहां की सरकार ने उन्हें सहानुभूति दी है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, क्योंकि वे भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति उलटी है। अगर वह भारत पर आरोप लगाएगा, तो दुनिया उससे पूछेगी कि ये आतंकी वहां कर क्या रहे थे?

● श्याम सिंह सिकरवार

बोलने से ज्यादा चुप रहने की रणनीति पर काम कर रहे हैं शरीफ

पाकिस्तान की सरकार अल्पमत वाली सरकार है, जो सेना की इच्छा पर चल रही है। पाकिस्तान में सही बोलने वालों के साथ क्या सुलूक होता है यह शाहबाज शरीफ भी जानते हैं। इसलिए वह बोलने से ज्यादा चुप रहने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसी तरह कुर्सी बचाकर सरकार चलाने की रणनीति ही उनके लिए बेहतर भी है। शरीफ जानते हैं कि ज्यादा महत्वाकांक्षा का मतलब पाकिस्तान में जेल या फांसी पर चढ़ना होता है। अगर वह खुलकर भारत के खिलाफ आरोप लगाएंगे, तो उसे अपने आतंकियों को समर्थन देने की सफाई भी देनी पड़ेगी। इसलिए, पाकिस्तान सरकार इन हत्याओं को कभी गैंगवार, कभी आंतरिक संघर्ष तो कभी अनजान हमलावरों की करतूत बताकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है।

जंगलों में समर अलर्ट

मप्र के जंगलों में गर्मी के मौसम के दौरान बाघों के बीच वर्चस्व की जंग और तेज हो जाती है। इस बार ऐसा न होने पाए, इसकी तैयारी में वन प्रबंधन जुटा हुआ है। इसके लिए जंगलों में समर अलर्ट घोषित किया गया है और जंगल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मौसम में परिवर्तन के साथ न सिर्फ जंगल के स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है, बल्कि वन्य प्राणियों के विचरण में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि उनकी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यूं तो जंगलों में पानी के संकट को दूर करने के लिए अब सोलर पावर पंप का उपयोग किया जाने लगा है। प्रदेश के छह टाइगर रिजर्व में करीब साढ़े तीन सौ सोलर पावर पंप के माध्यम से वाटर होल भरे जाते हैं। जबकि प्राकृतिक जल स्रोतों को भी संरक्षित किया जाता है। इसके बाद भी पानी की कमी कहीं न कहीं गर्मी के दिनों में उत्पन्न हो जाती है और ज्यादा उम्र के बाघ पानी की तलाश में अपना क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान उनका दूसरे बाघों से आमना-सामना हो जाता है।

महुआ का सीजन होने के कारण जंगल के बाहरी हिस्सों में गांवों के नजदीक अक्सर लोग आग लगा देते हैं। आग के कारण बफर जोन में सक्रिय बूढ़े और कमजोर बाघ उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घने जंगल के अंदर पहुंचते ही फिर उनका सामना जवान और ताकतवर बाघों से होता है और इस तरह वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती है। बांधवगढ़ के खितौली रेंज में इन दिनों डी-वन बाघ सक्रिय हो गया है जो दूसरे बाघों को इस तरफ टिकने नहीं दे रहा है। छोटा भीम के घायल होने के बाद जबसे उसे भोपाल के वन विहार शिफ्ट किया गया है, तबसे उसके संपूर्ण क्षेत्र में डी-वन का कब्जा हो चुका है। डी-वन इन दिनों अपनी प्राइम ऐज में है। ऐसे में बाघ लगातार अपनी टैरिटरी बढ़ाता है। हाल ही में इसी बाघ ने बाघिन तारा के दो शावकों को मौत के घाट उतार दिया था। यहां का एक दूसरा बाघ पुजारी भी अब लगभग दस साल का हो चुका है। स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वर्चस्व की जंग तेज हो सकती है। जंगलों में गश्त और सुरक्षा श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई है। पानी की कमी नहीं होने पाए इसके इंतजाम पर नजर रख रहे हैं। जीरो फायर मिशन के तहत जंगल में आग नहीं लगे इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में बाघों की आपसी दूरी सामान्य से कम है वहां हाथी दल के माध्यम से नजर रखी जा रही है।

चीतों को सुरक्षित रखने की चुनौती

कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में चीतों की संख्या अब 17 हो गई है, जो पार्क प्रबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है। 10 चीते अहेरा पर्यटन जोन के खजूरी जंगल में हैं, जहां इनका आमने-सामने आना टैरिटरी फाइट का कारण बन सकता है। इसके अलावा, दूसरे जानवरों से टकराव का भी खतरा है। पार्क के आसपास सक्रिय शिकारियों के खतरे का भी डर है। वन विभाग की टीमों ने हाल ही में दो अलग-अलग कार्रवाईयों में तीन शिकारी और एक महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। हालांकि, जैसे-जैसे जंगल में ये चीते दौड़ते हुए घूम रहे हैं, यह संभावना भी हो सकती है कि वे शिकारियों के जाल में फंस जाएं। इसी वजह से पार्क प्रबंधन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और मॉनीटरिंग टीम को अलर्ट किया है। टैरिटरी फाइट का डर दोनों ग्रुप में शामिल दो-दो नर शावकों को लेकर है, क्योंकि नर चीतों के बीच ही टैरिटरी फाइट होती है। हालांकि पार्क प्रबंधन इस बात को लेकर राहत में है कि दोनों समूह का नेतृत्व मादा चीता कर रही हैं, जिनके बीच अमूमन टैरिटरी को लेकर फाइट नहीं होती। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर के डीएफओ आर थिरुकुराल का कहना है कि अभी सभी चीते दूर-दूर हैं। टकराव जैसी स्थिति नहीं है। मादा आपस में नहीं लड़ती हैं। गामिनी और उसके चारों शावकों के दिन अच्छे गुजरे हैं।

रातापानी के जंगल में गर्मी के मौसम में जंगल के प्राकृतिक जल स्रोत सूखने से वन्य प्राणी रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे जंगल से सटे गांवों में बाघ और अन्य जंगली जानवरों के आने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग ने इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। विभाग ने जंगल में 30 सौंसर (जल कुंड) बनवाए हैं और 100 झिरियों की सफाई की है। डीएफओ हेमंत रैकवार के अनुसार, इन जल स्रोतों से वन्य जीवों को जंगल के अंदर ही पानी मिल सकेगा। विभाग हर दो दिन में टैंकर से इन सौंसर में पानी भरवा रहा है। रेंजर कार्तिकेय शुक्ला ने बताया कि रातापानी की 4 और डिविजन की 10 रेंजों के 152 बीटों में ये सौंसर बनाए गए हैं। सौंसर बनाने के लिए जमीन में कड़ाई की तरह गोल गड्ढा खोदा जाता है। इसे सीमेंट-कांक्रीट से पक्का किया जाता है। इससे न तो किनारे की मिट्टी बहती है और न ही पानी जमीन में सोखता है। औबेदुल्लागंज वन डिवीजन के चिकलोद रेंज की भोजपुर बीट में पिछले 15 दिनों से दो बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। जो कि लगातार गोवंश को अपना शिकार बना रहे हैं। 19 मार्च को बाघ ने भोजपुर स्थित विद्यासागर गौशाला में घुसकर एक बछिया को अपना शिकार बनाया। यह घटना सुबह 8:30 की बताई जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र के पशुपालकों के साथ आमजन भी दहशत में है। पिछले पांच दिनों में बाघ ने इस गौशाला में दूसरी बार गोवंश को अपना शिकार बनाया। इसके पहले बीते सप्ताह टाइगर ने एक बछड़े पर हमला कर मार दिया था। घटना के बाद सूचना मिलने पर एसडीम और तहसीलदार के साथ वन विभाग की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची।

प्रदेश में 30.72 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30 प्रतिशत है। यहां कुल वन क्षेत्र 94 हजार 689 वर्ग किलोमीटर (94 लाख 68 हजार 900 हेक्टेयर) है। प्रदेश में 24 वाइल्डलाइफ सेंचुरी, 11 नेशनल पार्क और 9 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी टाईगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में लैंडमार्क साबित हो रहा है। साथ ही, नामीबिया से आए चीतों के लिए ये प्रदेश सबसे महफूज माना गया है। मप्र को बाघ एवं तेंदुआ स्टेट का सम्मान प्राप्त है।

● विकास दुबे

गुलाब-गेंदा फ्लॉवर नहीं फायर है...!

बुंदेलखंड के किसान फूलों की खेती को लगातार लाभ का धंधा बना रहे हैं। तभी तो बुंदेलखंड में फूलों की जमकर पैदावारी हो रही है। बुंदेलखंड के इलाकों में खिले फूलों ने महाकुंभ में तो अपनी खुशबू बिखेरी ही, साथ ही बागेश्वर धाम सहित देश के कई राज्यों में अपनी महक छोड़ रहे हैं। जिले का फूल रोजाना मप्र, उप्र, बिहार, राजस्थान, बागेश्वरधाम पर बिकने के लिए जाता है, जिससे किसानों को घर बैठे कम लागत में अच्छा मुनाफा हो रहा है। सरकार भी किसानों को फूलों की खेती पर सब्सिडी दे रही है। ताकि बुंदेलखंड के किसान मजबूत हो सकें। सूखे बुंदेलखंड के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां किसान पानी की समस्या और खेती को लेकर काफी परेशान रहते हैं। इसके बाद अब किसान कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की ओर रुख कर रहें हैं। जिससे वे लाखों कमा रहें हैं। जिले के किसान कई प्रकार के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे जिले में लगातार फूलों की बंपर पैदावार हो रही है। जिले के किसानों के चेहरे भी फूलों की तरह खिल रहे हैं।

बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में 65 हेक्टेयर के रकबे में फूलों की खेती की जाती है। इस साल किसानों ने महाकुंभ आयोजन को देखते हुए गेंदा और गुलाब के फूलों की बंपर पैदावार की। किसान एक एकड़ की खेती में 60 से 70 हजार रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। छतरपुर जिले में गेंदा और गुलाब के फूल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। करीब 3 टन प्रति सप्ताह गेंदा और गुलाब की मांग रहती है। जो फूल पहले अन्य जगह से आते थे लेकिन अब जिले के किसान ही डिमांड पूरी कर घर बैठे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान विभाग खेती करने वाले किसानों को प्रमोट भी कर रहा है। छतरपुर जिले में फूलों के अच्छे उत्पादन को देखते हुए 30 से ज्यादा किसान इसकी खेती कर रहे हैं। चंद्रपुरा निवासी किसान ने बताया कि फूलों की खेती में लागत से तीन गुना ज्यादा मुनाफा होता है। जिस कारण किसानों का मन भी फूलों की खेती की ओर लगा हुआ है। गेंदे की खेती करने की शुरुआत खजुराहो क्षेत्र के किसानों ने की थी। जैसे-जैसे किसानों ने इसमें मुनाफा देखा तो अब जिला मुख्यालय से लगे गांवों के किसान अपने खेत में नियमित रूप से गेंदा और गुलाब की खेती कर रहे हैं। अब जिले के फूल विक्रेताओं और जरूरतमंद लोगों को बाहर से फूल नहीं खरीदने पड़ रहे हैं। उन्हें जिले में ही पर्याप्त मात्रा में फूल मिल जाते हैं। बुंदेलखंड के फूलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। जिले के फूल बागेश्वर धाम, उप्र, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में जाते हैं। गत माह महाकुंभ आयोजन में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी हुई थी। वह भी अधिकांश बुंदेलखंड के फूल ही थे। किसानों के लिए फायदे का धंधा बनी फूलों की खेती पर कीटों का प्रभाव बेअसर रहता है। फूल की खेती कर रहे किसान हरिओम पटेल ने बताया कि गेंदे के फूलों पर आमतौर पर सब्जियों की अपेक्षा रोग कीट कम आते हैं, जिससे फूलों को नुकसान नहीं पहुंचता। उन्होंने बताया कि, इल्ली और मकड़ी से बचाव आवश्यक होता है जो काफी आसान है। जब फूल आते हैं तो तुरंत तुड़ाई की जाती है। बाजार में एवरेज रेट 25-30 रुपए किलो रहता है। जो लागत खर्च से तीन गुना होता है। इससे किसानों को अच्छी खासी इनकम हो जाती है।

त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान मार्केट में फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह के सीजन में किसानों को अच्छी कीमत मिलती है और उन्हें अधिक मुनाफा होता है। वहीं, फूलों की खेती में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं रहता है। फूलों की बिक्री के सीजन में उम्मीद से ज्यादा फसल की कीमत मिल जाती है। इसलिए जिले के किसानों के लिए फूल की खेती लाभ का धंधा बनती जा रही है। वहीं, छतरपुर से लगे आटारन गांव के निवासी किसान रामरतन पटेल ने बताया कि फूलों की खेती से रोजाना 1000 से 1500 तक के फूल बेच देते हैं। फूलों की खेती को लगभग ढाई माह लगता है और फूल आना शुरू हो जाता है। पूरे साल फूलों की खेती होती है। वहीं, छतरपुर के फूल व्यापारी बाला प्रसाद चौरसिया बताते हैं, छतरपुर का फूल बागेश्वर धाम जाता है। इससे पहले जब महाकुंभ चल रहा था, तो वहां भी जा रहा था। घर बैठे अच्छी कमाई हो रही है। ऑनलाइन माल प्रयागराज सहित सभी धार्मिक स्थानों पर जाता है। इतनी मांग है कि माल दे नहीं पाते।

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल कहते हैं कि छतरपुर के किसान घर बैठे फूलों की खेती से लाभ कमा रहे हैं। जिले का किसान समृद्ध हो रहा है। सरकार द्वारा खेती के लिए अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही है। समय-समय पर जानकारी दी जाती है, कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। बाहर के किसानों से खेती की नई-नई टेक्नोलॉजी भी जिले के किसानों को बताई जाती है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए कृषि उद्यानिकी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। उद्यानिकी अधिकारी जगदीश सिंह मुजाल्दा ने बताया कि जिले में 65 हेक्टेयर के रकबे में फूलों की खेती की जाती है। जिले का फूल इस समय बागेश्वर धाम, उप्र, बिहार और मप्र के कई जिलों में जाता है। वहीं, फूलों की खेती के लिए सरकार 10 हजार रुपए हेक्टेयर सामान्य वर्ग के लिए और 12 हजार रुपये एससी-एसटी वर्ग के लिए सब्सिडी भी दे रही है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बिना मिट्टी, पानी में लहलहाएंगी फसलें

बुंदेलखंड में खेती को लेकर तरह-तरह के इनोवेशन किए जाते हैं। इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग बुंदेलखड में हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बिना मिट्टी के पानी के जरिए खेती की तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहा जाता है। वैसे तो खेती का ये तरीका उन इलाकों में ज्यादा उपयोग होता है। जहां खेती योग्य जमीन नहीं है या फिर बड़े शहरों में लोग अपने किचन या टैरेस गार्डन में इस तकनीक से खेती करते हैं। अब बुंदेलखंड में इस नई तकनीक से किसानों को अवगत कराने उद्यानिकी विभाग ने पहल की है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती को सरल शब्दों में समझें, तो ये खेती मिट्टी की जगह पानी के जरिए की जाती है। इस तकनीक का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है। जहां सीमित जमीन है या जमीन उपलब्ध नहीं है या फिर खेती योग्य जमीन नहीं है। हमारे देश में महानगरों में बागवानी के शौकीन लोग अपने घरों में या टैरेस में इस तकनीक से खेती करते हैं। इसे एक्वाकल्चर और टैंक फार्मिंग भी कहते हैं।

मप्र का बजट सत्र छोटा... काम पूरा

अपनों के निशाने पर रही सरकार

मप्र की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र यानि बजट सत्र में भले ही 9 बैठकें हुईं, लेकिन इस दौरान जिस तरह सदन की कार्यवाही बिना हंगामे और बिना गतिरोध के चली, उससे एक बार फिर से मप्र की गरिमा लौटी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के संचालन के लिए जो नवाचार गढ़े हैं, उसका ही असर है कि 17 साल बाद मप्र विधानसभा का सदन चलने का रिकॉर्ड बना है।

● **राजेंद्र आगाल**

मप्र विधानसभा का सबसे सीमित बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक तय समय के अनुसार चला। इस सत्र की विशेषता यह रही कि सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूरी शिद्दत के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लिया। हालांकि इस सीमित सत्र में भी कई प्रकार की असहजता देखने को मिली। सत्ताधारी दल के जहां कुछ विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस एक ही मुद्दे पर बटी नजर आई। बजट सत्र भले ही छोटा था, लेकिन इस दौरान जिस तरह विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए, उससे मप्र विधानसभा एक बार फिर 21 साल पुरानी परिपाटी पर लौटती नजर आ रही है। 9 दिन के इस सत्र में कुल 2849 सवाल विधायकों द्वारा पूछे गए, जिनमें से 1387 सवाल भाजपा, 1431 सवाल कांग्रेस और 31 सवाल भारत आदिवासी पार्टी ने पूछे हैं। इस तरह सत्र में सरकार को घेरने के लिए सत्तापक्ष के साथ विपक्ष ने भी दम लगाया।

16वीं विधानसभा के 9 दिनों के पंचम सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही 55 घंटे तक चली। यानि सदन की कार्यवाही तय समय तक चलती रही। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से लेकर 2025 के मानसून सत्र तक पिछले 21 साल में मप्र विधानसभा की 119 बैठकें आयोजित की गईं। लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से मात्र 79 दिन ही विधानसभा चल सकी है। अगर बजट सत्र की बात करें तो भले ही यह सत्र सीमित रहा हो लेकिन संदेश सत्ताधारी दल और विपक्ष को जरूर दे गया। विपक्ष का सर्वाधिक जोर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने का रहा। खासकर परिवहन घोटाले का मुद्दा किसी न किसी तरह से उठाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का जोर अलग-अलग रहा। जहां सदन के अंदर और सदन के बाहर परिवहन घोटाले का मुद्दा उठाते समय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पूरा फोकस पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत उनके परिजनों और सहयोगियों पर केंद्रित रहा, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के निशाने पर पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे। शायद यही कारण था कि मंत्री गोविंद सिंह के निशाने पर उमंग सिंघार रहे, वही भूपेंद्र सिंह के निशाने पर हेमंत कटारे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुछ महीने पहले चेक पोस्टों पर अवैध वसूली का मुद्दा जरूर उठाया था, लेकिन बाद में आक्रामकता नजर नहीं आई। हालांकि वे मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा भिखारी कहे जाने वाले बयान पर जरूर अपने तेवर तल्ख करते रहे और पूरे प्रदेश में इसका विरोध जताने का प्रयास भी किया।

अपनों ने जमकर घेरा

मप्र विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने परिवहन घोटाला, बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरा तो सत्तापक्ष के विधायकों ने भी सरकार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजनाओं में लेटलतीफी, धान उपार्जन घोटाले और सिंहस्थ के लिए अधिगृहीत की जाने वाली किसानों की जमीन के मुद्दे पर सत्तापक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे। इनका जवाब देने में विभागीय मंत्री असहज हो गए। इस दौरान भाजपा के कई विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा। जबलपुर की पाटन सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने धान उपार्जन घोटाले पर अपनी ही सरकार और सिस्टम को घेरा। जबलपुर में धान खरीदी में 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है। विश्नोई ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से पूछा कि घोटाले को अंजाम देने के लिए फर्जी आरओ (रिलीज ऑर्डर) जारी किए गए। जिन ट्रकों से धान का परिवहन हुआ, वो टोल नाकों से

किस विभाग से कितने सवाल

विभाग	सवाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	245
राजस्व	215
नगरीय विकास एवं आवास	183
स्कूल शिक्षा	177
लोक निर्माण	98
आनंद	1
संसदीय कार्य	1
लोक संपत्ति प्रंधन	3
भोपाल गैस त्रासदी	4

मुख्यमंत्री के विभाग

जीएडी	82
गृह एवं जेल	144
उद्योग	42
वन	93
जनसंपर्क	8
नर्मदा घाटी विकास	22
विमानन	6
खनिज संपदा	74
लोक सेवा प्रबंधन	7
प्रवासी भारतीय	0

गुजरकर ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना जैसे शहरों में गए। इसकी जांच आसानी से हो सकती है। एक माह से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है?

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की गड़बड़ियां सामने आएंगी, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विश्नोई ने तीन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मिलिंग के लिए व्यापारी धान उठाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मिलिंग चार्ज और प्रोत्साहन राशि लेते हैं और धान वहीं बेचकर चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है? धान या किसी दूसरी जिंस का उपार्जन सहकारी समितियों के जरिए होता है। इनमें से कई कर्मचारियों की वजह से डिफॉल्टर हो गई हैं। उन्हीं कर्मचारियों को फिर से खरीदी के काम में नियुक्त किया जाता है। किसानों को धान का भुगतान कब तक मिलेगा? जिन कम्प्यूटर ऑपरेटर्स ने गड़बड़ी की है, क्या उनका पता लगाया जाएगा?

भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये तक कहा कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, कुशवाह ने कहा कि भिंड में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक प्रदीप जैन की लापरवाही से बिजली कटौती हो रही है। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पर्याप्त बिजली दी जा रही है। तोमर के इस जवाब पर कुशवाह बोले कि मंत्रीजी आप भ्रष्ट अधिकारी को बचा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर जांच कराई जानी चाहिए। वहीं, कुशवाह का साथ देते हुए भाजपा विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि बिजली विभाग के अफसर हमेशा गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति रखते हैं। सवाल पूछने पर गलत जानकारी देते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि सत्तापक्ष का विधायक आवाज उठा रहा है, इसलिए इस मामले में कार्यवाही होनी चाहिए। विपक्ष की बात तो सरकार सुनती नहीं है। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विधायक की भावनाओं के आधार पर कार्यवाही होगी, किसी भी हालत में अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने उनके विधानसभा क्षेत्र के नयागांव में नया गर्ल्स कॉलेज खोलने के मुद्दे पर उच्च शिक्षा विभाग के

पूर्व मुख्यमंत्री सहित 31 विधायकों ने एक भी सवाल नहीं किया

मप्र विधानसभा के बजट सत्र में इस बार माननीय की उदासीनता दिखाई दी। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 31 विधायकों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। वहीं 15 ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया। मप्र विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 24 मार्च को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। 10 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र में कुल 9 बैठकें हुई। इस बार सदन में माननीयों की उदासीनता देखने को मिली। बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सहित 31 विधायकों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। 15 विधायकों ने किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सबसे ज्यादा 32 सवाल पूछकर टॉप पर रहे। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी 32 साल पूछकर सेकंड टॉपर बने। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 30 सवाल पूछे और भाजपा की तरफ से टॉपर बने।

मंत्री इंदर सिंह परमार को घेरा। कुशवाह ने ये तक कहा कि सरकार बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 मार्च 2024 को भिंड में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वादा किया था कि नया गांव में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा। लेकिन एक साल बाद भी प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई।

सिंहस्थ पर चर्चा विवादों में

उज्जैन में अप्रैल-मई 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण पर आलोट के भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मालवीय ने कहा कि उज्जैन का किसान डरा हुआ है। उसकी जमीन छीनी जा रही है। इस पर तराना के कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मालवीय का समर्थन किया। मगर, उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने आपत्ति दर्ज की। मालवीय के इस मुद्दे से सरकार असहज नजर आई। उज्जैन में सहस्त्र जमीन अधिकरण के मामले को विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरने के 2 दिन बाद ही आलोट के भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय को नोटिस जारी किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की ओर से जारी हुए नोटिस में लिखा गया है कि पिछले कुछ समय से आपके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सरकार की आलोचना की जा रही है एवं आपके वक्तव्य और कृतियों से लगातार पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। आपके इस आचरण से सरकार पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। चिंतामणि मालवीय के ताजा बयानों और कृतियों की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।

बजट पर बोलते हुए आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा था कि मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए उज्जैन सेहत के लिए रखे हैं। उज्जैन उन पर अभिमान करता है। उज्जैन उनको अपना नेता मानता है। उज्जैन को गर्व है कि मप्र का मुख्यमंत्री उज्जैन से है, लेकिन आज उज्जैन का किसान बहुत डरा और परेशान है क्योंकि सहस्त्र के नाम पर उसकी जमीन पहले 3 से 6 महीने के लिए अधिकृत की जाती थी लेकिन आज उन्हें स्थायी अधिकरण का नोटिस दिया गया है। पता नहीं किस अधिकारी ने यह विचार रखा है कि आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक नगरी किसी सिटी में नहीं रहती, वह तो त्याग करने वाले लोगों से होती है। हम कांक्रीट के भवन बनाकर आध्यात्मिक सिटी नहीं बना सकते है। उन्होंने कहा कि सहस्त्र का मुख्य विचार ही तंबू में है। क्या हम 4000 हेक्टेयर भूमि में कांक्रीट के भवन बनाएंगे, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, सन्यास ग्रहण कर लिया है। घर परिवार पैसा संपत्ति त्याग दी, उनको आप भवनों में बिठाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता

16वीं विधानसभा में दिखी माननीयों की गरिमा

मप्र की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र यानि बजट सत्र में भले ही 9 बैठकें हुईं, लेकिन इस दौरान जिस तरह सदन की कार्यवाही बिना हंगामे और बिना गतिरोध के चली, उससे एक बार फिर से मप्र की गरिमा लौटी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के संचालन के लिए जो नवाचार गढ़े हैं, उसका ही असर है कि 17 साल बाद मप्र विधानसभा का सदन चलने का रिकॉर्ड बना है। मप्र विधानसभा का बजट सत्र भले ही छोटा था, लेकिन इस दौरान जिस तरह विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए, उससे मप्र विधानसभा एक बार फिर 21 साल पुरानी परिपाटी पर लौटती नजर आ रही है। गौरतलब है कि 2023 में जब सर्वसम्मति से नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, तभी उन्होंने संकेत दे दिया था कि विधानसभा सत्र तय समय के अनुसार पूरे समय चलाया जाएगा। अगर मानसून सत्र को छोड़ दिया जाए तो 16वीं विधानसभा में अब तक हुए सारे सत्र शांति और समन्वय के साथ चले हैं। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी की है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य यही होता है कि लोकतंत्र समृद्ध हो और संसदीय कार्यप्रणाली प्रदेश और उसकी जनता की प्रगति तथा उन्नति का माध्यम बने। विधानसभा में सकारात्मक और अनुशासित वातावरण के लिए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस सूझबूझ, धैर्य और संतुलन के साथ इस सत्र का संचालन किया, वह अभूतपूर्व है। आमतौर पर विधानसभा की कार्यवाही राजनीतिक टकराव और तीखी बहसों के चलते बाधित होती रही है, लेकिन इस बार की कार्यवाही एक शांत, व्यवस्थित और सार्थक संवाद का मंच बन गई। नरेंद्र सिंह तोमर न केवल एक अनुभवी और सुलझे हुए राजनेता के रूप में पहचाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने अध्यक्ष पद की इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। उनकी नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक समझ, संवाद कौशल और निष्पक्ष रवैये ने विधानसभा में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया, जिससे सत्र की सभी बैठकें बिना किसी अवरोध के संपन्न हो सकीं। यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर के सुविचारित नेतृत्व और कुशल रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है।

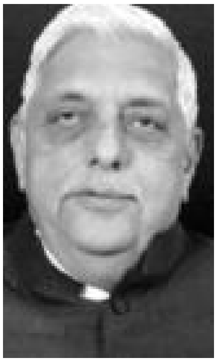

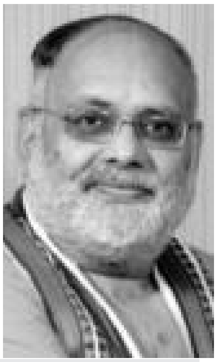

है कि यह बहुत गलत हो जाएगा। एक अन्य मामले में गृह विभाग के प्रश्नों के उत्तर देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल विधानसभा में रोते नजर आए। कुछ अन्य विधायकों ने भी ऐसे प्रश्न लगाए थे या उठाए थे जिससे सरकार को असहजता महसूस हुई।

सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त किसानों को कब मिलेगी? विदिशा जिले के कितने किसानों को दोनों योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की शिकायतें की गई हैं? उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? इस पर सरकार ने जवाब दिया कि योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की 19,481 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मिली थी। इनमें से सिर्फ 776 शिकायतों का निराकरण होना शेष है। 663 शिकायतें फरवरी माह में दर्ज हुई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। शर्मा ने ग्राम पंचायतों की जांच, अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता, नगर निगमों की सड़कों की जांच और वनों की अवैध कटाई को लेकर भी सरकार को घेरा।

रीति पाठक ने मंत्री को घेरा

सीधी से भाजपा विधायक रीति पाठक ने कहा कि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को रीवा के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तरह सीधी और पूरे प्रदेश के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जिला चिकित्सालय, सीधी में मेडिकल एक्सपर्ट के 37 पद हैं। इनमें से 25 खाली हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के 26 पदों में से 6 पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अच्छे से चल सकती हैं। इस पर मंत्री ने कहा- सुधार के लिए प्रयास जारी हैं। जहां दिक्कत होती है, वहां एनएचएम के माध्यम से सेवाएं दिलाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही पद भर जाएंगे, डॉक्टर की पोस्टिंग की जाएगी।

सीधी में मेडिकल कॉलेज के लिए पीपीपी मोड पर निर्माण कार्य करने अब तक कोई निविदा नहीं जारी होने का मामला उठाते हुए विधायक रीति पाठक ने कहा कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि सीधी में विरोधाभास बहुत है इसलिए सरकार को खुद यहां मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए काम करना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है। सरकार पीपीपी मोड को तेजी से बढ़ा रही है। 30 मार्च तक दूसरी बार ऑफर आएगा, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि मैं विधायक पाठक का समर्थन करता हूं। सीधी एक पिछड़ा और आदिवासी जिला है। सीधी से पीपीपी मॉडल स्थगित किया जाना चाहिए। गरीब आदिवासी जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण न कराया जाए बल्कि सरकार सीधे यह निर्माण कार्य कराए। मंत्री जिसे चाहेंगे, उसे टेंडर मिल जाएगा। इस पर मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सबकुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ई-टेंडर के माध्यम से काम होगा।

अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मुद्दा

भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से भोपाल के कोटरा स्थित गंगानगर में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन आवासों का छह साल में भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। बार-बार इसकी समय सीमा बढ़ती जा रही है। इसके चलते हितग्राही किराए से रहने को मजबूर हैं। उन्हें आवास के लिए राशि दी जानी चाहिए। इसके जवाब में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ठेकेदार के स्तर पर काम नहीं किया गया है। बीच में कोविड के कारण भी देरी हुई। कई बार हितग्राही का समय से पैसा जमा नहीं हुआ, इस कारण से भी दिक्कत हुई है। मंत्री के जवाब के बाद विधायक सबनानी ने कहा कि भोपाल में इस तरह के कुल 14 प्रोजेक्ट हैं। उनके मामले में भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक के अंतर्गत गंगानगर आवासीय परियोजना में कुल 600 आवास प्रस्तावित हैं। जिसमें 240 ईडब्ल्यूएस, 144 एमआईजी और 216 एलआईजी आवास शामिल हैं। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिसंबर-2025 तक कार्य पूर्ण होकर आवास हैंडओवर करने की बात कही।

दरअसल, भोपाल में हाउसिंग के प्रोजेक्ट

माननीयों में दिखी छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की चिंता

मप्र विधानसभा के 9 दिनी बजट सत्र में प्रदेश के विकास के लिए बजट पहली बार 4.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया। यही नहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 सालों में यह बजट दोगुना हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन को पूरा करने वाला बताया। यानी बजट में बड़े-बड़े विकास का खाका पेश किया गया। लेकिन इस सत्र के दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्र में छोटे-छोटे निर्माण को लेकर चिंता दिखाई। विधायकों ने अपने क्षेत्र में सड़क, नाली और तालाब निर्माण जैस मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मप्र की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र यानि बजट सत्र में भले ही 9 बैठकें हुईं, लेकिन इस दौरान जिस तरह सदन की कार्यवाही बिना हंगामे और बिना गतिरोध के चली, उससे एक बार फिर से मप्र की गरिमा लौटी है। 10 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 24 मार्च तक तय समय के अनुसार चला। इस सत्र में 9 बैठकें हुईं, जिसमें कुल 9 दिन के इस सत्र में कुल 2849 सवाल विधायकों द्वारा पूछे गए, जिनमें से 1387 सवाल भाजपा, 1431 सवाल कांग्रेस और 31 सवाल भारत आदिवासी पार्टी ने पूछे। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में छोटे-छोटे निर्माण को लेकर जिस तरह सवाल लगाए हैं उससे प्रदेश के विकास के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। मप्र में बड़े-बड़े विकास कार्य चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा-कांग्रेस के विधायकों ने सड़क, नाली, भवन और तालाब निर्माण जैसी मांगों को लेकर विधानसभा में 510 याचिका लगाईं। ये याचिकाएं ज्यादातर विपक्ष के विधायकों ने लगाईं। कई ने छोटे-छोटे निर्माण कार्य कराने की बात रखी तो कुछ विधायकों ने खेल स्टेडियम, नए स्कूल खोलने, स्कूलों का उन्नयन, पुल-पुलियों का निर्माण, तालाब बनाने की बात भी रखी। भाजपा के भी कई विधायक पीछे नहीं रहे। उन्होंने कॉलेज खोलने, पुराने ब्रिजों का जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण, सीएम राइज स्कूल बनाने, हैंडपंप खनन, बिजली उपकेंद्र की स्थापना और नहरों को पक्का करने के लिए याचिकाएं लगाईं।

अधूरे हैं। गंगानगर, 12 नंबर और बाग मुगालिया में अब तक मकान हैंडओवर नहीं हो सके हैं, जबकि मार्च से ही फ्लैट्स हैंडओवर किए जाने थे। अब सरकार ने दिसंबर 2025 तक लोगों को मकान देने की बात कही है। भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने अधूरे प्रोजेक्ट्स का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया है। हालांकि, दिसंबर तक सभी लोगों को मकान मिल जाए, इसकी संभावना कम ही है। क्योंकि, अभी तक कई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ही खड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में 6-7 साल से अपने घर का सपना देख रहे लोग विरोध प्रदर्शन करने के मूड में हैं। इस देरी का सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग परिवारों पर पड़ रहा है। लोग समय पर अपने घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे किराए, लोन और अन्य खर्चों में अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। 12 नंबर बस स्टॉप, गंगानगर और बाग मुगालिया के हितग्राहियों ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया था। तब कमिश्नर हरेंद्र नारायण यादव ने हितग्राहियों की बैठक कर आश्वासन दिया था कि दिसंबर 2024, जनवरी 2025 और मार्च 2025 में पजेशन दे दिया जाए, लेकिन कमिश्नर के आश्वासन का कोई असर नहीं हुआ।

80 विधायकों को नहीं मिले जवाब

बजट सत्र में विधायकों ने बढ़-चढ़कर सवाल पूछे, लेकिन विडंबना यह है कि कई विभागों ने सवालों के जवाब देने में केवल खानापूर्ति की है। यानी जनता इंतजार करती रही और माननीयों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। विधानसभा का रिकॉर्ड बता रहा है कि 80 विधायकों के सवालों के जवाब में राजस्व विभाग ने बड़ी गफलत की। विभागों द्वारा विधानसभा को लिखकर भेज दिया गया है कि विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में है। यह विधानसभा को भेज दी गई। लेकिन जब विधायक परिशिष्ट लेने पहुंचे तो उन्हें वो मिले ही नहीं। यानि विधानसभा पुस्तकालय के रिकॉर्ड में भी नहीं थे। विधानसभा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। साथ ही डीओ लेटर लिखकर आपत्ति की है।

गौरतलब है कि मप्र में सहारा समूह की संपत्तियों की खरीद-फरोख्त हुई या नहीं, हुई तो किसने की, बेचने और खरीदने वाला कौन है, किस नियम के तहत ऐसा हुआ, भूमि की कीमत कितनी थी और कलेक्टर गाइडलाइन क्या कहती है... आदि कई सवालों के साथ सरकारी जमीनों की मौजूदा स्थिति को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के ढेरों विधायकों ने विधानसभा में सवाल लगाए थे। लेकिन विभागों ने करीब 80 विधायकों के सवालों का पूरा जवाब नहीं दिया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने राजस्व विभाग से कहा है कि तत्काल व्यक्तिगत रूचि लेकर परिशिष्ट के साथ जानकारी भिजवाएं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल का कहना है कि पत्र आया है। कुछ कलेक्टरों से जानकारी नहीं मिली थी। अब आ गई है। एक-दो दिन में विधानसभा को भेज दी जाएगी। यहां बता दें कि कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ही पूछा था कि 2020 के बाद सहारा समूह की कितनी जमीनों के सौदे हुए। राजस्व विभाग की ओर से कह दिया गया कि जानकारी विधानसभा के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है। जबकि वहां कोई दस्तावेज नहीं था। कई दूसरे विधायकों के साथ भी ऐसा ही हुआ।

रतलाम जिले के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आरोप लगाया कि सैलाना और बाजना विकासखंडों की कई ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य सिर्फ कागजों पर पूरे दिखाए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। विधायक ने विशेष रूप से कहा कि उनके क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां तालाब, सड़कें और भवन कागजों पर बन गए लेकिन वास्तविकता में उनका कोई निशान तक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर रातों-रात घटिया निर्माण कर दिया। विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में निर्माण कराने की मांगें की हैं। विधायक महेंद्र रामसिंह यादव ने आगर में सीसी रोड, नाली और कोलारस में खेल स्टेडियम बनाने की मांग की। राजेंद्र भारती ने कहा कि दतिया के वामरोल में नहर की पुलिया से बस्ती तक सीसी सड़क बनाई जाए। अनुभा मुंजारे ने लालबर्रा बस स्टैंड से अमोली तक सीसी रोड निर्माण, कैलाश कुशवाह ने झिरी पंचायत में डामर वाली सड़क, कामाख्या प्रताप सिंह ने कराठा के मेन रोड से राधा कुशवाह के मकान तक सीसी रोड का निर्माण, डॉ. सतीश सिकरवार ने ग्वालियर के वार्ड 23 में सड़क निर्माण, दिनेश राय मुनमुन ने परासिया से बेलखेड़ी मार्ग के निर्माण की मांग की। इसी प्रकार अन्य कई विधायकों ने भी अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य की मांग की।

सबसे ज्यादा सवाल पंचायत, राजस्व और नगरीय विकास विभाग से जुड़े

विधायकों ने सबसे ज्यादा 245 सवाल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को लेकर पूछे। इस विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। विधायकों ने जनपद पंचायतों के खातों से पैसे निकाले जाने, भ्रष्टाचार के मामलों में उच्च स्तरीय जांच, सड़क निर्माण में अनियमितताएं, पेसा एक्ट, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े सवाल पूछे। वहीं, राजस्व विभाग को लेकर 215 सवाल पूछे गए। जिनमें जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें, अतिक्रमण, राहत राशि का भुगतान, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से जुड़े सवाल शामिल थे। नगरीय आवास एवं विकास विभाग को लेकर 183 सवाल पूछे गए। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कॉलोनियों और प्राधिकरणों से संबंधित सवाल शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास इस समय 10 विभाग हैं। इनमें सबसे ज्यादा सवाल गृह और जेल विभाग को लेकर पूछे गए। इनमें हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, सीआईडी जांच में देरी, प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण से जुड़े सवाल किए गए। सामान्य प्रशासन और वन विभाग से जुड़े सवालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाले और वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन जैसे सवाल शामिल थे।

सुनीता विलियम्स पर सबको नाज

सुनीता विलियम्स का यह लंबा प्रवास विज्ञान के लिए एक अनमोल अवसर साबित हुआ। आईएसएस पर रहते हुए उन्होंने 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें 900 घंटे से ज्यादा समय रिसर्च में बिताया। सुनीता विलियम्स की वापसी से सारी दुनिया ने राहत के सांस ली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर नौ महीने से अधिक समय बिताकर सुर्खियां बटोरीं। यह यात्रा, जो मूल रूप से केवल आठ दिनों के लिए नियोजित थी, बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण अनापेक्षित रूप से लंबी हो गई। 5 जून 2024 को शुरू हुई यह यात्रा 19 मार्च 2025 को समाप्त हुई, जब वे स्पेसएक्स ड्रैगन यान के जरिए पृथ्वी पर लौटीं। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं–क्या सुनीता का यह लंबा अंतरिक्ष प्रवास एक वरदान था या यह एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था जिसने उनके जीवन और विज्ञान को नए आयाम दिए?

सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को बोइंग स्टारलाइनर के पहले मानवयुक्त परीक्षण मिशन के तहत आईएसएस पर भेजा गया था। योजना थी कि वे आठ दिन वहां रहकर अंतरिक्ष यान की कार्यक्षमता का परीक्षण करेंगे और वापस लौट आएंगे। लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स में खराबी और हीलियम रिसाव जैसी समस्याओं ने उनकी वापसी को असंभव बना दिया। नासा ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टारलाइनर को बिना चालक दल के पृथ्वी पर वापस भेजा और सुनीता विलियम्स को आईएसएस पर ही रहने का निर्णय लिया। इस तरह, उनका आठ दिन का मिशन नौ महीने की लंबी यात्रा में बदल गया।

सुनीता विलियम्स का यह लंबा प्रवास विज्ञान के लिए एक अनमोल अवसर साबित हुआ। आईएसएस पर रहते हुए उन्होंने 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें 900 घंटे से ज्यादा समय रिसर्च में बिताया। इन प्रयोगों में जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में बैक्टीरिया और यीस्ट की जैव-उत्पादन प्रक्रिया और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में सामग्रियों के पुराने होने जैसे अध्ययन शामिल थे। ये शोध भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, विशेष रूप से मंगल ग्रह जैसे लंबी अवधि के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, पैक्ड बेड रिएक्टर एक्सपेरिमेंट में सुनीता ने जल पुनर्जनन प्रणाली की जांच की, जो यह समझने में मदद करती है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जल शोधन कैसे काम करता है। यह तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी की आपूर्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकती है। इसी तरह, यूरो मटेरियल एजिंग प्रयोग ने अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए डेटा प्रदान किया। इस दृष्टिकोण से देखें तो उनका लंबा प्रवास न केवल नासा के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक वरदान था, क्योंकि इससे प्राप्त ज्ञान अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देगा।

सुनीता विलियम्स पहले से ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा (2006–07) में 29 घंटे से अधिक का स्पेसवॉक करके महिलाओं के लिए रिकॉर्ड बनाया था। इस बार, नौ महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने कुल 62 घंटे और 9 मिनट का स्पेसवॉक पूरा किया, जिससे वह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेसवॉक करने वाली महिला बन गईं। यह उपलब्धि उनके धैर्य, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा, वे अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला भी बन गईं। यह रिकॉर्ड न केवल उनके करियर का एक सुनहरा पन्ना है, बल्कि यह दुनियाभर की महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। इस नजरिए से, उनका यह अनुभव निसंदेह एक वरदान था, जिसने उन्हें इतिहास में और ऊंचा स्थान दिलाया है। हालांकि, अंतरिक्ष में नौ महीने बिताना केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में इतना लंबा समय बिताने से मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हड्डियों का घनत्व हर महीने लगभग 1 प्रतिशत तक कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है।

● रजनीकांत पारे

क्या अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हैं निजी कंपनियां?

सुनीता का यह अनापेक्षित ठहराव अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी लेकर आया। बोइंग स्टारलाइनर की तकनीकी खामियों ने यह सवाल उठाया कि क्या निजी कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटना ने नासा को स्पेसएक्स जैसे वैकल्पिक विकल्पों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए मजबूर किया, जिसके ड्रैगन यान ने अंततः सुनीता और बुच को वापस लाया। यह अनुभव अंतरिक्ष यानों की विश्वसनीयता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाओं को बेहतर करने की जरूरत को रेखांकित करता है। इस तरह, यह घटना भविष्य के मिशनों को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। भारत के लिए सुनीता विलियम्स का यह सफर विशेष रूप से गर्व का विषय है। गुजरात के अहमदाबाद से संबंध रखने वाली सुनीता ने न केवल अपनी उपलब्धियों से, बल्कि अपनी दृढ़ता से भी भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि तकनीकी बाधाएं और व्यक्तिगत चुनौतियां भी इंसान को अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकतीं। भारत जैसे देश में, जहां अंतरिक्ष अनुसंधान तेजी से बढ़ रहा है (जैसे गगनयान मिशन), सुनीता का यह अनुभव एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है। इस नजरिए से, उनका नौ महीने का प्रवास भारत के लिए भी एक अप्रत्यक्ष वरदान है।

लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गत दिनों तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री समेत 58 दल के नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। इसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी लाया जा सकता है।

परिसीमन पर आर-पार

दक्खिन दिशा से उठी जोरदार हवा क्या विंध्य पार कर सकती है? राजनीति में किसी संभावना से इनकार कोई अहमक ही कर सकता है। वैसे, दक्षिण तो शायद पूरी तरह इस बवंडर की चपेट में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, द्रविड़ मुनेत्र कझगम (द्रमुक) के नेता एमके स्टालिन के हाथ तो जैसे नया राजनीतिक अमोघ अस्त्र लग गया है। उन्होंने 2026 के बाद संसदीय और राज्य विधानसभाओं के संभावित परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के त्रि-भाषा फॉर्मूले के खिलाफ मोर्चे को विंध्य पार ले जाने की मुहिम तेज कर दी है।

भाषा विवाद को तूल दे रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन पर बैठक बुलाकर यही सिद्ध किया कि वह राजनीतिक रोटियां सेंकने के इरादे से एक और ऐसे मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई सिर-पैर नहीं दिख रहा है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का उनका आरोप भी अपने राज्य के लोगों को बरगलाने के लिए ही है, क्योंकि इस नीति के त्रि-भाषा सूत्र में तो हिंदी का उल्लेख तक नहीं है। लगता है कि इस मुद्दे पर बेनकाब होने के बाद ही उन्होंने परिसीमन के मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वह यह शोर मचाने में लगे हुए हैं कि यदि परिसीमन के निर्धारण में केवल जनसंख्या को आधार बनाया जाता है तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की सीटें घट जाएंगी।

यह भय का भूत खड़ा करने की ही कोशिश है, क्योंकि अभी यह तय नहीं कि परिसीमन का एकमात्र आधार जनसंख्या को बनाया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि परिसीमन की नौबत तब आएगी, जब जनगणना होगी। अभी तो यही नहीं पता कि जनगणना कब होगी? यद्यपि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन में किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन स्टालिन को चैन नहीं। वह ऐसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं, जैसे जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कराने की मुनादी कर दी गई है।

भाषा का मामला हो या फिर परिसीमन का, स्टालिन के रवैये से यदि कुछ सिद्ध हो रहा है तो यही कि उनकी निगाह तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और वह अपनी राज्य की जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, जिनके लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जा सकता है। यह किसी से छिपा नहीं कि वह परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते जा रहे हैं। वह केवल दक्षिण के राज्यों की राजनीति की कमान ही अपने हाथ नहीं लेना चाहते। वह विपक्षी दलों की

परिसीमन पर सीमा

आजादी के बाद देश में परिसीमन की तीन बड़ी कवायदें 1952, 1962 और 1972 में की गईं। लोकसभा की सीटों की संख्या भी 500, 521, 543 होती गई। अलबत्ता, 1976 में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए 42वें संविधान संशोधन के जरिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी। तब भी मुख्य तर्क था कि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों (खसकर उत्तर में) को ज्यादा सीटें हासिल हो जाएंगी और जनसंख्या पर नियंत्रण रखने वालों (खासकर दक्षिण में) को घाटा होगा। इस कथित असंतुलन को रोकने के लिए यह फैसला किया गया कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही बना रहेगा। शुरुआत में यह रोक 2000 तक लागू रहनी थी, लेकिन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 84वें संविधान संशोधन से 2026 तक बढ़ा दिया। अब जब 2026 नजदीक आ रहा है, और अगली लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है तो परिसीमन की कवायद नए विवाद की वायस बन गई है। हालांकि यह कवायद अगली जनगणना के बाद ही होनी है, जो 2021 में हो जानी थी लेकिन पहले कोविड महामारी और बाद में टलती गई। अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है।

राजनीति के सूत्र भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें यह लगने लगा है कि वह ममता बनर्जी की तरह विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। इसमें वह शायद ही सफल हों, क्योंकि परिसीमन को लेकर बुलाई गई बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। वाईएसआर कांग्रेस भी इस बैठक से दूर रही। तथ्य यह भी है कि विपक्षी दलों के कई नेताओं ने 25 साल तक परिसीमन रोकने की उनकी मांग का समर्थन नहीं किया। ध्यान रहे कि परिसीमन को पहले भी दो बार टाला जा चुका है। केंद्र सरकार को इसे लेकर सतर्क रहना होगा कि स्टालिन और उनके साथ खड़े नेता परिसीमन को लेकर विभाजनकारी राजनीति न करने पाएं।

कर्नाटक में कांग्रेस के सिद्धारामैया का दावा है कि केंद्र सरकार के कदम लगातार राज्य को सजा दे रहे हैं, चाहे वह कर राजस्व वितरण में हेर-फेर हो, जीएसटी (माल और सेवा कर) और आपदा राहत में असमानताएं हों, शिक्षा नीति हो, या यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के मनमाने फेरबदल। उन्होंने कहा, परिसीमन के जरिए संसद में दक्षिण की नुमाइंदगी और केंद्र की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज को कमजोर करने की कोशिश है। रेवंत रेड्डी का तो कहना है कि भाजपा परिसीमन के जरिए दक्षिण को दरकिनार करके बीमारू राज्यों में सीटें बढ़ाकर पिछले दरवाजे से अपना दबदबा मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा पंजाब से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी परिसीमन को 1971 की जनगणना पर रहने देने की मांग उठाई है, तो लगता है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को आगे ही बढ़ाएगी।

यही नहीं, दक्षिण के गैर-भाजपा नेता इससे महिला आरक्षण कानून को भी जोड़कर देखते हैं। उनकी दलील है कि संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को लागू करने की शर्त परिसीमन को बनाने के पीछे भी सियासी खेल खेलने की मंशा है। इस तरह, न सिर्फ परिसीमन को जरूरी बनाया गया, बल्कि बहस को महिलाओं के हक से जोड़कर स्वायत्तता और संसदीय सीटों के घटने पर उठने वाले सवालों का रुख मोड़ने की कोशिश की गई। भाजपा को शायद उम्मीद रही है कि इससे विपक्ष और खासकर दक्षिण के विपक्षी दल परिसीमन का विरोध आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें महिला आरक्षण में देरी करने के आरोप से जूझना पड़ सकता है या उनका महिलाओं का वोट घट सकता है। लेकिन लगता है, सियासी बहस का रुख दूसरी ओर जा रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण राज्यों को भरोसा दिलाया है कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने भी काल्पनिक भय दिखाकर लोगों को गुमराह करने के लिए स्टालिन की खिंचाई की। लेकिन स्टालिन का कहना है कि दक्षिणी राज्यों के सिर पर तलवार लटक रही है।

शक-शुबहे की एक वजह नए संसद भवन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इससे विपक्षी दलों को आशंका है कि यह परिसीमन और अपने दबदबे वाले उत्तर भारत में सीटें बढ़ाने की भाजपा की लंबी योजना का हिस्सा है। संसदीय सीटों की परिसीमन की इजाजत हर जनगणना के बाद संविधान का अनुच्छेद-82 देता है। इसी तरह अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे का प्रावधान है। यह प्रक्रिया परिसीमन आयोग पूरा करता है, जिसे आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से खींचने और अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें तय करने का अधिकार हासिल है। अनुच्छेद 329(ए) के तहत परिसीमन के संबंध में संसद से पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचारी के मुताबिक, अनुच्छेद-81 में 550 सीटों की सीमा तय की गई है, यानी 530 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लिहाजा, सीटों की कुल संख्या में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए अनुच्छेद-81 में फेरबदल की दरकार होगी। अगली परिसीमन की कवायद से देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अहम बदलाव आ सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या 543 बनी रहती है, तो चार उत्तरी राज्यों उप्र, बिहार, मप्र और राजस्थान में 31 सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में 26 सीटें घट जाएंगी।

● विपिन कंधारी

सियासी और चुनावी अक्स

दरअसल यह भाजपा और विपक्षी पार्टियों की राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। कई जानकारों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनावों में महज 240 सीटों पर सिमटने से भाजपा की कोशिश उत्तर में सीटें बढ़ाकर 2029 के चुनावों में उसकी कुछ भरपाई करने की है। उधर, विपक्षी दलों की कोशिश केंद्र और भाजपा के खिलाफ इसे बड़ा मुद्दा बनाने की लगती है। दक्षिण में तो भाजपा विरोधी लहर को तेज करने और अपने खिलाफ सरकार विरोधी रुझान को कम करने के लिए स्टालिन इसे परिसीमन से कहीं आगे अधिकारों और तमिल पहचान की लड़ाई तक ले जाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय है। अपने जन्मदिन (2 मार्च) पर उन्होंने घोषणा की, हम देश में भाषा की लड़ाई की दिशा तय करने वालों में अग्रणी रहे हैं। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत तीन-भाषा नीति को हिंदी थोपने की कोशिश करार देते हैं और इसे केंद्र के अतिक्रमण से जुड़ा एक और पहलू करार देते हैं, जो पहले से ही तमिलनाडु को उसके हिस्से की धनराशि से वंचित कर रहा है। भाजपा ने बेशक तमिलनाडु में द्रमुक को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है, जो केंद्र-राज्य संबंधों और सामाजिक न्याय के साथ-साथ द्रविड़ मॉडल से भी जुड़ा है। स्टालिन और दूसरे नेता इसे आर्थिक मोर्चे पर गुजरात मॉडल बनाम समाज कल्याण मॉडल बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर यह मुद्दा पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नवीन पटनायक भी उठा लेते हैं तो इससे बड़े सियासी सूत्र खुलने की संभावना है।

आज पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व में ऐसे नारे गढ़ने की प्रतिभा का भी अभाव दिखता है। इसलिए अपनी कमी का दोष अपने दल के कार्यकर्ताओं नेताओं तथा अन्य लोगों पर मढ़ना उसकी मजबूरी है। राहुल गांधी जब सार्वजनिक रूप से अजीबो-गरीब बातें कहते हैं और उस कारण उनकी और पार्टी की किरकिरी होती है तो उसका दोष राहुल के वैचारिक सलाहकारों पर मढ़ दिया जाता है।

सुधार की क्षमता गंवाती कांग्रेस

कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि जीत का श्रेय जहां नेहरू-गांधी परिवार के खाते में जाता है तो हार का ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ा जाता है। इसी अघोषित, किंतु स्थापित परिपाटी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल में कहा कि राज्यों के चुनाव परिणामों के लिए पार्टी के प्रभारी जिम्मेदार होंगे। कुछ दिन पहले ही गुजरात में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं की भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन्हें कड़ी नसीहत दी।

राहुल ने ऐसे संदिग्ध नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने से परहेज न करने की बात भी कही। स्पष्ट है कि किसी भी संभावित हार की स्थिति में पार्टी ने अपना रुख पहले से ही तैयार कर लिया है, जिसमें हार की आंच किसी भी तरह नेहरू-गांधी परिवार पर नहीं पड़ने दी जाएगी। याद कीजिए कि 1962 में चीन से युद्ध हारने का जिम्मेदार तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और सैन्य नेतृत्व को बताया गया और नेहरू को उसकी तपिश से बचाने का हरसंभव प्रयास किया गया। इसके उलट 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में विजय का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी के खाते में गया। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय हुई तो उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे एक स्वर से ठुकरा दिया गया। असल में, जिस संगठन में जब बॉस इज आलवेज राइट का चलन होगा तो उसकी चाल बिगड़ने से भला कौन रोक सकता है। राजनीतिक इतिहास यही दर्शाता है कि कांग्रेस स्वयं में सुधार की क्षमता पूरी तरह खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोष सिर में है, लेकिन पार्टी इलाज पैर का करना चाहती है। अब जब वोटिंग मशीन पर लांछन लगाना काम नहीं आ रहा है तो कांग्रेस आलाकमान ने अगली किसी आशंकित हार के लिए अभी से ही बलि का बकरा खोजने की कवायद शुरू कर दी है। आजादी के तत्काल बाद से ही जातीय और सांप्रदायिक वोटबैंक के आधार पर कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया। हालांकि उसे 1952 में भी देश में सिर्फ 45 प्रतिशत वोट मिले। वह कभी 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाई। नेहरू-गांधी परिवार के शीर्ष नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना ऐसा मसीहा मान लिया है, जिसकी आलोचना मानो ईशनिंदा जैसी हो। यह कोई नई बात नहीं है। आपातकाल की पृष्ठभूमि में 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय के लिए पूरी तरह इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी जिम्मेदार थे, लेकिन पार्टी में उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई और न ही उन्हें इस पराजय की कोई सजा मिली। ऐसा इसीलिए, क्योंकि नेहरू-गांधी परिवार किसी भी अनुशासन या सजा से हमेशा ऊपर रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस कार्यसमिति सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया था। इस निर्णय का आधार इससे पहले इंदिरा गांधी के आवास पर हुई एक बैठक थी। हालांकि बाद में

विश्वसनीय सलाहकार नेपथ्य में चले गए

राहुल के कई पूर्व निकटस्थ विश्वसनीय सलाहकार मुख्यधारा से बाहर हुए या नेपथ्य में चले गए। भारत की तासीर धर्म और अध्यात्म है। इसका मूल हिंदुत्व में है। हमारा राष्ट्रभाव इसी से उत्प्रेत है। सेक्युलरवाद हमारे यहां सर्वपंथ समभाव है। सच यह है कि राहुल और उनके रणनीतिकारों के व्यवहार से पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में लोग असहज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए जब मोदी सरकार अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने का विधेयक लाई तो कांग्रेस नेतृत्व के विपरीत कई नेताओं ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 370 हटाना बिल्कुल सही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी लगभग हर राज्य से कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व की भावनाओं के परे रुख अपनाया। महाकुंभ में आध्यात्मिक-सांस्कृतिक-पुनर्जागरण का जो विराट रूप दिखा, वह बदलते भारत का प्रमाण था, जिसे हर पार्टी के नेताओं का बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष महसूस कर रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के इस वक्तव्य से बड़े वर्ग की असहमति थी कि क्या गंगा नहाने से गरीबी मिट जाएगी? अनेक कांग्रेसी नेता संगम में डुबकी लगाने गए। इनमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी थे, जिनके बारे में सूचना है कि राहुल गांधी की मंडली उनसे नाराज है। अगर राहुल और उनके रणनीतिकार वीर सावरकर जैसी हिंदुत्व विभूतियों के विरुद्ध घृणा के भाव में व्यवहार करेंगे तो उन्हें हर व्यक्ति भाजपा समर्थक ही नजर आएगा।

नेताओं को लगा कि वह निर्णय कांग्रेस के हित में व्यावहारिक और दूरदर्शितापूर्ण नहीं है, लेकिन उस निर्णय के पीछे मुख्य मंशा यही थी कि बड़ी से बड़ी हार के लिए भी नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। इससे पहले 1971 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को भारी बहुमत मिला तो कहा गया कि यह इंदिरा जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का असर था। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त किए। इससे कांग्रेस के प्रति आम लोगों खासकर गरीबों का आकर्षण बढ़ा। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के पास संगठन का कोई मजबूत ढांचा नहीं था। निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस का नाम ही संगठन कांग्रेस पड़ा था, क्योंकि संगठन का अधिकांश हिस्सा निजलिंगप्पा के पास ही रह गया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा कांग्रेस की जीत के पीछे यह तर्क मजबूत था कि शीर्ष नेता में यदि क्षमता-कुशलता है तो पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा ही। उस समय के नेतृत्व को लोकलुभावन नारे, भले वे झूठे ही क्यों न हों, गढ़ना तो आता था।

आज पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व में ऐसे नारे गढ़ने की प्रतिभा का भी अभाव दिखता है। इसलिए अपनी कमी का दोष अपने दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा अन्य लोगों पर मढ़ना उसकी मजबूरी है। राहुल गांधी जब सार्वजनिक रूप से अजीबो-गरीब बातें कहते हैं और उस कारण उनकी और पार्टी की किरकिरी होती है तो उसका दोष राहुल के वैचारिक सलाहकारों पर मढ़ दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने 2012 में लिखा था कि राहुल गांधी दुविधाग्रस्त और अगंभीर नेता हैं। इसके बावजूद हर कोई राहुल गांधी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। लगता है कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति का आंकलन करना भी बंद कर दिया है, जो पार्टी के पतन का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। एक समय देश के बड़े हिस्से पर शासन करने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से अपनी साख खोती गई, लेकिन पार्टी ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की समीक्षा करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

2014 के चुनाव में मानमर्दन के बाद हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित एंटनी समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि मुस्लिमों की ओर झुकाव का पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बावजूद यही लगता है कि कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं लिया। अब कांग्रेस की अपने दम पर मात्र तीन राज्यों में सरकार है और ऐसे ही एक राज्य कर्नाटक की सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण दिया जाएगा। इस पर बहस भी शुरू हो गई है, लेकिन कर्नाटक का मामला यही रेखांकित करता है कि कांग्रेस इस पहलू की कोई परवाह नहीं करती। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी उसका रवैया उसे संदिग्ध बनाता है। पार्टी देश के बदलते मानस और राजनीतिक परिदृश्य पर होते परिवर्तन को समझ नहीं पा रही और अपना जनाधार एवं प्रासंगिकता खोती जा रही है।

हाल में राहुल गांधी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने अहमदाबाद में प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में अपने नेताओं को दूसरी पार्टी यानी भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाने से लेकर उन्हें बारात के घोड़े तक की संज्ञा दे दी। उन्होंने भाजपा से मिलकर काम करने वाले 30-40 कांग्रेस नेताओं को निकालने की भी बात कही। गुस्से या खीझ में वक्तव्य देने का केवल गुजरात नहीं, पूरे देश के आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर संदेश सकारात्मक नहीं गया होगा। राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार कह सकते हैं कि कांग्रेस को जगह-जगह चुनावी जीत दिलाना और राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता में लाना है तो भितरघात करने वालों तथा पार्टी के विचार और लक्ष्य के अनुरूप न काम करने वालों को बाहर करना पड़ेगा। किसी पार्टी में अगर भितरघाती सक्रिय हों तो इसे सामान्य भाषा में गद्दारी कहते हैं। राहुल की बातों को स्वीकार कर लें तो उन्हें दूसरे दल से मिलकर काम करने वाले नेताओं को बाहर करने से रोकने वाला कोई नहीं है, किंतु यह इतना सामान्य नहीं है। उन्होंने जो कहा, उसका निहितार्थ उतना सपाट भी नहीं है। वर्तमान भारतीय राजनीति का सच यह है कि हर पार्टी में प्रकट या मौन हिंदुत्व समर्थक बढ़े हैं। कुछ नेताओं और पार्टियों का इस सच से सामना हुआ है कि किसी भी स्थिति में हिंदुत्व विरोधी दिखने से उनके जनाधार पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्हें सार्वजनिक तौर पर स्वयं को हिंदुत्वनिष्ठ-धर्मनिष्ठ प्रदर्शित करना पड़ रहा है। ऐसा करते हुए वे संघ और भाजपा को गलत हिंदुत्ववादी बताते हैं। एक समय राहुल और उनके पूर्व के रणनीतिकार भी धर्मनिष्ठ होने का प्रदर्शन कर रहे थे। वह मंदिर- मंदिर जा रहे थे। उस समय राहुल को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण बताया गया था। उनकी कैलास मानसरोवर की यात्रा तक हुई। इसके पीछे रणनीति यही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का सामना करना है तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व को भी हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रवाद पर आना पड़ेगा। कांग्रेस के अनेक नेता सार्वजनिक मंचों से स्वयं को हिंदू और धर्मनिष्ठ कहने लगे थे। क्या वे भाजपा, संघ या मोदी समर्थक हो गए थे?

● इन्द्र कुमार

वैचारिक अंतर्द्वंद्व से त्रस्त कांग्रेस

काफी समय से कांग्रेस में वैचारिक अंतर्द्वंद्व जारी है जो समय-समय पर उभरता रहता है। केरल में तिरुअनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर का मामला सामने है। चूंकि थरूर बड़े नेता हैं, इसलिए उनका मामला देशव्यापी चर्चा में आ गया। हर राज्य में ऐसे नेताओं की बड़ी संख्या है, जिन्हें इसी तरह संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जिस पार्टी के अंदर एक-दूसरे को लेकर संदेह का माहौल हो, कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दशा क्या होगी। थरूर ने अपने लेखन और वक्तव्य से ऐसे वैचारिक बदलाव का कोई संकेत दिया नहीं है कि वह आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के निकट हैं। यह अलग बात है कि सरकार की कई नीतियों खासकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर उनके वक्तव्य व्यावहारिक तथ्यों के साथ रहे हैं। सही को सही कहना भी किसी पार्टी में भाजपा समर्थन या आंतरिक अनुशासन तोड़ना है तो इसका कोई रास्ता नहीं है। एक समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो थरूर के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की प्रशंसा की थी।

छापेमारी की सियासत

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों के घरों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी ने प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जिसमें भूपेश बघेल, उनके परिवार, और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है और प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। महादेव सट्टा ऐप घोटाला एक बड़ा वित्तीय घोटाला है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारी मात्रा में नकद लेन-देन हुआ था। इसके अंतर्गत कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने हर महीने लाखों रुपए के बदले इस घोटाले को संचालित किया। इस मामले में भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल, भिलाई के कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम आए हैं।

सीबीआई की इस कार्रवाई के पीछे यही आरोप हैं, जिनकी जांच जारी है। यह कार्रवाई पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई शराब घोटाले की जांच से जुड़ी हुई है, जिसमें भूपेश बघेल और उनके बेटे के खिलाफ आरोप लगे थे। इसी क्रम में अब सीबीआई ने भूपेश बघेल सहित कई अन्य नेताओं और अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की है, जो महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े हुए थे। सीबीआई की छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपा ने सीबीआई को भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के पीछे लगा दिया है, लेकिन यह सब सत्ता की हताशा के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी नहीं झुकेगी और न रुकेगी। कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि वे सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश मानते हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताया और आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि भाजपा हर नाकाम कोशिश के बाद अब सीबीआई को इस कार्रवाई में लगा रही है, जो पूरी तरह से सत्ता के अन्याय का हिस्सा है। उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं को विश्वास दिलाया कि सत्य और न्याय की जीत होगी। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने भी भाजपा को एक कड़ा संदेश दिया और कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहू शीतल हो... के जरिए भाजपा को समझाया कि काम ऐसा करना चाहिए जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल को हमेशा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में कांग्रेस नेताओं को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच कर रही हैं तो यह कोई दुर्भावना नहीं हो सकती, बल्कि यह न्याय का हिस्सा है। उनका मानना था कि राजनीति से प्रेरित आरोपों की बजाय सभी को जांच में सहयोग करना चाहिए और प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा होने देना चाहिए। उनका कहना था कि कोई भी कार्रवाई चुनाव से पहले या बाद हो सकती है, लेकिन सबको न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सीबीआई की टीम ने भिलाई-3 स्थित भूपेश बघेल के आवास, भिलाई सेक्टर-9 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर दबिश दी। इनमें पुलिस अधिकारी डॉ. आनंद छाबड़ा, पूर्व एसपी दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव और पूर्व एएसपी दुर्ग संजय ध्रुव शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा के घरों पर भी जांच की जा रही है। रायपुर में पुलिस अधिकारियों शेख आरिफ और अभिषेक महेश्वरी के घर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी। इन सभी अधिकारियों और नेताओं के नाम महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े मामलों में पहले ही सामने आ चुके थे और इन पर आरोप है कि वे इस घोटाले में शामिल थे। भूपेश बघेल ने सीबीआई की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब सीबीआई आई है। उन्होंने बताया कि वह अहमदाबाद में 8-9 अप्रैल को होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने उनके रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। इस बयान से यह साफ हो जाता है कि भूपेश बघेल इस कार्रवाई को एक राजनीतिक साजिश मानते हैं और इसे चुनावी मुद्दों से पहले उठाया गया कदम मानते हैं। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ 2,161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच की थी। 10 मार्च को ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी करते हुए 33 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। उस समय कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और बघेल के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की थी। यह विरोध आज भी जारी है और बघेल के निवास के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित किया जा सके।

● रायपुर से टीपी सिंह

कांग्रेस ने ही की थी सीबीआई जांच की मांग

सीबीआई छापे को भाजपा ने इसे जांच के आधार पर होने वाली कार्रवाई बताया है। गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के अंदर इस सारे केस में खुद ही सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ विषयों पर सीबीआई जांच चाहिए। उन्होंने इस मामले में यह भी बात दोहराई थी कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मिलेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि हमने ऑनलाइन बेटिंग घोटाले से जुड़े मामले को सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई को कोई फाइंडिंग मिली होगी तो जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने नेता भूपेश बघेल और अन्य लोगों के परिसरों पर सीबीआई की तलाशी को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। अरुण साव ने कहा कि राज्य में पिछली बघेल सरकार के दौरान कई बड़े घोटाले हुए थे, जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है।

औरंगजेब पर सियासी संग्राम

महाराष्ट्र सहित पूरे देश में इस समय औरंगजेब पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई जारी है। 24 मार्च को नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चल गया। उसके घर के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इस बीच जिले में शांति लौटने के साथ ही पुलिस ने सभी इलाकों से निषेधात्मक आदेश वापस ले लिए हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद पुलिस चाक-चौबंद व्यवस्था बढ़ाकर जल्द ही अन्य आरोपियों पर दर्ज मामलों में कार्रवाई कर सकती है।

दरअसल, महाराष्ट्र में 14 फरवरी को फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद से औरंगजेब को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। दरअसल, फिल्म में औरंगजेब और मुगल सेना की संभाजी महाराज के साथ की गई क्रूरता को दिखाया गया। फिल्म के दृश्य इतने चौंकाने वाले थे कि एकाएक देशभर में औरंगजेब को लेकर सर्च बढ़ गए। इस बीच मामला राजनीतिक गलियारों में पहुंच गया। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी ने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण किया था, औरंगजेब क्रूर नहीं था। मैंने औरंगजेब के बारे में जितना अध्ययन किया है, उससे मुझे यह समझ में आया कि उसने कभी भी जनता का धन अपनी भलाई के लिए नहीं लिया। उसका साम्राज्य बर्मा (वर्तमान समय में म्यांमार) तक फैला हुआ था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि वह एक महान प्रशासक थे और उनकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। उनके इस बयान का चौतरफा विरोध हुआ। आजमी के खिलाफ मामले में केस भी दर्ज करा दिए गए। यह मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठा और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसने देशभक्त संभाजी को मारा, उस औरंगजेब को अच्छा शासक बताकर अबु आजमी ने बड़ा पाप किया है। मामला इतना बढ़ा कि आजमी को माफी तक मांगनी पड़ गई। हालांकि, उन्हें बाद में विधानसभा से निलंबित कर दिया गया।

15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू की। उनका तर्क था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था और उसकी कब्र को ऐतिहासिक धरोहर मानकर संरक्षित रखना अनुचित है। इस मांग को लेकर नागपुर, पुणे और संभाजीनगर में इन संगठनों ने बड़े प्रदर्शन किए। बजरंग दल ने कहा कि अगर सरकार कानून के जरिए इस काम को करने में नाकाम रहती है तो फिर वह कार सेवा करेंगे। विहिप और बजरंग दल ने कहा कि वह 17 मार्च को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कानूनी तरह से कब्र हटाने की मांग की जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात 10.30 से 11.30 बजे के बीच भीड़ ने हमला बोल दिया, पथराव किया और वाहनों में आगजनी की। लोगों को पीटा। भीड़ ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाकर तोड़ा। उसके बाद से लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस घटना के एक से डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची।

नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि यह हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि यह सुनियोजित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी चाहिए।

फडणवीस ने बताया कि हिंसा में तीन उपायुक्त (डीसीपी) समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि पांच नागरिक भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने पांच केस दर्ज कर 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पांचपावली, शांत नगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। वहीं, इस मामले में विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना (यूबीटी) को घेरते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब के महिमामंडन पर सवाल उठाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब कौन है? हमें अपने राज्य में उनका महिमामंडन क्यों होने देना चाहिए? वह हमारे इतिहास पर एक धब्बा है। यह भी सामने आया कि पुलिस ने नागपुर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद दोनों संगठनों के आठ कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

● बिन्दु माथुर

संघ ने घेरा, शिवसेना ने किया बांग्लादेश लिंक का दावा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस और नागपुर में हुई हिंसा के बाद मचे बवाल पर अपना रुख साफ किया। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आक्रमणकारी या आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था, या हम उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने इस भूमि की परंपराओं के अनुसार काम किया? वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि नागपुर हिंसा के लिंक बांग्लादेश से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा सुनियोजित थी और एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। संजय निरुपम ने कहा कि नागपुर हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों का बांग्लादेश से जुड़ाव हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि हिंसा के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सोशल मीडिया पर मुजाहिद्दीन गतिविधियों के लिए फंड जुटा रहा था।

खाली हो रहा कोटा!

अन्य कोचिंग संस्थान खुलना भी एक कारण

कोटा कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी ने कहा कि संख्या में गिरावट के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि देश के विभिन्न भागों में कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का पालन हो। नियमों का पालन न करने वाले पीजी छात्रावासों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जैसे स्प्रिंग फैन सुनिश्चित करना। हालांकि, डेवलपर्स से लेकर बिल्डर्स, पीजी हॉस्टल मालिकों से लेकर कोचिंग संस्थानों के मालिकों तक, विभिन्न हितधारकों को उम्मीद है कि जल्द ही पुराना समय लौट आएगा और वे पहले की तरह मुनाफा कमा सकेंगे। संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के पीछे एक और कारण देश के अन्य भागों में कोचिंग उद्योगों का तेजी से बढ़ना है। माना जाता है कि बिहार का पटना, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए तेजी से उस राज्य के छात्रों की पसंद बन रहा है, क्योंकि माता-पिता अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं।

राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025 विधानसभा में पेश किया गया। राज्य में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती सुसाइड और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। वहीं देश का कोचिंग हब कहलाने वाला कोटा की कोचिंग अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। यह गिरावट केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि इस कभी चहल-पहल वाले शहर में लगभग हर जगह दिखाई दे रही है। सुनसान सड़कों पर सैकड़ों पीजी हॉस्टल की इमारतों में जो ज्यादातर खाली पड़ी हैं। निवेशकों, बिल्डरों और डेवलपर्स के चेहरों पर जो अपने निवेश के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलने के कारण लाखों और करोड़ों रुपए के नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं। कोटा के कोरल पार्क इलाके में 200 से ज्यादा इमारतों पर टू लेट और फॉर सेल के बोर्ड लगे हुए हैं। कई निर्माणाधीन इमारतों पर काम सिर्फ इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि डेवलपर्स को पीजी, हॉस्टल के लिए नई इमारतें बनाने में कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि मौजूदा इमारतों में से कई में कोई खास आबादी नहीं है।

डेटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में, 175351 छात्र कोटा में विभिन्न कोचिंग संस्थानों के माध्यम से नीट और जेईई की तैयारी कर रहे थे। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-2025 में, अब तक यह संख्या 122616 है। कागजों पर, संख्या में अनुमानित गिरावट लगभग 30 प्रतिशत है। हालांकि, वास्तविकता में, स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर है। कोटा में लगभग 4500 पीजी हॉस्टल हैं। पहले, उनमें से अधिकांश में 85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की ऑक्यूपेंसी होती थी। वर्तमान में यह 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कम हो गया है। कोटा में 1500 से अधिक मेस एरिया हैं। छात्रों की संख्या में गिरावट ने उनके व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पीजी हॉस्टल मालिक, जिनकी मासिक आय पहले 3 लाख थी, वर्तमान में किसी तरह अपना गुजारा कर पा रहे हैं, क्योंकि मासिक आय घटकर मात्र 30000 रह गई है। रेजोनेंस कोचिंग संस्थान की वाइस प्रेसिडेंट कीर्ति सिंह सोंगकारा कहती हैं कि संख्या पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह एक चक्र है। हम अनुकूल माहौल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने रेसो केयर जैसी कई पहल की हैं।

कोटा में आत्महत्याओं की बाढ़ और उनके इर्द-गिर्द चर्चा ने स्पष्ट रूप से कोचिंग उद्योग में गहराई से निवेश करने वाले कई हितधारकों की मदद नहीं की है। 2025 में, कोटा में अब तक 6 छात्रों ने आत्महत्या की है। 2024 में कोटा में 16 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। 2023 में चौंकाने वाली बात यह है कि कोटा में 27 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 12 सालों में ही राजस्थान के कोटा जिले में 150 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। कोटा पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं कि संख्या में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय से कोटा का कोचिंग उद्योग एक पैसा कमाने का धंधा बन गया था, जहां हर साल बड़ी संख्या में छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते थे और कभी-कभी, प्रतिस्पर्धी माहौल और उम्मीदवारों की भीड़ में, छोटे शहरों से आने वाले युवा लड़के और लड़कियां खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं।

बिहार, उप्र, मप्र और झारखंड जैसे राज्यों से कोटा आने वाले बहुत से छात्र अपने माता-पिता की अपेक्षाओं, साथियों के बढ़ते दबाव, बड़े पाठ्यक्रम और कोटा में शिक्षण पद्धति में भारी अंतर के कारण अपने ऊपर आने वाले अत्यधिक दबाव से बोझिल महसूस करते हैं। कोटा ने देश के कोचिंग हब होने का तमगा हासिल किया है लेकिन यह रातों-रात नहीं हुआ। कुछ दशक पहले, कोटा एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था, जहां बिजली के उपकरण, कपड़े आदि से संबंधित विभिन्न लघु उद्योग स्थापित किए गए थे। लेकिन धीरे-धीरे, ये उद्योग पीछे छूट गए क्योंकि जिला एक कोचिंग हब के रूप में विकसित होने लगा। कोटा विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों, जिनमें आईआईटी, एनआईटी, एम्स आदि शामिल हैं, में सबसे अधिक संख्या में छात्रों को भेजता रहा है। एक फल विक्रेता ने कहा कि पहले, मैं रोजाना 10,000 का लेन-देन करता था। कारोबार में भारी गिरावट आई है। अब, मैं रोजाना केवल 2000 का कारोबार करता हूं। संख्या में गिरावट का मतलब है कि फल विक्रेताओं, ठेले वालों का कारोबार भी बुरी तरह से गिर गया है। उप्र-मप्र जैसे दूसरे राज्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आने वाले छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिवर्ष 150000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए, कभी-कभी उनके परिवार द्वारा कोटा में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किए जाने वाले आर्थिक निवेश से उन पर सफल होने का अतिरिक्त दबाव आ जाता है। कुछ मामलों में, यह भी पाया गया कि यदि कोई छात्र शुरुआती प्रयासों के दौरान परीक्षा पास करने में असमर्थ रहता है, तो अंततः उस पर सफल होने का दबाव बढ़ जाता है। यह धारणा तेजी से फैल रही है कि किसी छात्र के लिए अपने गृह जिले में कोचिंग करना किसी दूसरे राज्य में जाने की तुलना में काफी प्रभावी है, जहां उनके पास कोई सहायता तंत्र नहीं हो सकता है। एक छात्र आदित्य ने कहा कि मैं बिहार से हूं और 2022 में कोटा आया था। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में स्पष्ट गिरावट आई है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

मिशन 2027 पर फोकस...

उप्र में विधानसभा चुनाव भले ही दो साल बाद हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम का ऐलान करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र चौधरी की जगह ऐसे चेहरे की तलाश में है, जो मिशन-2027 के फतह की इबारत लिख सके। इसके अलावा सूबे के सियासी समीकरण में फिट बैठने के साथ ही दिल्ली और लखनऊ के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चल सके?

भाजपा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उप्र के अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बना दिया है। जिला अध्यक्षों की सूची के आने के बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। भाजपा के संविधान में यह व्यवस्था है कि 50 फीसदी से ज्यादा जिलाध्यक्षों की घोषणा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ऐसे में पार्टी 71 फीसदी से ज्यादा जिला अध्यक्ष बना चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही लखनऊ का दौरा करके भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला करेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि भूपेंद्र चौधरी की जगह भाजपा का उप्र में नया सेनापति कौन होगा? भाजपा उप्र में जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, उसी की अगुवाई में पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में भाजपा ऐसे चेहरे की तलाश में है, जो पार्टी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में मददगार साबित हो सके। उप्र के सत्ता की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में हैं, तो पार्टी संगठन की बागडोर भी उसके कद के नेता के हाथ में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें उप्र में घट गई थीं, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाना चाहती है, जो भाजपा के खिसके हुए जनाधार को वापस ला सकें और भाजपा की जीत में मजबूत आधारशिला रखे।

2017 और 2022 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। ऐसे में भाजपा अब ऐसे चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बंपर सीटें दिलवा सके। चुनाव में कैंडिडेट के चयन से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को एक्टिव करने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होता है। यही नहीं 2027 के चुनाव अभियान को धार देने और सियासी नैरेटिव सेट करने में प्रदेश अध्यक्ष का रोल काफी अहम होता है। यही वजह है कि भाजपा को ऐसे चेहरे की तलाश है, जो भाजपा की जीत की इमारत को बुलंदी दे सके। भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की जरूरत है, जो सूबे के सियासी और क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठ सके। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव भाजपा ने ओबीसी प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में लड़े थे। दोनों चुनाव में भाजपा ने बंपर जीत दर्ज की थी। 2017 में भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और पार्टी ने 312 सीटें हासिल की थीं। 2022 में कुर्मी बिरादरी से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और 255 सीटें जीतकर भाजपा ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई। भाजपा के सामने चुनौती विपक्षी इंडिया गठबंधन, खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था। भाजपा का सवर्ण-पिछड़ा-दलित वोटबैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का सियासी दृश्य ही बदल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से हैं और पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण के साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की भी चुनौती भाजपा के सामने हैं। इसीलिए नए अध्यक्ष के नाम पर जातीय और क्षेत्रीय बैलेंस के मद्देनजर मंथन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की तलाश है, जो सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाकर चल सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में यह बात उठी थी कि सरकार से बड़ा संगठन है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। इस बात पर खूब तालियां बजी थीं, लेकिन उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से जोड़ दिया गया था। योगी सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है और नौकरशाही पूरी तरह हावी है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मैं उपमुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं, जो भी किसी जिम्मेदारी पर बैठे, चाहे वो उपमुख्यमंत्री के नाते या मंत्री के नाते, विधायक या सांसद के नाते सभी पहले कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान करें। इसके बाद उप्र में सरकार बनाम संगठन की चर्चा काफी तेज हो गई थी। ऐसे में भाजपा को ऐसे नेता की जरूरत है, जो पार्टी संगठन को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ योगी सरकार के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर रख चल सके। सरकार और संगठन में टकराव की स्थिति न बने।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

दिल्ली-लखनऊ के बीच समन्वय

भाजपा को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, जो केंद्रीय नेतृत्व यानी दिल्ली और उप्र की योगी सरकार यानी लखनऊ के बीच समन्वय बनाकर चल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव भाजपा मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ेगी। ऐसे में भाजपा के नए अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी के साथ तालमेल बैठाकर चल सकें। दिल्ली बनाम लखनऊ की बातें भाजपा में आती रहती हैं। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के रिश्ते जगजाहिर हैं। सूबे में आए दिन दोनों ही नेताओं के बीच सियासी टकराव की खबरें आती रहती थीं। स्वतंत्र देव इस वक्त जलशक्ति मंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री योगी से अच्छा तालमेल है। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री योगी के साथ बेहतर तालमेल बैठाए रखा था। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ वैसे रिश्ते नहीं दिखे। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा नेताओं के पुराने इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व अपनी पसंद के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है ताकि सत्ता और संगठन का बैलेंस बना रहे। केंद्रीय नेतृत्व ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता है, जो पूरी तरह से योगी सरकार का होकर रह जाए। इसीलिए लखनऊ-दिल्ली के बीच बेहतर समन्वय बनाकर चलने वाले नेता की तलाश की जा रही है।

दलितों के ही भरोसे कांग्रेस

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। कांग्रेस का प्राइम फोकस बिहार के दलित समाज के वोटों पर है, जिसके इर्द-गिर्द ही राहुल सियासी तानाबाना बुन रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भूमिहार समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दलित समुदाय से आने वाले दो बार के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस की बागडोर सौंप दी है।

औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के पीछे राहुल गांधी की दलित सियासत का हिस्सा माना जा रहा है। इस तरह राहुल बिहार में कांग्रेस के चार दशक पुराने सियासी रुतबे को दोबारा से हासिल करने की कवायद में हैं। इसके लिए कांग्रेस के पास बिहार में दलित सियासत की मजबूत विरासत है, जिसके तार दोबारा से कांग्रेस के साथ जोड़ने की कवायद है? राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलित वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश में है, जिस पर फिलहाल जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जैसे दलित नेताओं का कब्जा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का भी कहना है कि समय कम है, लेकिन इम्तिहान बड़ा है। साथ ही कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी का धन्यवाद है कि उन्होंने एक दलित के बेटे को इतना बड़ा दायित्व दिया है। ऐसे में ये बात साफ है कि दलित वोटों को साधने के लिहाज से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया है। राजेश कुमार की खास बात यह है कि वह खानदानी कांग्रेसी हैं। राजेश के पिता पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद बिहार में दलितों के जाने माने नेता थे। दिलकेश्वर राम का पारिवारिक संबंध पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार से था। दिलकेश्वर राम कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने पार्टी संगठन में भी अच्छा योगदान दिया। इस तरह से राजेश कुमार को सियासत अपने पिता से विरासत में मिली है, लेकिन मजबूत सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। राजेश कुमार ने कुटुंबा सीट से 2015 में जीतनराम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष और इस समय बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को हराया था। 2020 में भी उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार को हराया। हालांकि, इस बार जीतनराम मांझी की पार्टी ने संतोष कुमार सुमन की जगह श्रवण भुइयां को उम्मीदवार बनाया था। राजेश राम विधानसभा में कांग्रेस के उपमुख्य सचेतक हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर भी सौंप दी है।

बिहार में कांग्रेस की नजर अपने पुराने परंपरागत वोट पर है। यहां से परंपरागत वोटर दलित समाज का है। कांग्रेस की नजर दलित के लगभग 18 फीसदी वोट को अपने पाले में करने की है। दलित परंपरागत रूप से फिलहाल सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। भाजपा और जेडीयू के पास भी कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। आरजेडी में तेजस्वी यादव को आगे करने के चलते दलित लीडरशिप उभर नहीं आई। ऐसे में कांग्रेस ने दलित मतों के लिए उस राजेश राम को आगे किया, जिनकी विरासत में राजनीति है। राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित समुदाय को सियासी संदेश देने का दांव कांग्रेस ने चला है।

56 साल के राजेश कुमार रविदास समुदाय से हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में दलित समुदाय पर अपनी पकड़ बेहतर करने के लिए उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस का निशाना रविदास जाति पर है, जो पासवान की तरह मजबूत दलित जाति है। कांग्रेस की इस जाति पर तगड़ी पकड़ रही है। बाबू जगजीवन राम से लेकर उनकी बेटी मीरा कुमारी और दिलकेश्वर राम जैसे कांग्रेस के मजबूत दलित चेहरा बिहार में हुआ करते थे और अब कांग्रेस राजेश राम को आगे करके दोबारा से उसे भुनाने की कवायद में है।

बिहार में करीब 18 फीसदी दलित वोटर हैं, जिनके लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इस तरह से दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। लंबे समय तक यह कांग्रेस का वोटबैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग-अलग पार्टियों में बिखर गया। 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में दलित वोटर आरजेडी के खेमे में पहले खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव दलितों को अपने साथ रखकर 15 साल तक बिहार की सत्ता में बने रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक दल गठन करने के बाद रामविलास पासवान ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। रामविलास की गिनती शुरू में एक दलित नेता के तौर पर होने लगी थी, लेकिन धीरे-धीरे वो सिर्फ दुसाधों के सबसे बड़े नेता बनकर रह गए। दुसाधों के वो पहले बड़े नेता थे और ये उनके लिए मददगार साबित हुआ, मंत्री बनने के साथ-साथ उनकी राजनीतिक हैसियत भी बड़ी होती गई और ये वोटबैंक मजबूत होता गया, लेकिन दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी जगह बिहार में नहीं बना सके। बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले इन जातियों को दलित और महादलित की श्रेणी में बांटकर रामविलास पासवान की सियासत को सिर्फ दुसाधों तक सीमित कर दिया। 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित मान लिया। इसके बाद भी पासवान समुदाय एलजेपी का वोटर बना रहा तो मुसहर जाति के नेता बनकर जीतनराम मांझी उभरे, जबकि रविदास समाज से बसपा ने अपना नाता जोड़ लिया।

● **विनोद बक्सरी**

कांग्रेस बिहार में तलाश रही जमीन

मंडल बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ है। दलित-ओबीसी वोटर आरजेडी-जेडीयू-एलजेपी के साथ चला गया तो सवर्ण मतदाता भाजपा से जुड़ गया। इसके चलते कांग्रेस बिहार की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई। कांग्रेस अब दोबारा से दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने दोबारा से दलित वोटों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए पहले उन्होंने दलित समाज के कई अहम चेहरे को अपने मिशन के लिए जोड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बिहार से आते हैं और दलित समाज से भी हैं। वह राहुल के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दो कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। पटना में 18 जनवरी को संविधान की रक्षा कार्यक्रम में शिरकत किए थे।

बिखराव की राह पर पाकिस्तान

बीते दिनों पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों समेत कई लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़े कि फौज और राजनीतिक दलों को आनन-फानन में बैठकें बुलानी पड़ीं। पाकिस्तान के हालिया घटनाक्रम ने कई अनकहे और कटु सत्य उजागर किए हैं। पहला, यह कि पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं, अपितु औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए बनाई गई एक कृत्रिम इकाई है। दूसरा, विश्व के जिस मानचित्र पर पाकिस्तान है, वहां के अधिकांश लोग इस्लाम के नाम पर न तो देश का विभाजन चाहते थे और न ही पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन करते थे। कई आज भी उसके विरोधी हैं। तीसरा, इस्लाम के नाम पर वैश्विक मुस्लिम सहयोग-एकता को बल देता उम्माह केवल किताबी बात है। इसका व्यावहारिकता से कोई लेना-देना नहीं। सुर्खियों में छाए बलूचिस्तान की बात करें उसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। सातवीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं के भारत पर हमले के बाद यहां इस्लाम का प्रभाव बढ़ा।

हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता मंदिर आज भी यहां विद्यमान है। ब्रिटिश हुकूमत के समय बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। 1876 में दोनों के बीच संधि हुई और वह सशर्त ब्रिटिश अधीनस्थ राज्य बन गया। 1947 में विभाजन के बाद कलात ने स्वतंत्र रहने का अधिकार चुना, लेकिन मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के निर्देश पर पाकिस्तानी सेना ने इसे बलपूर्वक हड़प लिया। तब से यह बलूच राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय के संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। पाकिस्तान में अलगाववाद केवल बलूचिस्तान तक सीमित न होकर सिंध और पश्तून क्षेत्र तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान के अतिरिक्त सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी विभाजन पूर्व इस्लाम के नाम पर अलग देश का विरोध था। सिंध इत्तेहाद पार्टी के शीर्ष नेता अल्लाबख्श मुहम्मद उमर सूमरो अविभाजित भारत में सिंध के दो बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मजहब के आधार पर अलग देश बनाने की अवधारणा को इस्लाम विरोधी बताया था। 1943 में अल्लाबख्श की हत्या कर दी गई, जिसमें मुस्लिम लीग के हाथ होने का संदेह जताया गया। 1945 तक अविभाजित पंजाब में भी पाकिस्तान के लिए कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में पंजाब के लोगों ने घोर मजहबी मुस्लिम लीग के बजाय सेक्युलर यूनियनिस्ट पार्टी को चुना।

इस दल ने सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में अकाली दल और कांग्रेस के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई। सिकंदर ने 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनके निधन के बाद रसूखदार मलिक खिजर हयात तिवाना ने 1942 से पंजाब सरकार की बागडोर संभाली। जिन्ना ने तिवाना पर दबाव बनाया लेकिन तिवाना झुके नहीं और पंजाब में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी। इससे खिन्न जिन्ना ने पंजाब में मजहबी उन्माद भड़काया। यूनियनिस्ट पार्टी बिखर गई और 1946 के चुनाव में पंजाब मुस्लिम लीग की झोली में चला गया। राजनीति से संन्यास लेकर जब तिवाना अक्टूबर 1949 में नवगठित पाकिस्तान के पंजाब पहुंचे, तब वहां की इस्लामी सरकार ने खुन्नस निकालते हुए उनकी अपार संपत्ति जब्त कर ली। मजहबी उत्पीड़न से बचने के लिए वह अमेरिका जाकर बस गए और 1975 में वहीं अंतिम सांस ली। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के लिए समर्थन नहीं था। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को व्यापक समर्थन नहीं मिला था। सीमांत गांधी कहे जाने वाले सरदार अब्दुल गफ्फार खां की कर्मभूमि ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। गफ्फार ने पश्तूनों की स्वायत्तता हेतु संघर्ष किया, जिसके कारण उनका अधिकतर समय जेल या फिर निर्वासन में बिता। इसी तरह जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला पहचान को पाकिस्तानी सत्ता-अधिष्ठान बार-बार कुचलता रहा, तब शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में उठी विद्रोह की आग ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया। अब यही स्थिति बलूचिस्तान में दिख रही है। इस बीच यह पहली बार नहीं है, जब उम्माह पर प्रश्नचिह्न लगा हो। यदि उम्माह वाकई व्यावहारिक है, तो सऊदी-ईरान, तुर्की-सीरिया और पाकिस्तान-अफगानिस्तान में शत्रुभाव का कारण क्या है? अहमदिया मुस्लिमों की पाकिस्तान निर्माण में बहुआयामी भूमिका थी। 1940 में पाकिस्तान के मजहबी विचार को अहमदिया मुस्लिम मुहम्मद जफरुल्लाह ने ही लेखबद्ध किया था। वह पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ पैरवी भी करते थे। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब अहमदिया मुस्लिमों के खलीफा मिर्जा बशीर-उद-दीन महमूद अहमद ने भारतीय सेना के खिलाफ फुरकान फोर्स जैसा सैन्यबल बनाया। सोचिए, इस्लाम के नाम पर सपनों के जिस देश के लिए अहमदिया मुसलमान लड़े, उसी पाकिस्तान में उन्हें मजहबी कारणों से 1974 में गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया गया। तब से वे भी अन्य काफिरों की भांति मजहबी प्रताड़ना के शिकार हैं।

● ऋतेन्द्र माथुर

अपनी मौलिक पहचान खो रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसी विषाक्त वैचारिक परियोजना है, जिसकी नींव केवल भारत-हिंदू विरोधी घृणा पर केंद्रित है। 12 मार्च को ही पाकिस्तानी पंजाब के शिक्षा विभाग ने अनैतिकता-अश्लीलता के नाम पर स्कूल-कालेजों में हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर पश्चिमी नाच-गानों पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? यह पाकिस्तान की पहली विडंबना नहीं है। पाकिस्तान अपनी मौलिक पहचान को भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से काटकर खाड़ी देशों की अरब संस्कृति में समाहित करने का असफल प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के पंजाबी भाषी और उर्दू-अंग्रेजी राजभाषा होने के बाद भी विदेशी फारसी लिपि में कौमी तराना (राष्ट्रगान) होना इसका ही प्रमाण है। इन्हीं विरोधाभासों के कारण पाकिस्तान गहरे राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक संकट में है, जो उसे लंबे समय तक एक इकाई के रूप में एकजुट नहीं रहने देगा।

ट्रंप टैरिफ का खौफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम कई देशों पर कहर बनकर टूटने वाला है। ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है। इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंका है। ट्रंप का यह नया टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से अमेरिका को तकरीबन 100 अरब डॉलर का फायदा होगा। ट्रंप इस फैसले से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने का दावा कर रहे हैं लेकिन एक सच ये भी है कि इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। लेकिन ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी।

ट्रंप का यह 25 फीसदी टैरिफ इम्पोर्टेड कार और ऑटो पार्ट्स पर लगेगा। ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अमेरिकी ऑटो कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन दूसरी तरफ इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी है क्योंकि टैरिफ का बोझ आखिर में ग्राहकों पर पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत और कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने इसी महीने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत जैसे कई देश बहुत ज्यादा टैरिफ लेते हैं, अब अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। माना जा रहा है कि 2 अप्रैल से एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। बीते एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजार बढ़त की ओर था लेकिन जैसे-जैसे 2 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है। भारतीय शेयर बाजार कंफ्यूज है। ट्रंप के टैरिफ बम का घरेलू बाजार पर क्या असर होगा? इसे लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। भारत ही नहीं अमेरिकी और यूरोपीय शेयर बाजारों में भी कुछ दिनों से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गुड और बैड दोनों तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे।

अमेरिका का फोकस शराब, ऑटोमोबाइल, कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क घटवाने पर है। अभी यह शराब पर 150 फीसदी, कारों पर 100 से 165 फीसदी और खेती उत्पादों पर 120 फीसदी है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसकी धातुओं, रसायन, आभूषणों, फार्मा और ऑटोमोबाइल पर अमेरिका भारी टैक्स लगाएगा। इससे भारत को सालाना 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दो अप्रैल से भारत सहित दुनियाभर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। भारत अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का बड़ा सप्लायर है। 2022 में अमेरिका में 40 फीसदी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं भारतीय कंपनियों से आईं, जिससे अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई। लेकिन टैरिफ बढ़ने से भारतीय दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। छोटी भारतीय दवा कंपनियां, जो कम मार्जिन पर काम करती हैं, टैरिफ का बोझ नहीं झेल पाएंगी। कुछ को अमेरिकी बाजार से बाहर होना पड़ सकता है, जिससे भारत का निर्यात घटेगा।

अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ने से वहां के मरीजों पर मेडिकल बिल का बोझ बढ़ेगा, जिससे भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। ट्रंप की नीति से भारत के कई सेक्टर प्रभावित होंगे, जिसमें रसायन, धातु उत्पाद और आभूषण शामिल हैं। सिटी रिसर्च के अनुसार, भारत को सालाना 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के कृषि क्षेत्र को टैरिफ युद्ध से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इसका भारतीय किसानों पर बुरा असर पड़ता है। ये भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि कृषि निर्यात बड़ा सेक्टर है।

अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अपने कार्यकाल के पहले महीने में ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नए मानक गढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक हाथ ले तो दूसरे हाथ दे का नुस्खा है। एक सुनहरे अतीत की ओर लौटने का ख्वाब है और सीधे सपाट लहजे में बात करना इसका ऊपरी स्वरूप है। लेन-देन के मामले में टैरिफ ही ट्रंप का हथियार हैं। वो जिस सुनहरे दौर की ओर लौटने की बात करते हैं, वो ठीक वैसा ही है, जिसकी बात शी जिनपिंग चीन में और व्लादिमीर पुतिन रूस में पहले से कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ट्रंप न केवल अपने घरेलू समर्थकों से दो टूक बातें कर रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संवाद में भी उनका यही लहजा है।

हकीकत तो ये है कि ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का इस्तेमाल करके बाकी दुनिया पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो सब अमेरिका के हितों की पूर्ति करें। अगर हम ये कहें कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो गलत नहीं होगा। हां, जो बात पहले अमेरिका दबे ढके लहजे में करता था, वही अब ट्रंप खुलकर कह रहे हैं। अमेरिका की व्यापक रणनीति हमेशा ही आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक, सैन्य और सूचना की ताकत का इस्तेमाल करके अपने घरेलू हित साधने और दुनिया का एजेंडा तय करने की रही है।

● सुश्री नित्या

रणनीति पुरानी, बस अब शोर ज्यादा है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, जो उनके पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति करते आए थे, ताकत का प्रदर्शन। बस एक फर्क है- सर्वसंपन्न लोगों का संरक्षण करने या फिर मुर्दा लोगों को सामाजिक सुरक्षा से मदद करने के बजाय वो अमेरिका में रोजगार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप अपनी रणनीति को खुलकर बोल रहे हैं। पहले जैसा नहीं जब अमेरिका का डीप स्टेट पर्दे के पीछे यही सब करता था। आपको पसंद आए या नहीं, पर अब सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है। पहले वो खुले तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करते हैं और उसके बाद उन्हीं मकसदों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। रूस या चीन के साथ टकराव की बड़ी रणनीति में फर्क ट्रंप के उसको लागू करने के तौर तरीके में है। वो दुनिया में अपने कदमों के लिए पहले स्वदेश में समर्थन जुटाते हैं। अमेरिका हो या फिर रूस और चीन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अंतरराष्ट्रीय नियमों को नहीं तोड़ा है। चीन, व्यापार के नियमों और बंद बाजारों के नियमों का उल्लंघन पहले भी करता आया था और आज भी कर रहा है; दूसरे देशों के चुनाव में रूस की दखलंदाजी और अमेरिका द्वारा दुनिया के तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन के अभियान, सब इसकी मिसालें हैं।

सीमा-रेखा न लांघें

एक-दूसरे के लिए प्रेम दर्शाना गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में कई लोग अश्लीलता की हद पार कर देते हैं, जिससे आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे में लड़कियों को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतों के वीडियोज सेकंड्स में वायरल हो सकते हैं या वीडियोज बनाकर उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। माना कि बॉडी आपकी है और उस पर हक भी आप का है और प्रेम करना भी गुनाह नहीं है, मगर पब्लिक प्लेस पर इस तरह प्रेम का इजहार एक तरह से पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह खुलेआम प्रेमी जोड़े का प्रेम प्रदर्शन सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है।

युवा प्रेमी जोड़े अधिक रोमांटिक होते हैं, उन्हें जब एकांत स्थान नहीं मिल पाता तो वे पब्लिक प्लेस में भी अपने पार्टनर के प्रति इंटिमेसी व्यक्त करने से नहीं चूकते। अक्सर पब्लिक प्लेस या किसी गार्डन में प्रेमी जोड़े एक-दूसरे को चूमते, गले लगाते और हाथों में हाथ डालकर चलते हुए नजर आते हैं। इन जोड़ों का प्रेमालाप आसपास के लोगों को कई तरह से प्रभावित करता है। दरअसल पब्लिक प्लेस पर बच्चे, फैमिली, बुजुर्ग सभी तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक-दूसरे के लिए प्रेम दर्शाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु हर जगह प्रेम दर्शाने का अलग-अलग तरीका भी होता है। कई देशों में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को लीगल माना जाता है, परंतु बात यदि भारत की करें तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन तब तक दंडनीय नहीं है जब तक कि यह अश्लीलता में न बदल जाए और दूसरों की भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस न पहुंचे। प्रेम प्रदर्शन की सीमा-रेखा अपने आसपास के माहौल को देखते हुए आपको खुद तय करनी होगी। पब्लिक प्लेस पर अपने पार्टनर के प्रति प्रेमस्नेह जाहिर करने के और भी तरीके हैं जिन्हें शारीरिक गतिविधियों से परे भावनात्मक प्रेम कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मौजूद व्यक्ति कई बार इस तरह की प्रतिक्रिया को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।

जब पब्लिक प्लेस पर स्नेह जताने का तरीका जिस्मानी हो जाता है, जैसे कि एक-दूसरे को लंबे समय तक चूमते रहना, अमान्य रूप से इधर-उधर टच करना, लंबे समय तक एक-दूसरे को बांहों में लिए रहना, तो आसपास मौजूद लोग असहज हो जाते हैं। ये गतिविधियां आसपास मौजूद लोगों की स्वेच्छा के बगैर की जाएं तो इसके अनुरूप आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई और फाइन चार्ज किया जा सकता है। जवान लड़कियां लड़कों की बातों में आकर प्रेम और वासना के बीच के अंतर को समझ नहीं पातीं। इसी वजह से वे अपना सबकुछ न्यौछावर कर देती हैं। पार्टनर के साथ प्रेम करने या सेक्स करने की वीडियो बनाने की बेवकूफी कभी न करें, क्योंकि ब्रेकअप होने पर लड़के आपको ब्लैकमेल करने से गुरेज नहीं करते। छोटे शहरों से लेकर महानगरों में आजकल एक नई तरह का ट्रैंड चल रहा है। बाइक पर पति या प्रेमी के साथ सवार पत्नी या प्रेमिका अपना हाथ पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर रख बेशर्मी के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमती है। पब्लिक प्लेस पर यह करके आखिर वे किस तरह का प्रेम कर रहे हैं। खासतौर पर लड़कियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमालाप के दौरान किसी ऐसी जगह का चयन करें जहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। मोबाइल में वीडियो बनाने की गलती कभी न करें क्योंकि यह एक तरह का सुबूत होता है। युवा जोड़े जब आपस में मिलते हैं तो जोश में आकर मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं और फिर समाज में उनकी बदनामी होती है। युवक-युवतियां अक्सर फिल्मों या टेलीविजन सीरियल्स में दिखाए जाने वाले दृश्यों से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। फिल्मों में नायिका नायक द्वारा प्रेम का सार्वजनिक रूप से इजहार करने पर खुश होती है, वहीं असल जिंदगी में इसका असर ठीक विपरीत होता है। ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन के बाद लोगों को प्रेम के इजहार के लिए जगह चुनने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

वेबसाइट एमएसएन द्वारा 2,000 लोगों के मध्य किए गए एक सर्वेक्षण में 28 प्रतिशत लोगों ने माना कि सार्वजनिक स्थानों पर और दूसरे लोगों की मौजूदगी में प्रेम का इजहार उन्हें असहज करता है। करीब एक-चौथाई ब्रिटिश युवतियां सार्वजनिक स्थानों पर गले लगने और यहां तक कि हाथ थामने में झिझक महसूस करती हैं जबकि हर 10 में से एक महिला ऐसे पुरुषों का साथ पसंद नहीं करती है जो सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रेम का इजहार करने से बाज नहीं आते। अपनी बॉडी किसी दूसरे को सौंपने से पहले दस बार सोचें कि ऐसा करने से कोई नुकसान तो नहीं है। कई दफा इस तरह के वीडियो की वजह से पुलिस भी प्रेमी जोड़े को परेशान करती है। कानूनी कार्यवाही के नाम पर पुलिस पैसा ऐंठती है या फिर यौन शोषण करती है। कमोबेश यही हालत सोसाइटी में रहने वाले लोगों की भी है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

लचीला कानून

भारत में अश्लीलता विरोधी कानून बना हुआ है, जिसका उद्देश्य अश्लील सामग्री के वितरण को रोकना या प्रतिबंधित करना है। आईपीसी की धारा-292 इसका विवरण करती है कि किन मानकों को अश्लील माना जाएगा या नहीं, जिसके आधार पर अपराधी को सजा भी हो सकती है। अश्लीलता शब्द उन शब्दों में से एक है जिसका अर्थ हमारे भारतीय कानून में स्पष्ट नहीं है। लचीले कानून की वजह से अश्लील सामग्री है या नहीं, यह पूरी तरह से वकीलों और न्यायाधीशों पर निर्भर करता है और वे अश्लील शब्द की व्याख्या कैसे करते हैं। अश्लीलता की परिभाषा समय-समय पर बदलती रही है। हम जानते हैं कि कानूनों को समय-समय पर बदलना पड़ता है लेकिन अश्लीलता को सही तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि फिल्मों, वेब शो, कला, छवियों या चित्रों, साहित्य में अश्लीलता को अभी तक हमारे देश में परिभाषित नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा-294 को भारतीय न्याय संहिता में धारा-296 में बदला गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई दूसरों को क्षोभ पहुंचाने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करेगा या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाएगा, सुनाएगा या बोलेगा, उसे 3 महीने की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

ज्ञान हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का एक तरीका

भगवद गीता में श्रीकृष्ण ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने ज्ञान को आत्मा की सच्चाई और संसार के वास्तविकता को समझने का माध्यम बताया। गीता में ज्ञान न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का उपाय है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का एक तरीका भी है। श्रीकृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर एकत्व को महसूस करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान वह है जो आत्मा के साथ जुड़कर, संसार की नश्वरता को समझने में मदद करता है। सच्चा ज्ञान वही है, जो आपको अहंकार और माया के बंधन से मुक्ति दिलाए। ज्ञान से ही आत्मा की शुद्धता होती है, और इस शुद्धता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान केवल एक पुस्तक या विद्या का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई को जानने का उपाय है। ज्ञान वह है, जो आत्मा को इसके वास्तविक रूप को जानने में सक्षम बनाता है और संसार के भ्रम से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान में निष्ठित होता है, वह जीवन के हर संघर्ष को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करता है। कर्म करते समय अपने कार्यों का फल न सोचकर, केवल धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलो। सच्चा ज्ञान वही है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करे।

भगवद गीता में कहा गया है कि....

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

बच्चों की आदत होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में यह श्लोक उनके बहुत काम आ सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत करो।

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्संजायते कामः
कामात्क्रोधोऽभिजायते॥

अर्थ- विषय-वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे लगाव हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में बाधा आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी चीज के लगाव से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। बच्चे किसी चीज को देखते ही उसकी जिद करने लगते हैं। और न मिलने पर जल्द ही गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह श्लोक उत्तम है।

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

अर्थ- क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। कई बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में यह श्लोक उन्हें गुस्सा करने से होने नुकसानों से अवगत कराता है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

अर्थ- श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण यानी जो-जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या कहें कि वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव-समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यह श्लोक अच्छे आचरण के फायदे बताता है। जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है।

श्रद्धावान्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

अर्थ- श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम-शांति को प्राप्त होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह श्लोक बहुत ही उत्तम है। यह उन्हें एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है।

भगवद गीता में श्रीकृष्ण ने बताया है कि व्यक्ति को आत्ममंथन अवश्य करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह जीवन में कर रही गलतियों का आंकलन कर सकता है और अपने निर्णय को दृढ़ता से व सोच-समझकर ले सकता है। गीता में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर भी काबू रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेश में आकर व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और अधिकांश समय गलत निर्णय लेता है। जिस कारण से उसे भविष्य में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रीकृष्ण भगवद गीता में बताया है कि मनुष्य को अपने मन एवं चित्त पर संयम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मन चंचल प्रवृत्ति का होता है और जिसके कारण गलत निर्णय लिए जाने का भय निरंतर बना रहता है। वहीं जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवनकाल में सदैव सद्कर्म ही करते रहना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और वह सभी दुखों से दूर रहता है।

● **ओम**

रंगीन बादल

एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया को बादलों से बहुत प्यार था। वह अक्सर छत पर बैठकर घंटों बादलों को देखती रहती थी। एक दिन, रिया ने एक ऐसा बादल देखा जो बहुत ही रंगीन था। वह इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था।

रिया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह कोई जादुई बादल है। वह बादल के करीब जाना चाहती थी। रिया ने बादल की ओर दौड़ लगाई और उछलकर हवा में उड़ गई। वह बादल पर बैठ गई और बादल के साथ आसमान में घूमने लगी।

बादल रिया को बहुत दूर-दूर ले गया। उसने रिया को समुद्र, जंगल और पहाड़ दिखाए। रिया ने बहुत सारे नए-नए जीव-जंतु और पौधे देखे। रिया बहुत मजे कर रही थी। कुछ देर बाद, रिया को घर वापस जाना याद आया। उसने बादल से कहा, मुझे घर वापस ले चलो। बादल ने रिया को उसके घर के ऊपर ले गया और धीरे से उसे छत पर छोड़ दिया।

जब रिया उठी तो वह अपने कमरे में थी। उसने सोचा कि यह सब एक सपना था। लेकिन उसे बादल के रंग अभी भी याद थे।

– अज्ञात

बोलने वाले जानवर

एक बार की बात है, एक जंगल में सभी जानवर बातचीत कर सकते थे। शेर बाघ से पूछता था, आज का शिकार कैसा रहा? तो बाघ जवाब देता, बहुत अच्छा, आज मैंने एक हिरण का शिकार किया है।

एक दिन, जंगल में एक नया जानवर आया। वह एक छोटा सा चूहा था। चूहे ने बाकी जानवरों को देखा जो आपस में बात कर रहे थे। वह बहुत हैरान हुआ। चूहे ने हिम्मत करके शेर से पूछा, तुम लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो? शेर ने चूहे से कहा, हम सभी जानवर आपस में बातें करते हैं। यह हमारी आदत है। चूहा बहुत खुश हुआ। अब उसे भी बाकी जानवरों के साथ बात करने में मजा आने लगा।

– अज्ञात

हैवानों इंसान बनो

चार दिनों की मिली जिंदगी,
हैवानों इंसान बनो।
अहं भरी दीवार गिराकर,
प्रेम भरी दीवार चुनो।

मुट्ठी बांधे जग में आए,
हाथ पसारे जाओगे।
धन दौलत यह माल खजाना,
साथ नहीं ले पाओगे।
लोभ मोह तो मकड़जाल है,
निकलो बाहर बात सुनो।
चार दिनों की मिली जिंदगी,
हैवानों इंसान बनो।
मनुज स्वार्थ में अंधा होकर,
कोमल हृदय दुखता है।
महल दुमहले मोटर गाड़ी
के मद में इतराता है।
माया नगरी में माया की
क्षण भंगुर है जात सुनो।
चार दिनों की मिली जिंदगी,
हैवानों इंसान बनो।
धर्म जाति के इन झगड़ों में
उलझ-उलझ दम तोड़ रहे।
आतंकी बन चीर कलेजा
गहरी खाई खोद रहे।
दगाबाज ही इक दिन जग में
खुद से खाता मात सुनो।
चार दिनों की मिली जिंदगी,
हैवानों इंसान बनो।
रावण, कंस, हिरण्याकश्यप
कौरव यही बताते हैं।
जो अधर्म की राह चलें है
वो समूल मिट जाते है।
वेद, पुराण, उपनिषद गुन लो
नहीं मिलेगी मात सुनो।
चार दिनों की मिली जिंदगी,
हैवानों इंसान बनो।

– मंजूषा श्रीवास्तव

कबड्डी में भारत का डबल धमाल

भारतीय खेल जगत में इन दिनों एक ओर जहां आईपीएल की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश की मिट्टी से जन्मा पारम्परिक खेल कबड्डी विश्वकप में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब बरकरार रख डबल धमाल कर दिखाया है। 17 से 23 मार्च तक इंग्लैंड की धरती पर खेला गया कबड्डी विश्वकप चार अलग-अलग स्थानों पर खेला गया, जिसमें भारत समेत कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट को दो ग्रुप में बांटा गया और भारत की पुरुष टीम को ग्रुप-बी में रखा गया, जहां उसका मुकाबला इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और हॉन्गकॉन्ग जैसी टीमों से हुआ। वहीं ग्रुप-ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी और यूएसए शामिल थी।

कबड्डी विश्वकप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने अभियान की शुरुआत 17 मार्च को इटली के खिलाफ मुकाबले से की। लीग मैचों के बाद भारत और वेल्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया जबकि दूसरा सेमीफाइनल ईरान और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। टीम इंडिया को अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भारतीय टीम ने बेहद आसानी के साथ वेल्स को 93-37 के अंतर से हरा दिया था। जबकि ईरान ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड को बेहद आसानी के साथ 84-36 से हरा दिया। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 44-41 के अंतर से जबरदस्त जीत हासिल करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया।

इस विश्वकप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें दोनों ही ट्रॉफी को जीतने में कामयाब रही। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी फाइनल मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को 57-34 के अंतर से मात दी।

कबड्डी विश्वकप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का अजेय अभियान देखने को मिला जिसमें उन्होंने ग्रुप मुकाबले में इटली, हॉन्गकॉन्ग और वेल्स को जहां मात देने में कामयाबी हासिल की तो वहीं स्कॉटलैंड के साथ ड्रॉ मुकाबला खेलते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का किया था। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना हंगरी की टीम से हुआ जिसको उन्होंने 69-24 के अंतर से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को पक्का किया। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने वेल्स की टीम को 93-37 के अंतर से मात देने के साथ खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई जहां उन्होंने अब मेजबान इंग्लैंड को मात देने के साथ ट्रॉफी को अपने नाम किया है।

● आशीष नेमा

महिला टीम का भी दिखा दबदबा

भारतीय महिला टीम का भी इस विश्वकप के हर मैच में दबदबा देखने को मिला जिसमें उन्होंने ग्रुप स्टेज में जहां वेल्स की टीम को 89-18 के अंतर से हराया तो इसके बाद पोलैंड की टीम को 104-15 के बड़े अंतर से मात देने में कामयाब रही। वहीं सेमीफाइनल में भारतीय महिला कबड्डी टीम का सामना हॉन्गकॉन्ग चाइना के साथ था, जिसको उन्होंने 53-15 के अंतर से जीतते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। खिताबी मैच में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इंग्लैंड को एकतरफा 57-34 के अंतर से मात देते हुए ट्रॉफी जीती। गौरतलब है कि कबड्डी विश्वकप 2025 का यह दूसरा सीजन था जिसका आयोजन विश्व कबड्डी द्वारा किया गया। इससे पहले इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित हुआ था जिसमें भारत का दबदबा साफ नजर आया था। उस समय भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इराक को 57-27 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया था, जबकि महिला टीम ने ताइवान को 47-29 से मात देकर खिताबी जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार दोनों टीमों पर खिताब बरकरार रखने की चुनौती थी जिसका उन्होंने बखूबी बचाव कर खिताब अपने नाम किया। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन भी एक अलग टूर्नामेंट का आयोजन करता है जिसे कबड्डी विश्वकप कहा जाता है। इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर एशियन वुमेंस कबड्डी चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम कर सभी खेल प्रेमियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया था।

साल 2007 बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार के लिए काफी लकी साबित हुआ था। उनकी 4 फिल्में साल 2007 की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल थीं। वह अकेले ऐसे अभिनेता थे जिनकी 4 फिल्में उस लिस्ट में शामिल थीं। इस मामले में उन्होंने अकेले ही सभी अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए आपको अक्षय की उन 4 बेहतरीन फिल्मों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

जब बॉक्स ऑफिस पर गूंजी थी अक्षय की दहाड़

2007 में बजी थी इन 4 फिल्मों की डंका, अकेले सब पर पड़े थे भारी...

वेलकमः यह एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसे अनीस बज्मी ने सह-लिखा और निर्देशित किया था। यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, यह साल 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसमें फिरोज खान, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, परेश रावल और मल्लिका शेरावत प्रमुख भूमिकाओं में थे। वहीं, सुनील शेट्टी और मलाइका अरोड़ा विशेष भूमिकाओं में नजर आए थे।

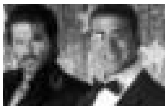

हे बेबीः यह भी एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया था और निर्देशन साजिद खान ने किया था। इसमें अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख, विद्या बालन, जुआना सांघवी और बोमन ईरानी थे। इस फिल्म की मुख्य कहानी मलयालम फिल्म थूवलस्पर्शम (1990) पर आधारित थी, जो अमेरिकी फिल्म थ्री मेन एंड ए बेबी (1987) का रूपांतरण थी। यह साल 2007 की छठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

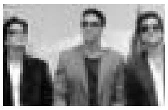

भूल भुलैयाः यह एक साइको कॉमेडी हॉरर फिल्म थी, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और पटकथा नीरज वोरा ने लिखी थी। इसका निर्माण टी सीरीज ने किया था। यह मधु मुत्तम द्वारा लिखित और फाजिल द्वारा निर्देशित 1993 की मलयालम-भाषा की फिल्म मणिचित्राथजु का रीमेक थी। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा और अमीषा पटेल के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी और विक्रम गोखले थे। यह फिल्म साल 2007 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

नमस्ते लंदनः यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्देशन और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नीना वाडिया, जावेद शेख, उपेन पटेल और क्लाइव स्टैंडन मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म मूल रूप से अक्षय कुमार के दोस्त की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित थी। रितेश देशमुख फिल्म में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दिए थे। यह साल 2007 की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

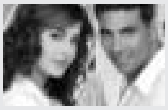

जब जया बच्चन की बात सुन सन्न रह गई थीं रेखा, बिग बी से तुरंत बना ली दूरी

एक जमाने में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के खूब चर्चे रहे हैं। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उस बीच उनके रिलेशनशिप की खबरें भी खूब आती थीं। दिलचस्प बात है कि उस समय बिग बी की जया से शादी हो चुकी थी। लेकिन साथ में फिल्मों की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा एक-दूसरे से प्यार कर बैठे। उस बीच जया बच्चन ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा को अलग होना पड़ा। हाल ही में राइटर और फिल्म हिस्टोरियन हनीफ जावेरी ने बताया कि जया बच्चन ने कैसे अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता खत्म कर दिया था।

हनीफ जावेरी ने बताया कि जया बच्चन ने किस तरह अमिताभ और रेखा के बीच रिश्ता खत्म करवा दिया था। उनके अनुसार, जया बच्चन ने रेखा को अपने घर में लंच पर इनवाइट किया था। उस वक्त अमिताभ घर पर नहीं थे। उन्होंने रेखा को अच्छे से खाना खिलाया और खूब सारी बातें कीं। जब रेखा के जाने का टाइम आया, तो जया बच्चन ने उनसे कहा देखो अमिताभ मेरे हैं, मेरे थे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। जया की इन बातों का रेखा पर बहुत बड़ा असर पड़ा था और फिर उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया था।

सलमान-सोहेल के साथ आए फिल्मों में नजर, फिर भी काम को हुए मोहताज...

बॉलीवुड एक्टर कादर खान ने गोविंदा के साथ कॉमिक रोल से दर्शकों के दिलों में पहचान बनाई। कादर खान के तीन बेटे हैं और उनके दो बेटों- सरफराज खान और शाहनवाज खान ने एक्टिंग में किस्मत आजमाई। दिग्गज एक्टर के बेटे सरफराज ने सलमान खान और सोहेल खान के साथ कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने साल 1993 में फिल्म शतरंग से एक्टिंग डेब्यू किया था। उसके बाद वो क्या यही प्यार है, मैंने दिल तुझको दिया जैसी फिल्मों में काम किया था। एक्टर सरफराज खान फिल्म मैंने दिल तुझको दिया में सोहेल खान के साथ नजर आए थे। दिलचस्प बात है कि इंडस्ट्री में बरसों संघर्ष करने के बाद अपना मुकाम हासिल करने वाले कादर खान ने अपने बेटों को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने की नसीहत दी थी। लेकिन सरफराज और शाहनवाज दोनों ने ही उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने पिता की सलाह को नजरअंदाज करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम तो रखा, लेकिन न ही उन्हें अच्छे रोल मिले और न ही अच्छी फिल्में। साल 2003 में सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित फिल्म तेरे नाम में कादर खान के बेटे सरफराज ने सलमान खान के जिगरी दोस्त का किरदार अदा किया था।

एक पौधे की व्यथा

कालो, भाई! चार दिन से कार की पिछली डिक्की में पड़ा हूं। मालिक भूल गए क्या? नर्सरी से मुझे ऐसे लेकर आए थे जैसे अनाथाश्रम से बच्चा गोद लिया हो। पचास मेरे भाई-बहनों में से मुझे चुना, मैं तो उसी समय घबरा गया था। मेरे वश में होता तो वहां से भाग खड़ा होता। मुझे मालूम है, पिछले साल भी तुम्हें वृक्षारोपण का भूत चढ़ा था। मेरे एक भाई को ले गए थे, उसके साथ तुमने क्या किया, यह मुझे पता है। जैसे ही तुम जैसे किसी पर्यावरण प्रेमी की गाड़ी नर्सरी के गेट पर ठहरती है, नर्सरी में एकदम सन्नाटा छा जाता है! तुम्हारे लिए यह पौधारोपण या वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, हमारे लिए तो बकरीद जैसा ही है। शहादत तो हमें ही देनी है न! तुम्हारी समाज सेवा की बलि वेदी पर हमारी ही बली चढ़नी है!

अच्छा-भला नर्सरी में फल-फूल रहा था, माली समय पर पानी दे रहा था, खाद दे रहा था, सूरज की तपिश मिल रही थी। वहां की गरीब कुटिया में भी स्वच्छंद अपना बचपन बिता रहा था। लेकिन तुम लोगों को न जाने क्या समाज सेवा की भूख चढ़ी है! अरे! समाज सेवा करनी है तो समाज की करो न! क्यों इस पर्यावरण सेवा और वृक्षारोपण के कीड़े ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है? चार दिन से कार की डिक्की में पड़ा हूं, दम घुट रहा है। अगर कार्यक्रम हरियाली तीज को ही रखना था, तो तब ही लेकर आते ना! कुछ दिन तो आराम से और जी लेता। अरे! फांसी पर चढ़ने वाले मुजरिम से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हलाल होने वाले बकरों को भी हलाल करने से पहले अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाता है, मुझे तो वह भी नसीब नहीं।

मुझे मालूम है, मेरे साथ क्या होने वाला है। सोच-सोचकर ही रूह कांप जाती है। यहां कोई है भी नहीं जिससे बात करूं, अपना दुख-दर्द साझा करूं। तुझे तो मेरा नाम भी मालूम नहीं! माली से डींगें हांक रहा था कि हम पौधे खरीदते नहीं, गोद लेते हैं। गोद लेते हैं तो क्या नाम भी नहीं पूछते? किसका पेड़ है? चार दिन से चार बार तो अपने बच्चों को मुझे दिखा चुका है, उनका बॉटनी का ज्ञान मुझसे ही बढ़वाएगा! कोई मेरी पत्ती तोड़कर देख रहा है, कोई डाली तोड़कर, कोई मेरे जाइलम-फ्लोएम की जांच कर रहा है। तुम्हारी नजर में तो सब पौधे एक जैसे हैं, तुम्हारी नजर में तो सब पौधे केवल पौधारोपण कार्यक्रम के काम आते हैं। जैसे मैं पौधा नहीं, आम आदमी हो गया हूं, जो सिर्फ वोट देने के काम आता है!

तुम्हें तो बस पौधारोपण से मतलब है, चाहे मैं आम का हूं या बबूल का, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है! तुम तो बबूल को भी आम बताकर रोपित कर दोगे। पौधारोपण के समय फोटो खींचोगे, उसमें मैं तो कहीं दिखूंगा ही नहीं। तुम्हारी संस्था के दस आदमी मुझे यहां-वहां से ऐसी बेरहमी से पकड़ेंगे, जैसे कि बकरे को हलाल करने से पहले पकड़ा जाता है। मेरी नाजुक सी डाली पर अपनी संस्था की भारी-भरकम प्लेट टांग दोगे। अरे! कम से कम मैं शहीद हो रहा हूं तो इतना हक तो बनता है कि मेरी भी फोटो अखबार में छपे! हेडलाइन में भी मेरा नाम सिर्फ आम आदमी की तरह संख्याओं में होगा- संस्था ने 51 पौधे लगाए। किसके लगाए? इससे न संस्था को मतलब होगा, न पाठकों को।

जहां मुझे लगाया जाएगा, वह जगह भी तुम्हारी निजी संपत्ति होगी। वहां तुम्हारे प्रतिष्ठान का बड़ा-सा होर्डिंग पहले से टंगा होगा। वही जगह होगी, जहां पिछली बार तुमने मेरे भाइयों को शहीद किया था! अरे! हिम्मत है तो यह हेडलाइन दो न- संस्था द्वारा आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में 10 पौधों को किया शहीद।

मैं जानता हूं, तुम्हारे पौधारोपण की हकीकत। तुम दिहाड़ी मजदूर बुला लोगे। वही गड्ढा खोदेगा, वही पानी देगा, वही मुझे रोपेगा। भूखा-प्यासा, अपनी चार पसीने की बूंदें भी मुझे अर्पित कर देगा। जब तक तुम संस्था के ऑफिस में वृक्षारोपण संगोष्ठी में पर्यावरण संरक्षण पर लंबा-चौड़ा भाषण दोगे, मंच, माला, माइक से सरोबार होकर 10-15 फोटो खिंचवाकर चाय-नाश्ते से पेट भरोगे, तब तक वह मजदूर बेचारा अपनी मजदूरी की राह देखता रहेगा। किसी पेड़ की छांव में सुस्ताता रहेगा, एक बीड़ी सुलगाएगा।

तुम पेड़ लगाते क्यों हो, जब तुम्हें न तो इसकी छांव की जरूरत है, न इसके फलों की? फिर तुम सब आओगे, मुझे चारों तरफ से घेरकर दो-चार फोटो खिंचवाओगे, फिर ऐसे गायब हो जाओगे जैसे नेताजी चुनाव के बाद! उसके बाद निरीह सा मैं, पानी और खाद के लिए तरसता रहूंगा। कहीं बरसात ने थोड़े दिन के लिए मेहरबानी कर दी और मुझे जीवित रखा, तो वह भी तुम्हें सहन नहीं होगा। तुम्हारा लगाया गया ट्री-गार्ड कोई गंजेड़ी उखाड़कर उसे कबाड़ी बाजार में बेचकर अपनी शाम का जुगाड़ कर लेगा! फिर आवारा, भूखी-प्यासी गायें, बकरियां और भेड़ें मुझ पर छोड़ दी जाएंगी। मेरे साथ सार्वजनिक बलात्कार होगा! धीरे-धीरे गरीब की झुग्गी-झोंपड़ी में पले बच्चे की तरह सूखकर कांटा बन जाऊंगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा।

मेरी शहादत किसी भी अखबार में नहीं छपेगी। लेकिन तुम एक बार फिर पर्यावरण प्रेमी कहलाओगे, दो-चार तमगे अपनी शर्ट पर लगवा लोगे। मैं जमीन में मिलकर तुम्हारे अगले साल के पौधारोपण कार्यक्रम के लिए फिर जमीन तैयार कर दूंगा! बस यही मेरी नियति है!

● **डॉ. मुकेश 'असीमित'**

mycem cement
HEIDELBERGCEMENT
mycem power
Trusted German Quality
Over 150 Years
Send 'Hi' 7236955555

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

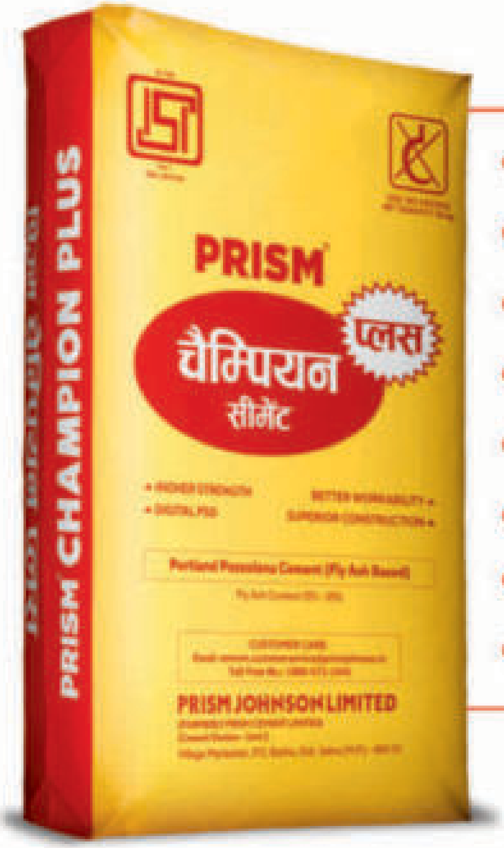

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
प्लस
चैम्पियन
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in